हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

18 दिस्मबर, 1980

खण्ड 3, अंक 4

अधिकृत विवरण

विशय सूची

18 दिस्मबर, 1980

पृश्ठ संख्या

भाोक प्रस्ताव	(4)1
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(4)4
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र न के लिखित उत्तर	(4) 28
वैयक्ति स्पश्टीकरणः– 1. सिचाई तथा बिजली उप मंत्री (श्री देवेन्द्र भार्मा) 2. डा0 मंगल सैन द्वारा	(4) 33
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग रोहतक तथा हिसार मे विधार्थियो मे बेचैनी संबधी	(4)35
ध्यानाकर्शण सूचनाए– 1. बिड़ला टी0आई0टी0 के वर्करो की छटनी संबधी 2. तहसील जगाधरी तथा यमुना नगर जिला अम्बाला आदि मे औलावृश्टि के कारण हुए नुकसान	 4 (37) 4 (37)

संबंधी	
वैयक्तिक स्पश्टीकरण चौधरी गंगा राम द्वारा	(4) 38
ध्यानाकर्शण सूचनाए पुनरारम्भ (iii) हरियाणा डेरी विकास विभाग के कर्मचारियों मे भारी असतोश संबधी (iv) हरियाणा के अकाल प्रभावित क्षेत्रो मे कर्ज माफ करने तथा बिजली व पानी की सप्लाई की वि ोश व्यवस्था करने संबधी (v) गन्ने की कीमत बढाने संबंधी	 (4) 39 (4) 39 (4) 40
वक्तव्य– कृशि मंत्री द्वारा उक्त ध्यानकर्शध सूचना संबधी	(4) 41
वाक आउट	(4) 48
वैयक्तिक स्पश्टीकरण मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल द्वारा	(4) 49
वक्तवय मुख्य मंत्री द्वारा रावी नदी पर थीन बांध के निर्माण	(4) 53

संबधी	
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(4) 59
दि पजाब एग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किटस (हरियाणा थर्ड अमैडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल 1980	(4) 64
बैठक का समय बढाना	(4) 76
दि पजाब एग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किटस (हरियाणा थर्ड अमैडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल 1980 (पुनरारम्भ)	(4) 76
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव हरियाणा राज्य मे प्राईवेट कालेजो की हालत आदि तथा राज्य सरकार की राश्टीयकरण नीति संबधी	(4) 88
बैठक का समय बढाना	(4) 97
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव (पुनरारम्भ)	(4) 98
आधे घंटे की चर्चा राज्य मे खाद की मात्रा प्राप्त होने संबधी	(4) 100

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 18 दिस्मबर, 1980

विधान सभा की बैठक, हरियणा विधान सभा हाल,विधान भवन, सैक्टर 1 चण्डीगढ मे प्रातः 9.30 बजे हुई । अध्यक्ष कर्नल राव राम सिंह ने अध्यक्षता की ।

भाोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः साहेबान, अब मुख्य मंत्री जी भाोक प्रस्ताव पढेगे।

मुख्य मंत्री चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय रत्न मंत्री डा0 राम सुभग सिंह के 16 दिस्म्बर, 1980 को हुए दुखद निधन पर हार्दिक भाोक प्रकट करता है।

डा0 राम सुभग सिंह का जन्म 7 जुलाई, 1917 को बिहार के भााहबाद जिले मे खजुरिया नामक स्थान पर हुआ ।उन्होने कां ाी विधापीठ से भाास्त्री और मौसोरी यूनिवर्सिटी अमेरिका से पी0एच0डी0 की डिग्री प्राप्त की । वह 1950 से 1952 तक अन्तरिम संसद के सदस्य रहे । वर्श 1952 मे वह पहली लोक सभा के लिये चुने गये और दिस्म्बर , 1970 तक इसके सदस्य रहे। वर्श 1952 मे वह पहली लोक सभा के लिये चुने गय और दिस्म्बर, 1970 तक इसके सदस्य रहे। वह काग्रेस कार्य समिति के

सदस्य थे और वर्श 1955–57,1958–59,1960 और 1962 के दौरान कांग्रेस संसदीय पार्टी के सचिव रहे। वह इसकी कार्यकारिणाी समिति के भी सदस्य थे । वह 1962–64 मे केन्द्रीय कृशि मंत्री और 1964–67 मे राज्य रेल मंत्री रहे और मार्च 1967, फरवरी से 1969 तक संसदीय मामलो एवम सचांर मन्त्रालयों के मंत्री रहे। वह फरवरी 1969 से नवम्बर 1969 तक केन्द्रीय रेलवे मंत्री रहे और नवम्बर 1969 मे लोकसभा मे विरोधी दल के नेता बने ।

उनका निधन से दे ा एक प्रमुख स्वतत्रता सेनानी श्री सन्तराम के 15 दिसम्बर,1980 को हुए । दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री संतराम ने अपनी आयु के लगभग 25 वर्श अग्रेजी भाासन के विरूद्ध संघर्श के कारण जेलो मे बिताये । सबसे पहले वह 1921 मे जेल गये । महात्मा गांधी द्धारा चलाये गये असहयोग आन्दोलन मे भाग लेने पर उन्हें 1926–35 तक जेल की यातानांए सहीन पड़ी। उन्होने''भारत छोडो आन्दोलन'' मे बढ चढ कर भाग लिया । वह पं0 जवाहर लाल नेहरू के घनिश्ठ साथी थे और उनके साथ जेल मे भी रहे । प्रजा मण्डल आन्दोलन मे भी उन्होने प्रमुख भाग लिया । उन्हे महान् सेवाओ के लिये 1972 मे ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया वह पंजाब परिशद के सदस्य भी रहे ।

उनके निधन से दे ा एक सुविख्यात स्वतन्त्रता सेनानी की सेवाओ से वचित हो गया है । यह सदन दिवंगत नेता के

भाोकाकूल परिवार के सदस्यो से अपनी हार्दिक सवेंदना प्रकट करता है ।

श्री मूल चन्द जैन सम्भालकाः अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि हाउस ने जिन दो महान नेताओ के बारे मे भाोक प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, मै उसके समर्थन मे खड़ा हुआ हूं । स्पीकर साहब, इन दोनो महानभावो से मेरा निजी सम्पर्क ही नही बल्कि गहरा संबंध रहा है ।जिस समय मै 1957 से 1962 तक पार्लियामैंट का मैम्बर था उस समय भी डा0 राम सुभग सिंह लोक सभा के मैम्बर थे । उम्र समय वे कांग्रेस पालियामैटरी पार्टी के जनरल सैक्रटी भी थे । अपनी पार्टी के प्रति उनमे जो प्यार था, भाायद ही मैने अपनी जिन्दगी मे देखा हो । उनका अच्छा व्यवहार सिर्फ काग्रेस पार्टी के मैम्बरो के प्रति ही नही था बल्कि विरोधी पार्टी के मैम्बरो के प्रति भी उनका गहरा प्यार था और उनके साथ बड़ा अच्छा व्यहार करते थे इस कारण वे कुछ दिनो मे ही लोक सभा के बहुत ही प्रिय नेता माने जाने लगे। स्पीकर साहब, इतना मुझे अच्छी तरह से याद है कि वे समय समय पर सरकार की गल्तियों को नुक्ताचीनी भी करते रहते थे । कांग्रेस पालियामैटरी पार्टी की जब निजी मीटिंग होती थी तो उस समय भी व सरकार के गलत कार्यो की आलोचना करते थे । ट्रेजरी वैचिज मे होते हुए भी वे कैबिनेट के आदमियों को, जो गलत बात होती थी, कहने से नही हिचकते थे । मै तो रूलिंग पार्टी के मैम्बरो से यह कहना चाहता हूं कि इनको उनके जीवन मे सबक

सीखना चाहिए । यह प्रस्ताव आज अचानक आ गया है । वे डिबेट मे बहुत चढ कर हिस्सा लेते थे । मै इस बात को उनकी डिबेट से दिखा सकता हूं कि कितने ही मौके पर उन्होने अपनी पार्टी काी नुक्ताचीनी की है वे बहुत की मीठी बाते करते थे और बडे ही रचनात्मक ढंग से सुझाव देते थे जैसा कि मैने उपर कहा है, रूलिंग पार्टी के मैम्बरो को उनके जीवन से सबक लेना चाहिए । स्पीकर साहब, से बहुत ही अच्छे आदमी थे ।

स्पकीर साहब, इसी प्रकार श्री सन्त राम जी का सारा जीवन बड़ा कुर्बानी का रहा है । वे अपने जीवन मे बहुत अधिक बीमार रहे है । उनके चले जाने हमने एक बहुत ही अच्छा स्वतन्त्रता सेनानी खो दिया है । वे स्वतन्त्रता आन्दोलन मे बहुत बढ चढ कर हिस्सा लेते थे । उन्होने कुछ ऐसे कार्य किए है जिन्हे भुलाया नही जा सकता । मै अपनी तरफ से और अपनी दल के साथियों की तरफ से इन दोनो महानभावों के प्रति गहरा संवेदना प्रकट करता हूं और आ ाा करता हूं कि उनके परिवार तक यह भाोक प्रस्ताव भेजा जायेगा ।

डा0 मंगल सैन रोहतकः अध्यक्ष महोदय, चलते सदन मे जो दो विभूतियां इस संसार से चली गई है उनके बारे मे आज की कार्य सूची मे सबसे पहले जिक्र किया गया है यह बहुत ही अच्छी बात है मै इन दोनो विभूतियों के प्रति अपनी श्रद्धाजली भेंट करता है । डा0 राम सुभग सिंह ए किसान परिवार के अन्दर बिहार मे जन्मे । बिहार के अन्दर उन्होने विधपीठ की ि ाक्षा लेने

के बाद अमेरिका से पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त की और फिर अस्थाई लोक सभा के सदस्य रहे । वे रेल विभाग मे और कृशि विभाग मे राज्य मंत्री के पद पर सु ाोभित हुए । जब सन् 1969 मे इस दे ा मे सतारूढ दल का विभाजन हुआ और द लमे ताना ााही पनपने लगी तो दल का विरोध करते हुए उन्होनें संगठन कांग्रेस मे रहना स्वीकार किया । लोकतांत्रिक संगठन मे रहते हुए लोकसभा मे विरोधी दल के नेता के पद पर आसीन रहे ं बाबू जी का भी सौभाग्य है कि उन्होने उनके साथ कार्य किय और स्वाधीनता संग्राम मे भाग लिया । हमारी तो मजबूरी यह रही कि हम इन इस संसार मे उनसे बाद मे ही आय। उनके साथ तो हमनें जेल यातनाएं सही नही, लेकिन स्वाधीनता के बाद जेल जरूर गए है । स्पीरक साहब, मैने उनके उस समय द र्ान किये जब वे भारतीय किसान यूनियन के प्रधान होने के नाते भी उनसे कई बार मझे मिलने का अवरस मिला है आज वे इस संसारे मे नही है, इस बात को हमे बडा खेद है । सरकार की तरफ से जो भाोक प्रस्ताव आया है उसका मै समर्थन करता हू।

स्पीकर साहब, इसी प्रकार से एक और स्वतन्त्रता सेनानी श्री संत राम जिनका सारा जीवन चारदीवारी मे बीता, उनके संबध मे भी भाोक प्रस्ताव आया है, उनके प्रति भी मै भावभीनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । वे जेल मे गुलामो से भी बदतर हालत मे रहे । न जाने उन्होने जेल के अन्दर कितनी यातनांए सही ं। इस बात को तो वही लोग समझ सकते है

जो उन राजनीतिक नेताओं के साथ जेलों मे गए हो तो वही लोग समझ सकते है जो उन राजनीतिक नेताओ के साथ जेलो मे गए हों । उनका सारा जीवन अग्रेजो के साथ सर्घर्श करते हुए बीता । उन्होने निरन्तर 25 वर्शो तक यानि एक भाताब्दी का चौथा हिस्सा अग्रेजो के साथ सर्घर्श करते हुए जेल से काटा । एक बार तो उन्होने बहुत ही लम्बी अवधि जेल के अन्दर काटी। वे 1926 से 1935 तक यानी 9 वर्शो तक जेल मे रहे । उन्हे इतनी लम्बी अवधि अग्रेजी भाासनकाल मे काटती पड़ी । उस समय राजनैतिक नेताओ के साथ अमानवीय व्यवहार होता था । वे भारत के पहले प्रधान मंत्री के निकटतक सहयोगी रहे । विधान परिशद के भी वे सदस्य रहे। मै इन दोनो महानुभावो के प्रति अपनी तरफ से और अपने साथियो की तरफ से श्रद्धाजलि अर्पित करता हूं और इस भाोक प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

कामरेड भांकर लाल (सिरसा): स्पीकर महोदय, दो महान दे ा भग्त जो अग्रेजी राज और अग्रेजी साम्राज्यवाद को हटाने मे और मिटाने मे बढ चढ कर हिस्सा लेने वाले रहे है, मै उन नेताओ के प्रति श्रद्धाजलि देने के लिये और भाोक प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस दे ा के अन्दर अग्रेजी राज्य राज के अन्दर जो लोग अग्रेजी राज के खिलाफ लड़े है, जिन्होने संघर्श किया है और जेल की यातनाएं सही है, उन लोगो को इस बात का ज्ञान है कि किस राज के खिलाफ संघर्श करना, बगावत करना, यह एक बहुत बडी दे ा भक्ति कही जाती है ।

उन्होने तो उस राज के खिलाफ बगावत की थी इस भारत दे । मे, विदे ाों मे आकर राज कर रहे थे । उस अग्रेजी साम्राज्यवाद को मिटाने के लिए इन दोनो नेताओ ने इस दे । के अन्दर बहुत कुछ किया है । मै ज्यादा कुछ न कहता हुआ अपने ह्रदय से उन महान नेताओ को श्रद्धाजलि अर्पित करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस भाोक प्रस्ताव की पास करे । अन्त मे मै अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से इन नेताओ को श्रद्धांजलि देता हूं । धन्यवाद ।

Mr, Speaker: Hon'ble Members, I fully associate myself with the deep feelings of sorrow at the sad demise of Dr. Ram Subhag Singh. Dr. Ram Subhag Singh. was not only a renowned parliamentarian as has been brought out by various members but he was a colourful and lovabler personality whom the country will find hard to replace.

Shri Sand Ram was a veteran freedom fighter and in him the country has lost a person whom it is hard to replace. It will be my sad duty to convey the condolences to the bereaved families.

Now I would request you to observe two minutes silence as a mark of respect to the memory of decedsed personalities.

(At this stage, the House stood in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of the deceased.)

तराकित प्र न एवम उतर

Mr. Speaker: Hon, Members, now we will take up questions. Charudhr Ram Lal Wadhwa.

Wheat, Paddy and Rice stord in Warehouses in the State.

***1807. Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Food & Supplies be pleased to state-

(a) the districtwise total quantity of wheat, paddy and rice stocked/stored by the haryana Govertnment in the Warehouse in the State during the years 1979-80 and 1980-81 (todate) together with the names and addresses of owners of such Warehouses and rent paid to them, separately; and

(b) the districtwise quantity of wheat, paddy and rice proposed to be purchased by the Haryana Govertnment and the number of wwarehouse areanged for the storge of these commodities as referred to in part (a) above during the current year together with the names and addresses of owners of such Warehouses and rent settled for payment to them, separately ?

Food and Supples Minister (Chaudhri Gajraj Bahadur Nagar): (a) Statement I giving the district wise quantity of wheat and rice stored by the Haryana Government in hired warehouse in the State during the years 1979-80 and 1980-81 placed on the Table of the House.

No Stock of paddy was purchased or stored by the Food and Supplies Department during thes years.

As regards addresses of the owners of the warehouses and the rent paid to them, it is considered that

the time and labour involved in colleting this information would not be commensurate with the result likely to be achieved.

(b) No further purchase of wheat is expected to be made during the current year.

No paddy was purchased by the State Govt. till 16-12-1980. Nor the State Govt. is likely to purchase any paddy during the current year,

Rice is procured by the State Govt. under the levy Scheme for Central Pool and the delivery of such rice is got made directly to the F.C.I from the Mills. As such the question of making storage arrangements for rice does not arise. Statement II showing the likely levy on rice districtwise is placed on the Table of the house.

STATEMENT 1

Districtwise quantity of wheat and rice stored by the Food and Supplice Department in Hired Warehouses during 1979-80 (maximum at any time)

(Figures in tones)

Sr. No.	Name of Circle	Year 1979-80		Year 1980-81	
		Wheat	Rice	Wheat	Rice
1.	Ambala	15155	236	2781	--
2.	Bhiwani	----	26	---	--
3.	Faridabad	21559	14	9035	63
4.	Gurgaon	13001	38	8003	130
5.	Hisar	14753	----	4526	12
6.	Jind	16194	11	9746	11
7.	Kaithal	4622	---	3507	---
8.	Karnal	93428	777	43478	92
9.	Kurrkshetra	43734	825	34973	---
10.	Narnaul	12091	19	93	---
11	Rohatak	3722	---	579	---
12.	Sirsa	300000	---	5000	---
13	Sonepat	917	---	---	--
Total		269176	1946	121451	308

STATEMENT II

Statement showing likely Levy on Rice District wise during Kharif Marketing Season 1980-81

Sr. No	District/Circle	Levy already received (up to 9-12-1980)	Levy likely to be received during remaining part of the year	Total
1.	Ambala	24817	31183	56000
2.	Karnal	44377	53263	98000
3.	Kurukshetra	63264	63736	127000
4.	Kaithal	48640	56360	105000
5.	Sonepat	5009	3991	9000
6.	Rohtak	379	1521	1900
7.	Jind	9813	24187	34000
8.	Hissar	11114	17886	29000
9.	Sirsa	17439	26561	44000
10.	Faridabad	236	264	500
Rice milled out of addy procured by F.C.I under price support		--	156000	156000

operations.				
Total		225088	435312	660400

चौधरी राम लाल वधवाः अध्यक्ष महोदय, पहले तो मै आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार के लिये बड़े अफसोस की बात है कि मेरे जितने भी क्वै चन्ज के जवाब आये है, उनमे सरकार ने यह लिखकर भेज दिया है कि इसमे जितनी मेहनत लगेगी उतना लाभ नही है। इस सब मे घपले है जिस के कारण सरकार जवाब दे रही है (ाोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सवाल पूछिये ।

चौधरी राम लाल वधवाः मै सवाल ही पूछ रहा हूं । मै तो आपको यह बता रहा था कि सरकार मेरे सवालो के जवाबो मे इस तरह से कह रही है ।

श्री अध्यक्षः मेरी यह डियूटी है कि अगर मै यह समझता हूं कि गवर्नमैंट किसी सवाल का इवेसिच रिप्लाई देती है तो मै उसको प्वायंट आउट करू और करता भी हूं लेकिन जहां पर मै जैनुअनली यह फील करता हूं कि time and labour involved in collecting the information is not commensurate with the result likely to be achieved, I accept that.

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, जब यह स्पैसिफिकली पूछा जाये कि लैजिस्लैटर्ज था मिनिन्टर्ज जो इसमे

भाामिल है, तो उनके नाम तो बता दिये जाए, दे यह भी नही दे सकते ?

Mr. Speaker: There must be literally hundreds of godowns. जो किराया पर लिये गये है, उन सब के नाम आने से यह समस्या हल नही होगी । अगर किसी स्पसिफिस गोडाउन के औनर या गोडाउन के बारे मे आपको डाउट है, तो उसके बारे मे आप सवाल उठा सकते है और अरग आप चाहें तो गवर्नमैंट से कोरैस्पोडैंस भी कर सकते है । (Interruptions) Wadnwa, Sahib, this is question hour, I would request you to please ask the relevant supplementary.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मै मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जो गोडाउन्ज किराये पर लिये हुए है और जिनके बनाने के लिये लाखो रूपये कर्जे के दिये हुए है, 5000 रूपये महीना जिनका किराया दिया जा रहा है, उनमे से कुछ गोडाउन्ज सरदार तारा सिंह तथा श्री देवेन्द्र भार्मा या उनके रि तेदारों से भी लिये हुए है ? (व्यवधान)

सिचाई तथा बिजली उपमंत्री(श्री देवेन्द्र भार्मा): स्पीकर साहब, मै इनको चेलैन्ज करता हूं (व्यवधान) इन्होने नाम लिया है ।

Mr. Speaker: Sharma Ji, please sit down. I will give you time for personal explanation at the end of question hour. (व्यवधान) कोई साइड टाक रिकार्ड न की जाये ।

चौधरी गजराज बहादुर नागरः मै अपने फाजिल मैम्बर को यह बताना चाहता हूं कि हरियणा सरकार ने कोई कर्जा किसी मैम्बर को गोडाउन्ज बनाने के लिये नही दिया है मै यह भी उन्हे बता देना चाहता हूं कि किसी के रि तेदार को भी फूड एंड सप्लाईज मिनिस्ट्री ने कर्जा देकर कोई गोडाउन नही बनवाया है ।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने सवाल के (ए) भाग के जवाब मे यह कहा है कि ''इन वर्शा मे खाध व पूर्ति विभाग द्वारा धान की केई खरीद या भण्डार नही किया गया'' और (ख) भाग के जवाब मे यह कह सकते है ''राज्य सरकार द्वारा 16.12.1980 तक कोई ध्यान नही खरीदा गया और न ही चालू वर्श मे राज्य सरकार द्वारा धान खरीदने की सम्भावना है'' मै मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नही किया गया और यह खरीद नही करना चाहते ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, इसकी जरूरत ही नही पड़ी है । हम जो लैबी का चावल होते है यह चावल डायरैक्टर एफ0सी0आई0 को देते है । हमे इस की आव यकता ही नही पड़ती और न ही हमे आव यकता है कि इसे खरीदे ।

श्री लहरी सिह मेहराः अध्यक्ष महोदय, यह जो सूचना पटल पर रखी गयी है इसमे देखने से यह पता चलता है कि जिला कुरूक्षेत्र मे सबसे जीरो प्रोक्योर होती रही है और हुई है

क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जीरो पैदा होती है मै सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि कुरूक्षेत्र जिला के रादौर, पेहवा और गुहला इलाको मे सबसे ज्यादा जीरो पैदा होती है, क्या वहां पर सरकारी गोडाउन्ज बनाये जायेंगे और क्या सरकार अपने गोडाउन्ज को एफ0सी0आई0 को देगीं ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः एफ0सी0आई0 स्टोरेज के लिये अपने गोडाउन्ज बनाती है। उनको स्टोरेज का अपना तरीका है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नही है। उन गोडाउन्ज पर उनका अपना ही कन्ट्रोल है, वे खुद ही अरैजमैट्स करते है, हम इस बारे मे कुछ नही करते।

Mr. Speaker: I would like some clarification about the supplemetnary asked by Dr. Mangal Sein.

एक तो आपकी इस स्टेटमैंट मे है कि इतना इतना राईस इन गोडाउन्ज मे रखा गया है दूसरे इसमे यह भी लिखा हुआ है:'—

"As such the question of making storage arrangements for rice does not arise"why is this contrdiction?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, पोजी ान यह है कि जो डिटेल इसमे दी हुई है यह इसलिए दी हुई है क्योकि सवाल मे इन्होने यह पूछा है कि कुल राईस स्टेट के अन्दर कितना स्टोर किया गया । स्टोरिंग के लिये एफ0सी0आई0 के अपने गोडाउन्ज भी है, सैट्रेल वेयरहाउसिंग कारपोरे ान के

गोडाउन्ज भी है एफ0सी0आई0 वालों ने वहां पर या ओर दूसरी जगहो पर अपना अनाज रख हुआ है , हमने नही रखा ।

श्री अध्यक्षः सवाल के पार्ट मे यह पूछा गया है

''the districtwise total quantity of wheat, paddy and rice stocked stored by the Haryana Government in the Warehouses in the State during the years 197980 and 1980-81 (to-date)"

इसके जवाब मे आपने टेबल 1 पर यज दिया हुआ है कि इतना इतना राईस प्रोक्योर हुआ है । फिर पार्ट बी के जवाब के अन्त मे यह दिया है :–

"As such the question of making storage arrangements for rice does not arise"

तो स्पश्ट स्थिति कया है ?

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, स्टेटमैंट मे काफी डिटेल मे जवाब दिया हुआ है यह जो डिटेल्ज दे रखी है अगर इसके अलावा हमारे पास बहुत ज्यादा गेहूं आता है । तो हम स्कूल की बिल्डिग मे भी रखते है।

श्री अध्यक्षः अगर स्कूल की बिलिंडग मे रखते है तो that is alos a stroage arangement?

मुख्य मंत्री चौधरी भजन लालः स्पकीर साहब, मैम्बर साहब ने जो सवाल पूछा है यह 1979–80 और 1980–81 का पूछा

है । यह स्टोक जो गोडाउन्ज मे रखा हुआ है इसमे पुराना भी है। चौधरी रामलाल वधवा की, हाउस को मोसलोड करने की आदत है सवाल मे कहीं भी एम0एफ0ए0 या मंत्री का नाम नही पूछा है ये हाउस मे कितनी गलत बात कर रहे है कि हमने एम0एल0ए0 और मन्त्री का नाम पूछा है अगर एम0एल0ए0 या मंत्री का नाम पूछने तो हम वाजाह करते है और पूर जवाब देते ।

Mr. Speaker: I will give time for personal explanation at the end of the question hour,

श्री मूल चन्द जैन: स्पीकर साहब, मेरा कहना यह है कि इन्होने जवाब न देने के लिए यह कहना बहाना बनाया है कि ''नाम और किराया बताने मे इतना समय और लेबर लगेगी जिसका कोई फायदा नही होगी'' मै इसको मूनासिब नही समझता। स्पीकर साहब, अभी ि ामला मे एक सैमीनार हुआ था, उसमे चार पांच नोरदर्न स्टेट्स के लोग आए थे और लोक सभा मे भी एक सैमीनार हुआ था। इनमे यह प्र ान आया था कि कई दफा सरकार सवाल का जवाब टालने के लिए बहाना बनाई जाए और उस कमेटी का नाम कमेटी और क्वै ाचंज हो ।ऐसा नही होना चाहिए कि सरकार जिस सवाल का जवाब न देना चाहे उसका जवाब ये दे दें । कि इसके बारे मे इंफरमे ान इकठ्ठी करने मे बडा टाईम लगेगा । स्पीकर साहब, यह मुनासिब बात नही है । मै सुझाव दूंगा कि यहां पर इस तरह की कमेटी बनाई जाए जो यह देखे कि सवाल का जवाब ठीक है या नही । स्पीकर साहब, अब मै

अपना सवाल करना चाहता हूं । क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि क्या सरकार ने अनाज रखने के लिए प्राईवेट आदमियों से गोडाउन्ज किराए पर एि है ?

श्री अध्यक्षः जैन साहब ने सवाल पूछा है कि कितने प्राईवेट गोडाउन्ज सरकार ने लिए है । I think, If the Minister can reply to this question, he may please give the same. But as far as the suggestion regarding constituting a Committee on question is concerned, I think, the Speaker is quite capable of undertaking this job, और मे हाउस को वि वास दिलाना चाहता हूं कि क्वै ाचंज के जो जवाब आते है, मै उनको बहुत डिटेल मे और क्रिटिकल प्वाएंट आफ व्यू से स्टडी करता हूं । जहां मुझे ऐसा लगता है कि इवेसिव जवाब दिया जा रहा है, I refer the same back to the Government to furnish full facts. अगर मिनिस्टर महोदय यह बता सकते है कि कितने प्राईवेट गोडाउन्ज हायर कर रखे है तो वे बात दे।

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, जैसा कि मैने पहले कहा है कि हम स्टोरेज नही करते, स्टोक करते है । यह टैम्पोरेरी फेज है । एफ0सी0आई0 हैफेड और दूसरी एजैन्सियां स्टोरेज करती है। हम तो सिर्फ स्टौक करते है ओर वह भी बहुत भाोर्ट स्पैल के लिए।कई दफा हमारे पास ज्यादा अनाज आ जाता है, ओर अनाज सरप्लस मे होता है तो हमे ओपन मे भी रखना पड़ता है मेरे जवाब मे कोई कफूंयजन नही है । हम तो बहुत ही

भाोर्ट स्पैल के लिए और टम्पोरेरी रखते है । It depends upon the procurement also.

श्री अध्यक्षः जहां तक मै समझ पाया हूं वह यह है कि फूड एंड स्पलाईज डिपार्टमैंट कोई गोडाउन परमानैंट बेसिज पर नही लेता । टैम्परोरेरी बेसिज पर स्टौक करता है हैफेड एफ0सी0आई0 और दूसरी एजैन्सियां स्टोरेज करती है टैम्पोरेरी बेसिज पर स्टोरेज करने के लिए कितना किराए दिया है, अगर आप यह बात सकते है तो बता दे।

चौधरी गजराज बहादुर नागरः यह सवाल बिल्कुल अलहिदा है इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए ।

श्री मूल चन्द मंगलाः स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने बताया है कि हम स्टोरेज करने के लिए गोडाउंज किराए पर नही लेते । स्पीकर साहब, मेरे नोटिस मे है कि इन्होने गोडाउंज किरए पर लिए है और किराया दिया हे ।क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि मैक्सीमम क्या किराया इन्होने दिया है?

श्री अध्यक्षः यह कहते है कि इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए ।

Shri Baldev Tayal: Sir] I would request you to please get thje position clarified. On the one hand the Hon Minister has stated that a statement giving the districtwise quantity of wheat and rice stored by the Haryana Government in hired Warehoused in the State during the years 1979-80

and 1980-81 is placed on the Table of the House] But on the other hand] now the Minister concerned is saying that the Government does not stock wheat, rice etc. Sir, i fall to understand, how the Minister concerned is saying that the Government does not stock wheat, rice etc?

Mr. Speaker: Yes, I agree with Shri Baldev Tayal, He is quite right in mentioning the reply to part a of the question in which the Government has stated the quantity of wheat and rice stored by teh Haryana Government in hired Warehouse (Interruption)

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, मै इस प्वायंट को क्लीयर करना चाहता हूं।

Mr Speaker: I am seized of the point raised by Shri Baldev Tayal because in the written reply, the Government has stated that whead and rice is stored by the Government in the hired warehouses and on the other hand, now it has neen stated that we do not stock wheat rice.

मै यह जानना चाहता हूं कि आपने 2 लाख 69 हजार टन और 1 लाख 21 हजार टन गेहूं कहां पर स्टोर किया था ? (Interruptions) Please give the Minister a chance to give the reply.

चौधरी गजराज बहादुर नागरः स्पीकर साहब, मेरे साथी श्री बलदेव तालय ने जो प्वायंट रेज किया है उसके बारे मे डिटेल्ड रिप्लाई अनेक्सचर 4 मे दिया हुआ है । स्पीकर साहब,

अनेक्सर 4 मे साफ तौर यह इफरमे ान ही हुई है (ाोर एवम व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवा: जो जवाब है उसमे अनैक्सचर 4 है ही नही । कही भी यह इंडरमे ान नही है यह हाउस को मिसलोड कर रहे है ।

Mr Speaker: This is not with me alos I would requet the Government to furnish a detailed reply to this question to the Vidhan Sabha Secretariat for circulation amongst the hon Members.

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे और मुख्य मत्री बीच मे उठकर खडे हो गय। क्या मुख्य मंत्री को अपने मंत्री पर वि वास नही रहा?

श्री अध्यक्ष: गंगा रमा जी, आप बैठ जाईये ।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह उस हिसाब से दिया है कि वह डिटेल हाउस के पटल पर रखी हुई है और जंहा तक प्राईवेट गोडाउंज लेने के सम्बन्ध है, उस बारे मे वाकफयदा आकड़े दिये हुए है । 1979–80 मे 980 गोंडाउंज प्राईवेट लोगों को दिये है और 1980–81 मे 339 गोडाउंनज किराये पर लिये गये है । अध्यक्ष महोदय सुचना मेरा ख्याल है पटल पर रखी हुई है ।

आवाजे: स्पीकर साहब, हमारे पास ऐसी सूचना नही है ।

Mr Speaker: I have already asked the Government to supply detailed reply to this question for circulation amongst the hon. Members.

Reducing the Seats in B.ED. Couurse

***1788, Chaudhri Har Swarup Bura:** Will the chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to reduce the B.ED seats from the next academic session;

(b) the number of posts available to absorb trained graduates in the State;

(c) whether there is any soope to absorb trained graducate in service in the State and

(d) If so, whether there is any proposal under consideration of the Government to give priority for employment to those whor are likely to cross the age limit for entry into Government service?

मुख्य संसदीय सचिव श्रीमति भान्ति देवी:

(क) नही ।

(ख) 1318 ।

(ग) हां, प्रि ाक्षित स्नातको को, सामाजिक अध्ययन अध्यापको/अध्यापिकाओ के पदों के अतिरिक्त, उपलब्ध रिक्तियो के समक्ष समायोजित किए जाने की सभावना है। क्योंकि सामाजिक अध्ययन अध्यापको/अध्यापिकाओ पहले ही सरप्लस है, इसलिए इनकी भर्ती पर प्रतिबन्ध है ।

(घ) नही।

चौधरी हरस्वरूप बूराः स्पीकर साहब, अभी सी0पी0एस0 महोदया ने अपने जवाब के पार्ट बी मे बताया है कि राज्य मे प्रि ाक्षित स्नातकों की सेवा मे समायोजन करने के लिये उपलब्ध पदों की सख्या 1318 है और इस समय बहुत से साईस मास्टर और मैथ के मास्टर सरप्लस है । उनकी दो दो साल की सर्विस भी हो गयी है लेकिन किसी वजह, से वे 31.12.1979 को सर्विस मे नही थे जो कि सरकार ने निर्धारित कर रखी है कि अगर 31.12. 1979 को जो आदमी सर्विस मे होगा, उनकी सर्विसिज रैगुलर कर दी जाएगी । क्या सरकार ऐसे केसिज पर विचार करेगी कि जो 31.12.1979 को सर्विस मे नही थ और उन की सर्विस 2–2 साल की हो चूकी है उन्हे दोबारा सर्विस मे ले लिया जाएगा ताकि किसी बेरोजगारी का सामना न करना पड़े ?

श्रीमती भाान्ति देवीः अध्यक्ष महोदय, ऐसे कई मामले विचारधीन है सरकार के पास जितनी वैकेन्सीज रिक्त पडी है उन वैकेन्सीज को सरकार बहुत भीघ्र ही एस0एस0एस0 बोर्ड द्धारा

भरवाने का प्रयास करेगी।सरकार ने जो डेट 31.12.1979 की रखी थी कि जिन टीचर्ज को 31.12.1979 तक सर्विस मे काम करते हुए 2 साल हो जाएगे, उनको रैगूलर कर दिया जाएगा, सरकार ने उन सब को, जो इस पालिसी के तहत आते थे रैगुलर कर दिया है जिन कर्मचारियों की सर्विस 31.12.1979 को दो साल की पूरी हो गयी थी और वे इस डेट सर्विस मे नही थे लगभग 1331 थे इनको हम बहुत भीघ्र ही एस0एस0एस0 बोर्ड द्धारा भरवाने का प्रयास करेंगे।

सरदार सुखदेव सिंहः स्पीकर साहब, आपकी मारफत मै मुख्य संसदीय सचिव महोदया से यह जानना चाहता हूं कि सिरसा जिले मे जे0बी0टी0 ओर साईस मास्टरों की सैकड़ो पोस्ट खाली पड़ी है, क्या उन पोस्टों को भरने के लिए सरकार कोई उपाय करेगी?

श्रीमती भाान्ति देवीः अध्यक्ष महोदय अगर मेरे भाई की नालिज मे कोई ऐसा स्कूल रह गया हो जहां पर कि पोस्टे खाली पड़ी हो तो वे हमारे नोटिस मे लांए, हम तुरन्त ही वहां पर टीचर्ज भेजने का प्रबन्ध करेगे।

श्री अध्यक्षः साहेबान मेरी माननीय सभी सदस्यो से यह रिकवेस्ट है कि वे भातिपूर्वक सुनें क्याकि बीच मे उठाकर बोलने मे किसी की इज्जत नही बढगी ऐसा करने मे अपनी नालिज का हमे डिसप्ले नही करना चाहियें । बल्कि ठीक उसका अपोजिट

डिसप्ले करना चाहिए क्योंकि जब कोई मैम्बर या मिनिस्टर साहेबान उठकर बोलते है तो बहुत सारे माननीय सदस्य बीच मे उठकर बोल पडते है आप से मेरी प्रार्थना है कि आप भातिपूर्वक सुने। यह स्टेट के हित का मामला है, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है स्टेट की अनएम्पलायमैंट का मामला है और उसका हम लोग खिलवाड उड़ा रहे है, ऐसा करना हमारे लिये भाोभा नही देता । मै फिर रिकवैस्ट करूगा कि जब इस तरह की कोई डिस्क ान हो रही हो तो आप भाातिपूर्वक सुनने की कृपा करे ।

चौधरी रिजक रामः अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य सचिव महोदया ने यहां पर बताया कि जिन अध्यापको की 31.12.1979 को दो साल की सर्विस हो गयी थी, उनको एबचार्ज कर दिया गया । मै यह जानना चाहता हूं कि जिन अध्यापको को दो साल की सर्विस हो गयी है लेकिन वे 31.12.1979 को सर्विस मे नही थे, क्या उनको भी एबचार्ज किया जाएगा?

श्रीमती भाान्ति देवीः स्पीकर साहब, ऐसी अभी कोई प्रोपोजल सरकार के विचाराधीन नही है ऐसा है कि हम उन लोगो को जिनकी सर्विस दो साल की हो गयी है और वे 31.12.1979 को सर्विस मे नही थे, एस0एस0एस0 बोर्ड द्वारा भर्ती करवाने का प्रयास करेगे ।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, मुख्य संसदीय सचिव महोदया ने अभी बताया है कि बहुत से सामाजिक अध्ययन के

अध्यापक और अध्यापिकाए सरप्लस है स्पीकर साहब, आप भी भली भाति जानते है कि हर साल बहुत से लड़के लडकियां जो कि बी0एड0 की ट्रेनिंग लेकर निकलती है, उनकी संख्या हजारो मे होती है और बहुत से ऐसे अध्यापक/अध्यापिकांए भी है जिन्होने कि पहले से ही बी0एड0 की ट्रेनिग ले रखी है लेकिन वे नौकरियों के लिये मारे मारे फिर रहे है । क्या ऐसे लोगो की सरकार एबजार्ब करने का विचार रखती है और आगे के लिए ट्रेनिंग बन्द करने का काई विचार है जब तक पहली ट्रेनिंग लिये हुए लोग एवचार्ब न हो जाए?

श्रीमती भाान्ति देवीः स्पीकर साहब, फरदर ट्रेनिग बन्द करने का सरकार का कोई विचार नही है क्योंकि आप जानते है कि आजकल गणित और विज्ञान के अध्यापक/अध्यापिकाओ की बराबर आव यकता है, उनको ट्रेड करने की काफी आव यकता है । एस0एस0 मास्टर्ज सरप्लस है हम उनको विज्ञान और मैथ का सबजैक्ट पढा कर ट्रेड करते है । जिन को हम ट्रेनिग देते है उन मे से काफी सारे प्राईवेट स्कूलो मे चले जाते हैै और काफी सारे दूसरे प्रान्तो मे चले जाते है अगर हम इस ट्रनिग को बन्द कर देंगे तो सरकार के उपर एक और बोझ पड़ेगा कि जो लैक्चरर्ज ट्रेनिग देने के काम मे लगे हुए है, वे आन रोड़ हो जाएगे और हमारे प्रान्त मे बेरोजगारी ही समस्या और भी बढ जांएगी ।

स्वामी अग्निवे ाः मै मुख्य सचिव संसदीय सचिव महोदया से यह जानना चाहता हूं कि पहले हरियाणा के उधोग

विभाग ने लड़कियो के लिये होम क्राफट्स का कोर्स आरम्भ किया था और उस ट्रेनिग से लगभग 15 हजार से 20 हजार तक लड़कियो ने लाभ उठाया है । अब वे चार चार सालो की सर्विस के बाद घर पर बैठी है और सरप्लस है, उनको सरकार की तरफ से मान्यता नही दी जा रही है न तो उनको अतिरिक्त माना जा रहा है और न ही अपनी नीति मे परिवर्तन करके उनको नौकरी मे दोबारा स्थायी रूप मे लेने का विचार करेगी ?

श्री अध्यक्षः मेन सवाल से तो इसका कोई संबध नही है, अगर मिनिस्टर साहब उतर देना चाहे तो दे सकते है।

श्रीमती भाान्ति देवीः अध्यक्ष महोदय, हमारे औधोगिक प्रि ाक्षण विभाग ने एक ट्रेनिग चालू की थी जिस होम साईस के नाम से जाना जाता है यह काम डा0 साहब के टाईम भारू हुआ थ और कुछ प्राईवेट संस्थाओ के लोगो ने इस दुकानदारी बना रखा थ और इसमे बहुत अनियमिततांए हो रही थी हमारी सरकार के आते ही हमने निर्णय लिया कि इन दुकानदारो की दुकानदारी को बन्द करना चाहिए। जहां तक ट्रेड लड़कियां का सवाल है वे देहात की है और सरकार चाहती है कि जितनी लडकिया ट्रेड हो चुकी है उनको ि ाक्षा विभाग मे सेवा करने का मौका दिया जाए ।यह मामला विचारधीन है ।

डा मंगल सैनः स्पीकर साहब मेरे उपर इन्होने एसप ंन किया है मुझे जवाब देने का मौका मिलना चाहिए । I have to clear my position, Sir

Mr. Speaker: It escaped my attention what she said but i will give you time for personal explantion at the end of the question hour,

श्री गुलजार सिंहः स्पीकर साहब, जैसा कि सी0पी0एस0 महोदया ने बताया कि 1300 के लगभग जो अध्यापक एडहोक बेसिज पर लगे हुए थे और जिनकी दो साल की सर्विस भी पूरी हो चुकी है लेकिन उनको रैगुलर नही किया जा रहा है । इन्होने बताया कि अब बोर्ड के जरिये उनको नौकरी मे लेगे । मै यह जानना चाहता हूं कि क्या ये कोई गारन्टी देंगे कि बोर्ड के जरिये उन सब को ले लिया जाएगा क्योंकि बोर्ड के जरिये तो और लोग भी आ सकते है ?

श्रीमती भाान्ति देवीः स्पीकर साहब, जैसे कि मैने बताया कि हमारे पास अध्यापको के बहुत पद रिक्त है और आव यकता अनुसार सब को मौका मिलेगा कि वे रैगुलर हो सके ।

श्री अध्यक्षः लास्ट सप्लीमैटरी बाई श्री हर स्वरूप बूरा ं।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, हमारी तरफ आप ध्यान ही नही देते । अगर हमे मोका नही दिया जाएगा तो हम वाक आउट कर जाते है (ाोर)

श्री अध्यक्षः अगर आप वाक आउड करने का थैट देते है तो बडी खु ाी से वाक आउट कर जांए । हाउस एक सैकिन्ड के

लिए चुप चाप नही बैठता और मेरा सब तरफ ध्यान रहता है । अगर फिर से आप वाक आउट करने का थैट देते है तो दरवाजे खुल है, बडी खु ी से कर सकते है (ोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, हमारी ऐसी कोई इन्टैन ान नही है ।

Mr. Speaker: Gentlemen, I may tell you that i am not misutilizingor wasting the time of the House. हाउस का एक एक सैकिन्ड यूटिलाइज हो रहा है। जहां तक भी हो सका, मै चारो तरफ नजर रखता रहा हूं और ज्यादातर बैक बैचर्ज को मौका देना चाहता हूं । अगर फिर भी मैम्बर साहेबान समझते हूं कि मै उनकी तरफ ध्यान नही देता और मै उनके थैट के अन्डर उनको बुलाउगा तो इस थैट के नीचे मै कतई नही आउगा ।

श्री वीरंन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो उसके लिए हमे अफसोस है ।

श्री भले रामः अगर आप हमें सवाल पूछने की इजाजत नही देंगे तो मझे वाक आउट करना पडेगा ।

श्री अध्यक्षः दरवाजे खुले है, आप बडी खु ी से वाक आउट कर सकते है ।

श्री वीरंन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, हमे अफसोस है । We are Sorry.

Mr. Speaker: Thank you very much. I appreciate the sentiments expressed by Sh. Vareender Singh.

डा0 मंगल सिंहः स्पीकर साहब, मेरी गुजारी ा है कि आप भी थोड़ा सा .....

श्री अध्यक्षः आप हंस कर मेरे से कुछ भी करवा ले लेकिन मै थेट के नीचे काम नही करूगा ।

श्री बलदेव तायलः स्पीकर साहब, भले राम जी भी हंस रहे है, नाराज नही है।

Mr. Speaker: Then I am Sorry.

चौधरी हरस्वरूप बूराः अध्यक्ष महोदय, अभी सी0पी0एस0 साहिबा ने बताया कि बोर्ड के जरिये भर्ती करेगे । मै उनसे पूछना चाहता हूं कि कुछ ट्रेड टीचर्ज ऐसे मार्जिन पर होते है जो औवर ऐज होने वाले होते है अगर बोर्ड ने टाइम पर वेकैसी न निकाली ओर वे औवर ऐज हो गये तो उनका क्या होगा ? क्या उनको रैगुलर करने मे कोई प्रैफरैस दिया जाएगा ?

श्रीमती भाान्ति देवीः अध्यक्ष महोदया, हमने पहले ही 27 साल का बजाए 30 साल की आयु सीमा नौकरी मे प्रवे ा के लिए बढा दी है और इससे ज्यादा आयु सीमा बढाने का सरकार का कोई विचार नही है ।

Loans advanced through Haryana Harijan Kalyan Nigam

***1826 Chaudhri Bhag Mal:** Will the Minister for irrigation and Power be pleased to state-

(a) the number of persons who applied to the Harjian Kalyan Nigam, Haryana for the grant of loans during the year 1966-1967 to date.

(b) the number of persons out of those refered to in part (a) above to whom the loan was advanced together with the total amount of loan so advanced; and

(c) whether complaints regarding the misuse of the aforesaid loan have been received during the period referred to in part (a) above?

सिचाई तथा बिजली मंत्री चौधरी मेहर सिह राठीः

(क) 38073 व्यक्ति ।

(ख) 6055 व्यक्ति । ऋण 15539343 रूपये ।

(ग) हां ।

चौधरी भाग मलः क्या मंत्री महोदय बताएगे कि जो इनके पास कम्पलैट्स आई है उनमे से किसी के खिलाफ कोई ड्रस्टिक स्टैप्स भी लिये गये है या नही ?

चौधरी मेहर सिंह राठीः मेन कप्पलैट जो है यह हिसार के गुंलाब सिंह जैन के खिलाफ आई है कि उन्होने धोखे से निगम से पैसा ले लिया ।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, जो आकड़े मिनिस्टर साहब ने दिये है उनसे हरियाणा हरिजन कल्याण निगम की परफारमैंस बहुत नजर आती है इन्होने 14 सालों मे 6055 आदमियों को कर्जे दिये बताये है । हमारे हरियणा मे चार लाख हरिजन परिवार है, इस हिसाब से सबको 90 साल मे कर्जा दिया जाएगा। इन आकड़ो के हिसाब से एक साल मे सिर्फ 440 परिवारो को कर्जा मिलेगा ओर सभी मे से 1/10 को भी कर्जा देने के लिये 90 साल लगे जाएगे । तो क्या मंत्री जी हरिजन कल्याण निगम की परफारमैंस से सनतुश्ट है, अगर नही है तो क्या कदम उठाना चाहते है ?

चौधरी मेहर सिंह राठीः यह निगम 2.1.1971 से काम कर रही है यानी इसको काम करते हुए अभी दस साल हुए है इसलिये यह गलत है कि यह 14 साल से काम कर रही है ।हमारे पास अभी तक कुल 9120 दर्खास्ते आई है इनमे से 3135 ने अभी फारमैलिटीज पूरी नही की है । बाकी 6055 ने फारमैलिटज पूरी कर दी और उनको उसी वक्त कर्जा दे दिया गया था । जो आदमी फारमैलिटीज पूरी कर देता है उसको उसी वक्त कर्जा दे दिया जाता है ।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, बाबू मूल चन्द जैन जी की बात ठीक है । लेकिन हरिजनो के कल्याण के लिए जितनी रा ि ा निर्धारित करनी चाहिए थी उतनी उस समय की जनता पार्टी की सरकार ने नही की और उस सरकार मे बाबू

जी वित मंत्री रह चुके है इन्होने भी हरिजनो के लिए कुछ भी नही किया । आप भााति से सुनिए । अध्यक्ष महोदय, आज से पहले हरियाणा हरिजन कल्याण निगम का सारा बजट 2 करोड़ रूपए का हुआ करता था लेकिन आज की कांग्रेस आई की सरकार ने 2 करोड़ से बढा कर 5 करोड़ रूपए कर दिया है ताकि हरिजनो को ज्यादा सुविधाए दी जा सके । हमने कढाई गुणा बढाया है ।

डा मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, अभी अभी पिछली सरकार की निन्दा करते हुए मुख्य मंत्री जी ने अपने मुह मियां मिट्ठू बनते हुए कहा कि मेरी सरकार ने हरिजनो को सुविधाए देने के लिए 5 करोड़ रूपए का प्रावाधान किया है । स्पीकर साहब, आप इस सवाल के जवाब के पार्ट बी मे देखे कि इस निगम को एक करोड़ 55 लाख 39 हजार 345 रूपए दिये गए है और मंत्री महोदय ने फरमाया है कि 9 हजार दरखास्ते आई थी जबकि 38073 दरखास्ते लोगो ने दी है ।

Mr. Speaker: Dr. Sahib, I these applications hed been received form 1966 onwards.

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरे पूछने का अभिप्राय यह है कि यदि इन्होने हरिजन कल्याण निगम के लिए 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है तो सिर्फ उसको डेढ करोड़ रूपया ही क्यो दिया गया है और बाकी का साढे तीन करोड़ रूपया कहा गया ?

चौधरी भजन लालः बाकी का पैसा 31 मार्च तक देना है ।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, आज से कई साल पहले श्री गुलाब सिंह जैन ने हरियाणा हरिजन कल्याण निगम से फर्जी रजिस्टर मे चढा कर हरिजनो के नाम कर्जा लेकर ट्रेक्टर ले लिए और आज उन हरिजनो के खिलाफ मुकदमे बन रहे है तथा पुलिस उनको पकड़ रही है। मैने खुद निगम को चिट्ठी लिखी थी और निगम की मीटिंग मे यह पास किया गया था कि उसके खिलाफ क्या ऐक्सन लिया गया और यह मामला किस स्टेज पर है ?

चौधरी मेहर सिह राठीः स्पीकर साहब, उसके बारे मे दो चार एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई गई है । हिसार की पुलिस ने वह केस दो बार दर्ज किया है । पहला केस 24.7.1977 को धारा 420,467, और 468 के तहत दर्ज किया गया था और दूसरा इन्ही धाराओ के तहत 30.3.1978 को दर्ज किया गया था यह केस दो दफा दर्ज हुआ है ।

चौधरी उदस सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैने डिप्टी कमी ानर हिसार की खुद चिटठी लिखी थी कि श्री गुलाल सिंह जैन ने हरिजन कल्याण निगम से फर्जी रजिस्टर मे हरिजनो के नाम कर्जा चढा कर खुद ट्रैक्टर ले लिए और उन ट्रैक्टर्ज को खुद बेच कर पैसा ख गया ।स्पीकर साहब, हरियणा हरिजन क्लायण

निगम का तीन लाख रूपया श्री गुलाब सिंह जैन और उसके लडके से इस्तेमाल किया है । मै मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार उसके बारे मे क्या कार्यवाही कर रही है और वह केस किस स्टेज पर है ?

चौधरी मेहर सिह राठीः स्पीकर साहब, अभी पुलिस उस केस की तफ्ती ा कर रही है । बाबू गुलाब सिंह जैन उनका लड़का और एक बाबू राम नाम का हरिजन है जो कि बाबू गुलाब सिंह जैन का ही आदमी है इनके खिलाफ केस बना है । अभी उनके खिलाफ इनक्वायरी हो रही है ।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हुए आज अढाई साल हो गए है, बडे भार्म की बात है कि अभी तक उस केस की इनक्वायरी चल रही है इनको आनी चाहिए इनको ..... स्पीकर साहब अढाई साल के अर्से मे यह सरकार अभी तक उस केस मे कुछ भी नही कर पाई है इनको ....आनी चाहिए (ाोर एवम विध्न)

श्री अध्यक्षः बाबू जी आप बैठ चाईए (ाोर एवम विध्न) जरा भााति से बोलिए ।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, आप मुझे माफ करेगे । मै अपनी भाातिं थोडी सी लूज कर गया हूं । स्पीकर साहब, उस केस को दर्ज हुए आज तीन साल होने जा रहे है और यह

सरकार उसमे कुछ भी नही कर सकी है, इनको .....आनी चाहिए (ाोर एवम विध्न)

श्री अध्यक्षः मुझे ऐसा लगता है कि this point has touched some explosive situation. मै गवर्नमैंट से दरखास्त करूगां कि यदि कोई ऐसा केस पेडिग है तो उसको एक्सपेडाइट किया जाए और उस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाए । (ाोर एवम विध्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि श्री गुलाब सिंह जैन और उसके लड़के ने हरिजनो के नाम से कर्जा लेकर ट्रैक्टर लिया जोकि गलत थे । अध्यक्ष महोदय, इस बारे मे मै आपको थोडा सा बताना चाहता हूं और आप रिकार्ड निकलवा कर देख लें, जब चौधरी देवी लाल जी मुख्य मंत्री थे और इस जगह पर बैठा करते थे जहां आज मे बैठा हूं मैने उस जगह पर बैठे हुए हाउस मे एक क्वे चन किया था और मैने उस सरकार पर इल्जाम लगाया था कि श्री गुलाब सिंह जैन ने हरिजन कल्याण निगम से हरिजनो के नाम गलत कर्जा लेकर ट्रैक्टर लिया है उस पर सरकार ने कोई कार्यवाही नही की है सरकार को इनक्वायरी करनी चाहिए लेकिन उस सरकार ने कोई इनक्वायरी नही की और जिस दिन मै मुख्यमंत्री बना यह इल्जाम लगाया था और बाबू मूल चन्द जैन उस सरकार मे वित्त मंत्री थे (ाोर एवम विध्न)आप भातिं से सुनिए । मै यह बात रिकार्ड की कह रहा हूं , गलत थोडे ही कह रहा हूं । मै उस सरकार पर यह इल्जाम

लगाया था और बाबू मूल चन्द जैन उस सरकार मे वित्त मंत्री थे (ाोर एवम विध्न) अध्यक्ष महोदय, उस सरकार ने कोई कार्यवाही नही की। इस सरकार ने बनते ही बाबू गुलाब सिह जैन के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया और उसके खिलाफ इनक्वायरी भाुरू की यह इल्जाम लगाया था और बाबू मूल चन्द जैन उस सरकार मे वित्त मंत्री थे (ाोर एवम विध्न)

Shri Hira Nand Arya: He is misleading the House (Interrpution)

श्री मूल चन्द जैनः अध्यक्ष महोदय ये बिल्कुल गलत कह रहे है ये 1978 मुख्यमंत्री बने थे और आज तक इन्होने कोई कर्यवाही नही की है। यह इल्जाम लगाया था और बाबू मूल चन्द जैन उस सरकार मे वित्त मंत्री थे (ाोर एवम विध्न)

श्री अध्यक्षः मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमैंट दी है कि उनके खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया गया है । I have no ground to turn down the statement made by the chied Mineister But at the same time I must say कि अगर मुकदमा दर्ज किया हुआ है तो जब मंत्री से सवाल पूछा गया था तो उनको सिर्फ इतना जवाब दे देना चाहिए था कि उस भाख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और यह सिचुए ान डिवैल्प नह होती मै सरकार से दरखास्त करूगा कि इस मैटंर को एक्सपेडाइट किया जाए क्यो कि हाउस इस पर बडा एजीटेटिड फील कर रहा है । Now this matter is colosed (interrptions) I have requested the Government to

expedite this matter and take appropriate action. Gentlemen, now this matter is closed.

श्री फतेह चन्द विजः अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय ने जवाब मे कहा कि श्री गुलाब सिंह जैन.....

Mr. Speaker: Gulab Singh Jain's incident is closed. I have requested the Government to expedite the matter and take proper action. (Interruprtions)

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय चीफ मिनिस्टर साहब वहां खाना खाते है यह मिली भगत का परिणाम है ।

परिवहन मंत्री श्री जगन नाथः चौधरी देवी लाल जी भी वहां खाना खाकर आए थे और श्री वीरेन्द्र सिंह जी भी साथ थे ।

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय जिस पूरक प्र न के उतर मे गुलाब सिंह जैन.....

श्री अध्यक्षः चौधरी भले राम।

Shrimati Sushama Swaraj: I am not asking about Shri Gulab Singh Jain, Sir (Interruptions)

श्री अध्यक्षः चौधरी भले राम।

श्रीमती सुशमा स्वराजः स्पीकर साहब, इस केस का एक पहल यह है .....

श्री भले रामः स्पीकर साहब, हरिजन कल्याण निगम हरिजनो को मकान बनाने के लिए अढाई तीन हजार रूपये तक का कर्जा देता है और इतनी ही रा ि ा वैलफैयर महकमा देता है लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पिछले साल हरिजन कल्याण निगम पैसा देने के असमर्थ रहा और वह सारे का सारा पैसा लैप्स हो गया । क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि पिछले साल पूरा पैसा खर्च नही हो सका लेकिन उस पैसे को हमने अगले साल मे डायवर्ट कर दिया है वह लैप्स नही हुआ है ।

श्री भले रामः अध्यक्ष महोदय 820000 रूपये लैप्स हुए है । क्या मुख्य मंत्री जी बताएगे कि इससे डबल पैसा इस साल दिया जाएगा ?

श्री अध्यक्षः मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पैसा लैप्स नही हुआ है पैसा बचा था जो अगले साल मे डायवर्ट हो गया है ।

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, पैसा बचने का मतलब ही लैप्स होना होता है

श्री अध्यक्षः साफ तौर पर यंहा कहा गया है कि पैसा लैप्स नही हुआ है बच गया था जो अगले साल मे डायवर्ट हो गया है

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय जिन हरिजनो के नाम से कर्जा लिया गया है उनके खिलाफ जिला प्र ाासन ने वसूली की कार्यवाही भाुरू कर रखी है और उनको हैरास किया जा रहा है । मैने इस केस को बतौर मैम्बर पब्लिक अडरटेकिगज कमेटी मे ऐग्जामिन किया है जब सरकार के नोटिस मे यह बात है कि हरिजनो के नाम से झुठे कर्जे वसूल किए गए है तो क्या मुख्य मत्री जी बातएगे कि उनके रिकवरी के लिए जो कार्यवाही की जारही है उसे समाप्त किया जाएगा ?

चौधरी मेहर सिंह राठीः स्पीकर साहब गुलाब सिंह जैन ने 396000 रूपये के ट्रैक्टर लिए थे और उसमें से उन्होने 311000 रूपये दे दिए है यह रिकवरी भी गुलाब सिंह जैन दे रहा है ।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी ने तो हरिजन एम0एल0एज0 के कहने पर हरिजन कल्याण निगम का बजट दो करोड़ से बढा कर पांच करोड़ रूपये किया है इसके लिऐ हम उनके धन्यवादी है ।

श्री अध्यक्षः आप सवाल पूछिए ।

चौधरी गया लालः स्पीकर साहब प्र ान के भाग (ग) के बारे मे मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिस फर्म ने गलत नामो से अपनी जमानत से पैसा लिया था, उससे वह पैसा वसूल किया गया है या नही ?

(इस प्र ान का उतर नही दिया गया)

श्री लहरी सिंह मेहराः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महेादय ने सूचना दी कि सन् 1966–.67 से लेकर अब तक 6055 आदमियों को 15539343 रूप्ये का ऋण दिया गया लेकिन मै मंत्री महोदय से यह जानतना चाहूंगा कि जबसे चौधरी भजन लाल कीी सरकार वजूद मे आई है उस दिन से आज तक कितने लोनीज को कितने रूपये का ऋण दिया गया?

चौधरी मेहर सिंह राठीः स्पीकर साहब, इसके लिए से अलहदा नोटिस दे, हम जवाब देगे ।

Allotment of Revolvers and Guns out of C.M Quota

***1830 Shri Raghu Nath Goyal:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the names and addresses of the persons who have been allotted revolvers and guns out of C.M Quota and the confiscated fire arms since 1-6-1977 to date.

(b) whether some Members of the haryana egistative Assembley alos applied for the fire arms referred to above for their self protection, if so, their names; and

(c)the names of the M.L.As. out of those referred to in part (b) who were not allotted the fire arms together with the reasons therefore?

मुख्य मंत्री चौधरी भजन लालः

(क) मुख्य मंत्री कोटा से दिनांक 1.6.1977 से 7.10. 1980 तक अवधि के दौरान 74 व्यक्तियो को जब्त भुदा अस्त्र अलाट किए गए है। उनके नाम तथा पते सूची मे दिए गए है जो विधान सभा के पटल पर रखी है ।

(ख) हां, कुछ विधान सभा सदस्यों ने भी इन अस्त्रो के लिए प्रार्थना की । उनके नाम सूची मे दर्ज है जो विधान सभा के पटल पर रखी गई है।

(ग) अभी तक किसी भी विधान सभा सदस्य की प्रार्थना अतिम रूप मे अस्वीकार नही की गई है कुछ मामले अभी भी विचाराधीन है ।

STATEMENT 'A'

Allotment of confiscated Fire arms from C.M.'s Quota.

Sr No.	Name and addres of allottess of Firearms from C.M.'s Qota
1	2
1.	Sh. Kulwant Singh I.A.S Commissioner, Ambala Division, Ambala (now Financila Commissioner, Chandigarh)
2.	Sh. Fateh Chand M.L.A Panipat
3.	Sh. Teja Singh Dardi M.L.A Tiraon P.o Bhikhi

	Teh.Mansa Distt Bhatinda.
4.	Lt. Col. B.B Gupta 152 Air Defence Regt C/o 56 APO
5.	Shri Sher Singh S/o Sadhu Ram Thansar Member janata Party Distt Executive. Kurukshetra.
6.	Chaudary Bhagmal M.L.A V& P.O Marwa Kalan Teh Jagadhri, Distt Ambala
7.	Ch. Dharam Singh I.P.S , DIG Ambala Range.
8.	I.C 5117 Brig. T.S Chaudhrary, Cdr, 48 Arty. Bde C/o 56 APO
9.	Sh. Sanpar Singh Additional Political Secy. To C.M Haryana, Chandigarh
10.	Sh. Balbir Singh Dy.Principal Secy. To C.M Haryana, Chandigarh
11.	Sh. Sher Singh Excise and Taxation Mainister, Haryana Chandigarh
12.	Sh. Kulwant Singh I.A.S Commissioner, Ambala Division, and Secy. to Govt. Haryana
13.	Sh. Surajbhan M.A LL.B M.P Lok Sabha 121 railway Road, Ambala Cantt.
14.	Sh.M.S Malik I.P.S Asstt. DIG/CID Haryana
15.	Sh. Ram Kishaan M.L.A Safidon, Distt Jind
16.	Sh.Virender Singh Home, Minister Haryana

17.	Sh.Sajjan Singh S/o Karam Singh H.C 275/R Hno. 3278 sec 22D chandigarh
18.	Sh. Hukam Singh M.L.A ward No. 1 Distt Bhiwani
19.	Sh. Jal Narain, M.L.A Kalanur, Distt Rohtak
20-.	Sh. Jaswant Singh Ex. Capt 17 , M.L.A Flat Sector 3, Chandigar
21.	Sh. Sant Kumar M.L.A S/o Raghbir Singh R.K Bhawan, Kishan Pura Rohtak
22.	Sh. Attarjit Singh Nehra, Addl. Advovate General. Haryana
23.	Sh. Ram Kishan M.L.A Chairman Housing Board, Haryana Kothi No. 64 Sec 8 Chandigarh
24.	Sh. Jaimal Singh s/o Molu Ram V&P.O Chau.
25.	Sh. Mahander Singh Lathar, M.P Lok Sabha. Karnal.
26.	Sh. Ranbir Singh s/o Ch. Daulat Ram V. Ram Sara The. Fazilka distt Ferozepur.
27.	Sh. Jai. Pal Singh V. Badshapur Machari,Distt Sonepat.
28.	Sh. Birender Singh M.L.A
29.	Sh. Bhim Sein Gunman to C.M Haryana
30.	Sh. V.P Johar I.A.S. Financila Commissioner, Haryana, Chandigarh

31.	Sh. Chand Kashya s/o Shri. Shiffia Mal of Meham Road Gohana, distt Sonepat
32.	Sh. Ishawar Singh M.L.A VPO Jaggil, Teh Kaithal Kurukshetra.
33.	Sh. Sher Singh Revenue Minister, Haryana, Chandigarh
34.	Sh. Manohar Lal S/o Raju Ram VPO Kajila, Distt Hisar
35.	Sh. Mohamed Yunus, A.S.I C.I.D office of the D.I.G/C.I.D Haryana, Chandigarh
36.	Sh. Jogi Ram M.L.A Hayana Chandigarh
37.	Sh. Om Parkash S/o Arya Lal VPO Kurri Distt Hisar
38.	Sh. Ramji Lal S/o Sewa Ram VPO Kunai Distt Hisar
39.	Sh. Ude Singh Dalal, M.L.A VPO Manathi, Distt Rohtak.
40.	Sh. Sardar Khan Dy. Home Minister, Haryana Chandigarh
41.	Sh. Kanshi Ram, Jamidar/Khadya Minister Haryana Chandigrh
42.	Sh. Malik Daya S/o Malik Narshing Dass Sarpach Nasirpur, Ambala City.
43.	Sh. Sakrulla Khan M.L.A Ferozepur Jhirka, Distt

	Gurgaons.
44.	Sh. Hanuman Bishnoi Suraj Theatre, Sirsa
45.	Sh. Surja Ram S/o Shri Brij Lal Alawalyas distt Hisar
46.	Sh. Pir Chand M.L.A Fatehbad Haryana Chandigarh
47.	Sh. Hat Ram Bhima Ram V. Bara Khana, Mamalpur Rohi Teh Fatehbad Distt Hisar
48.	Sh. J.P Bishnoi Poliitical Sacy. To C.M Haryana Chandigarh
49.	Sh, Sital Singh S.I/C.I.D, Haryana, Chandigarh
50.	Sh. Rajesh Kumar Sharma S/o Bhagwat Dayal r/o Rewari distt Narnaul
51.	Sh. Mani Ram S/o Sahi Ram V&PO Adampur Distt Hissar,
52.	Sh. Subash S/O Siri Ram Village Khajuri Jatti Distt Hissar
53.	Sh. Pirthi Singh S/o Sh. Bir Singh V. Nagthala Distt Hissar
54.	Sh. Sagar Chand Sharma D.S.P Haryana Chandigarh
55.	Sh. Sham Lal Shastri Near Head Post Office, Jind.
56.	Sh. GurbachanSingh Gate Holidar, Civil Secretariat, Haryana Chandigarh

57.	Sh. Baru Ram S/o Nathu Ram V. Rijhand. Teh Safidon Distt Jind
58.	Sh. S.P.S Rathorem I.P.S Sr. Supdt. of Police, Ambala
59.	Sh. Ram Pal Singh, Public Works Minister, Haryana Chandigarh
60.	Sh. Shyama Ram Kataria S/o Shri Inder Ram Kataria. V&P.O Sohana Teh UMB.
61.	Sh. Omparkash S/o Sh. Sohan Lal V.&P.O Mandi Adampur Distt Hisar
62.	Sh. Bull singh S/o Ch. Pokar Mal r/o Suraj Theatre. Sirsa
63.	Sh. Bhurra Ram S/o Manphool Singh V. Muhammadpur, distt Hisar
64.	Sh. Charanjit Singh 51 D.L.F Colony Gurgaon.
65.	Sh. R.S Chauhan, H.C.S Officer on Special Duty to C.M Haryana , Chandigarh
66.	Sh.Vijay Pal Singh Deputy Speaker Haryan Vidhan Sabha, Chandigarh
67.	Dr. Mohinder Kumar Ranjan S/o Shri Virbhan Naval Talkies Panipat, distt Karnal.
68.	Sh. R.S Gupta, Distt Sessions Judge Karnal
69.	Sh. R.S Dhari Balmik Ex M.L.A Gohana Distt Sonepat.

70.	Sh. Prit Singh H.C.S Sub- Divisional Offiers, Civil Jagadhri Distt Ambala.
71.	Sh. Dewakar Partap Singh H.No. 917 Sec 15 A Faridabad, Haryana
72.	Sh. Ratti Ram s/o Singram V.and PO Seedpur Distt Karnal.
73.	Sh. Kartar Singh Thakar S/o Gobind Ram Gurdwan Manji Sahib, Ambala
74.	Sh. Ram Duptt Singh D.S.P Naraingarh.

STATEMENT 'B'

List of M.L.A applying for confiscated Firearms.

1.	Sh. Fateh Chand Vij, M.L.A
2.	Chaudhry Bhagmal, M.L.A
3.	Sh. Sher Singh, Revenue Minister, Haryana
4.	Sh. Ram Kishan. M.L.A
5.	Sh. Virender Singh Ex-Home Minister, Haryana
6.	Sh. Hukam Singh, M.L.A
7.	Sh. Jai Narain. M.L.A
8.	Sh. Sant Kanwar, M.L.A
9.	Sh. Birender Singh, M.L.A

10.	Sh. Ishwar Singh, M.L.A
11.	Sh. Jogi Ram, M.L.A
12.	Sh. Ude Singh Dalal, M.L.A
13.	Sh. Sardar Khan, Deputy Home Minister
14.	Sh. Sakrulla Khan, M.L.A
15.	Sh. Peer Chand, M.L.A
16.	Sh. Ram Pal Singh, Public Works Minister, Haryana
17.	Kr. Vijay Pal Singh Deputy Speaker, Haryana Vidhan Sahba.
18.	Sh. Rajinder Singh M.L.A
19.	Smt. Shanti Rathi, Chief Partiamentary Secretry.
20.	Sh. Har Swrup Bura, M.L.A
21.	Smt. Shakuntla Bhagwaria, M.L.A
22.	Sh. Jagjit Singh Pohloo. M.L.A
23.	Sh Gaya Lal, M.L.A
24.	Sh. Raghu Nath Goel. M.L.A
25.	Sh. Lehri Singh, M.L.A

श्री रघुनाथ गोयलः क्या मुख्य मंत्री जी बताएगे कि जिन विधायको ने तीन साल पहले दरखास्ते दी थी, उनको तक रिवौलवर क्यो नही मिले ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, तीन साल की जिम्मेवारी मै नही लेता । डेढ साल की जिम्मेवारी तो डा0 मंगल सैन की है और डेढ साल की मेरी जिम्मेवारी है । रघुनाथ गोयल जी की ऐप्लीके ान विचारधीन है और बहुत जल्दी ही इनको भास्त्र अलोट कर दिया जाएगा ।(विघ्न)

श्री भाम ोर सिहः अध्यक्ष महोदय, पार्ट (ए) के जवाब मे जो लिस्ट दी गई उसमे तीन चार नाम ऐसे है जिनको दो दो दफा रिवौलवर दिए गए है । एक हरियाणा गवर्नमैंट के सैक्रटरी है, एक मिनिस्टर है और एक एम0एल0ए0 है । मै मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या एक आदमी को दो बार भी रिवौलवर दिया जा सकता है और क्या इसके लिए कोई फर्म रूल्ज वगैरा है जिनके तहत यह अलौटमैंट की जाती है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, एक आदमी को दो भास्त्र भी दिए जा सकते है हो सकता है उन्होने एक बन्दूक ली हो और एक रिवौल्वर लिया हो

श्री अध्यक्षः उन्होने अलौटमैंट के रूल्ज के बारे मे भी पूछा था ।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, रूल यह है कि कोई भी व्यक्ति पांच साल तक असले को बेच नही सकता ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, मै चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या इस मामले मे एम0एल0ए0 की बजाय प्राईवेट आदमियों को भी प्रायरिटी दी जाती है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, एम0एल0ए0 की 6 ऐप्लीके ान्ज पैडिंग है जिसमे पोहलू साहब का नाम भी भाामिल है। इनको भी बहुत जल्दी ही रिवौलवर अलौट कर दिया जाएगा ।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, पार्ट (बी) के जवाब मे उन एम0एल0एज0 की लिस्ट दी गई है जिन्होने फायर–आर्मज के लिए ऐप्लाई किया है । इसमे चौधरी भाग मल जी का नाम है लेकिन जो लिस्ट इन्होने फायर–आर्मज सप्लाई की दी है, उसमे इसका नाम नही है ?

चौधरी भजन लालः सीरियल न0 6 पर इनका नाम है ।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, कई एम0एल0एज0 को मिल गए है। सिर्फ आपको और मुझे ही नही मिला है ।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, कुछ मिनिस्टर्ज को भी फायर–आर्मज दिए गए है। क्या चीफ मिनिस्टर साहब बताने

की कृपा करेंगे कि जो मिनिस्टर्ज बाकी रह गए है उन्हे भी फायर आर्मज दिए जाएगे ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय,जिन को हमने असला (हथियार) अलाट किया है, उसकी सूची पटल पर रखी दी है। चौधरी रिजक राम जी ने सवाल उठाया है कि मंत्रियों की कितना एप्लीके ान पैडिंग है, उनमे एम0एल0एज0 के अलावा श्री मती भाकुन्तला देवी पालियामैन्टरी सैक्रटरी को भी पैडिंग है।

चौधरी जय नारायणः स्पीकर साहब, जिन विधायको को रिवाल्वर अलाट हुए है अगर उनमे किसी का खराब हो गया हो तो क्या उसे चेंज कर देगे ?

चौधरी भजन लालः रघुनाथ गोयल और श्री जय नारायण जी लेने से पहले टैस्ट करके देख ले कि चलने लायक है या नही। लेने के बाद बदलने का तो सवाल ही नही है ।

श्रीमती डा0 कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहती हूं ?कि पिस्टल देने का क्या आइटेरिया है क्या अपनी स्टेट से बाहर के आदमियों को भी देते है ?

चौधरी भजन लालः दे सकत है। इस पर कोई पाबंदी नही है।

श्री बलदेव तायलः क्या मुख्यमंत्री बतायेगे कि हथियार अलाट करने का कोई आईटेरिया या मापदण्ड है ?

श्री अध्यक्षः डिस्कि ान पर है ।

स्वामी आदित्यवे ाः स्पीकर साहब, बहुत से ऐसे विधायक है, जिन को रिवाल्वर एलाट किए गए है। उन से हरियाणा मे भाान्ति भंग होने का खतरा है । क्या उनके लाईसैंस रद्द करवाये जायेंगे ?

श्री हीरा नन्द आर्यः क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि सरकारी कोर्ट से जो असला दिया जाता है, उसकी कीमत फिक्स करने की क्या आईटेरिया है और मार्किट प्राइस मे कितना अन्तर है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, एक कमेटी बनी हुई है जियमे डी0सी0, एस0पी0 और आरमोरर होते है। वह कमेटी कीमत फिक्स करती है । अगर कीमत रिव्यू करने की आव यकता हो तो होम सैक्टरी और आई0जी0 भी देखते है कि आया कमेटी ने कीमत ठीक लगाई या नही ।

Mr. Speaker: Hon, Members, the question hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए ताराकिंत प्र ानो के लिखित उतर

Strikes in industries in the State

***1896 Chaudhri Sant Kanwar:** Will the Chief Minister be pleased to state the number of time the workers, want on strikes in the following Industries during the year 1979-80 together with the number of employees emoved from service in the said Industries, separately.

(i) Atlas Cycle Sonepat;

(ii) B.S.T Gannaur (Sonepat):

(iii) E.C.E Bahalgarh Road Sonepat:

(iv) Good Year Ture, Faridabad;

(v) Escort Tractors, Faridabad; and

(vi) Jindal Pipe, Hissar

सिचाई तथा बिजली मंत्री(चौधरी मेहर सिंह राठी): वाछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है ।

कमसख्या	उधोग का नाम	वर्श 1979 मे श्रमिक जितनी बार हड़ताल पर गए (1—4—49 से 31—3—1980	सेवा मुक्त किये गए श्रमिाकों की संख्या
1	2	3	4

1.	मै0 एटलस साईकिल इण्डस्ट्रीज लि0 सोनीपत	1	भून्य
2.	मै0 बी0एस0टी0, गन्नौर सोनीपत	...	...
3.	मै0 ई0सी0ई0, बहालगढ रोड़ सोनीपत	...	....
4.	मै0 गुडईयर टायर, फरीदाबाद	..	..
5.	मै0 एक्कोर्ट ट्रैक्टर, फरीदाबाद	...	...
6.	मै0 जिन्दल पाईप, हिसार	...	...

Strikes in Faridabad Indusrial Area

***1886. Shri Mool Chand Mangla:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that workers of some industrial units located in the industrial Area at Faridabad went on strike during the period from1-1-1980 to date; if so,

the names of such industrial units together with the reasons for their going on strike; and

(b) the number of working hours lost due to the strikes referred to in part (a) above ?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Mehar Singh Rathee):

(a) yes. The names of the industriat units where the workers went on strikes together with the reasons thereof are shown in the enclosed Annexure.

(b) 252996

[Shi Mehar Singh Rathee]

Annexure

Sr. No.	Name of Industrial Units Where the workers went on strike	Reasons
1	2	3
1.	M/s Tulpar Engineering	Reinstatement of

	(P) Ltd, Faridabad	suspended workers
2.	M/s Tulpar Engineering Tools Co. Faridabad	Reinstatement of suspended workers
3.	M/s High Polyer Labs. LTD Ballabgarh	Reinstatement of suspended workers
4.	M/s Vishal Enterprised (P) LTD, Faridabad	Reinstatement of suspended workers
5.	M/s Endee Woollen & Silk Mills, Fariadbad	Reinstatement of dismissed retrenched workers
6.	M/s Jotindera Steel Tubes (P) Ltd. Fariadbad	Reinstatement of suspended workers
7.	M/s Ahuja Gereral Industries, N.I.T Faridabad	Reinstatement of retrenched workers
8.	M/s Printers House (P) Ltd, Faridabad	Reinstatement of Union President who had been dismissed by the management.
9.	M/s Supreme Engg. Industries (P) Ltd; Faridabad	Demand for increase in wages and Bonus.
10.	M/s Elcan industries Ltd, Faridabad	Reinstatement of terminated workers.

11	M/s Amar Foundry, Faridabad	Reinstatement of terminated workers.
12.	M/s Brake Linning Ltd, Faridabad	Due to lay-off declared by the management.
13.	M/s Intrumentration Ltd; Faridabad	In support of other unions of sister units.
14.	M/s Sikand Plastice Ltd, Faridabad	Increase in D.A and Adhoc Relief.
15.	M/s Indian Alluminium Cables Ltd. Faridabad	Reinstatement of suspended workers
16.	M/s S.J Knititing & weaving Mills Faridabad	Reinstatement of suspended workers.
17.	M/s Clutch Auto (P) Ltd; Faridabad	Reinstatement of suspended workers.
18.	M/s Avery India Ballabgarh	Quarrel between two workers and management called the police.
19.	M/s Remingtion Road of India, Ballabgarh	Reinstatement of suspended workers.
20.	M/s Venue Industries N.I.T Faridabad	Demand for increase in wages.
21.	M/s Delhi Faridabad Texitle (P) Ltd, Faridabad	Reinstatement of suspended workers.

22.	M/s Fabrication and Allied Products Ltd. Faridabd	Demand for increas in wages and bouns.
23.	M/s Hindustan Wires (P) Ltd, Faridabad	Demand for increas in wages and bouns.
24.	M/s Larson and Tourbo Ltd, Faridabad	Demand for increas in wages and D.A
25.	M/s Prestolite of India Ltd, Faridabad	Demand for increas in wages and reinstatement of subpended workers.
26.	M/s Trans Auto D.L.F Faridabad	Reinstatement of retreched workers.

Construction of Sutlej Yamuna Link Canal

***1889. Shri Surender Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to State-

(a) the progress, if any, made by the Government in the construction of carrier channel(S.Y.L Canal) after 31st January, 1980; and

(b) the time by which it is likely to the completed ?

सिचाई तथा बिजली मंत्र चौधरी मेहर सिंह राठीः

(क) कैरियर चैनल एस0वाई0एल0 नहर का कार्य हरियाणा के भाग मे पि चमी यमुना नहर तक पूरा हो चुका है ।

केवल कुछ छोटे टुकड़ो मे कार्य चल रहा है। पजांब की सीमा मे नहर का कार्य अभी तक भारू नही हुआ है ।

(ख) कैरियर चैनल एस0वाई0एल0 नहर के हरियाणा भाग का कार्य 30.6.1981 तक पूरा होने की सभावना है । पजाब के भाग मे नहर के पूरा होने की तिथि वहां पर कार्य भारू होने की तिथि पर निर्भर करती है ।

25 Beld Hosital In Kalanaur

***1915. Chaudhri Jai. Narain:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether sanction has been accorded by the Government to construct 25 Bed Hospital in Kalanaur constituency; and

(b) if so, the time by which the construction work is likly to be started and completed ?

मुख्य मंत्री चौधरी भजन लालः

(क) कालानौर मे एक 25 बिस्तरो का हस्पताल बनान का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, परन्तु अभी तक कोई ओपचारिक मजूंरी जारी नही की गई ।

(ख) निर्माण कार्य कब तक आरम्भ तथा पूर्ण हो जाएगा, यह बताना इस समय कठिन है ।

Supply of Diesel Engines

***1918. Chaudhri Gaya Lal:** Will teh Minister for Cooperation be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of the fact that the dealers sell diesel engines to the farmers to whom loans are issued through cheques by the Land Development Bank at the rates on and half time more than the market price; and

(b) if so, the steps being taken by the Government for preventing this malpractice ?

सहकारिता तथा योजना मंत्री ठाकुर बीर सिंहः

(क) नही।

(ख) प्र न ही पैदा नही होता ।

Posts of Pharmacists in the Health Department

***1914. Shri Mange Ram Gupta:** Will the Chief Minister be pleased to state the total number of the posts of Pharmacists lying vacant in the Health Department together with the details of duties therof ?

मुख्य मंत्री चौधरी भजन लालः इस समय स्वास्थय विभाग मे औशधकारकों के 70 पद रिक्त है औशधकारकी की ड्यूटीज का विवरण निम्न प्रकार है :–

(क) औशधियों का बनाना तथा देना,

(ख) स्टाक रजिस्टर तैयार करना तथा उसका रख रखाव करना,

(गा) आकंड़े तथा रिपोटो को तैयार करना,

(घ) मरणोपरान्त निरीक्षणो तथा चिकित्सा विधि संबधी रिपोर्ट के लिए चिकित्सा अधिकारी को सहायता देना,

(ड़) चिकित्सा अधिकारी द्धारा सूपूर्द किए गए अन्य कर्तव्यो को निभाना ।

Amount incurred for the construction work at Rai in connection with Asian Games

***1917 Chaudhri Rajinder Singh:** Will the Minister for Transport be pleased to state the total expediture so far incurred by the State Government for the construction of building or stadium for Asian Games events at Rai?

परिवहन मंत्री श्री जगननाथः अब तक हुए खर्चे का पूरा ब्यौरा अभी उपलब्ध नही है ।

Report of Judicial Commission for Dabwali Incident

*** 1929 Shri Mool Chand Jain:** Will the Chied Minister be pleased to state-

(a) whether the Judicial Commission appointed to enquire into the charge of rape and murder of Shila Devi at Dabwali, District Sirsa and subsequent firing by the Police has submitted its report; is so, a copy of the report be laid on the Table of the House; and

(b) the action taken or proposed to be taken on the findings of the Commission ?

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लालः

(क) जी हां। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है । यह रिपोर्ट एक उच्च स्तरीय समिति के विचारधीन है जिसके सदस्य मुख्य सचिव, वित आयुक्त गृह और हरियाणा सरकार के विधि परामर्शी है । समिति से अपनी सिफारिशे अति भीध्र देने के लिए कहा गया है । यथा समय रिपोर्ट को विधान सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) उपरोक्त समिति की सिफारिशो के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

वैयक्ति स्पश्टीकरण

Mr. Speaker: Now I will give time for personal explanation to Sh. Devender Sharma and Dr. Mangel Sein. I will give two minutes time to each of them.

(i) सिचाई तथा बिजली उप मंत्री(श्री देवेन्द्र भार्मा):

सिचाई तथा बिजली उप मंत्री(श्री देवेन्द्र भार्मा): स्पीकर साहब, आदरीणय राम लाल वधवा जी ने मेरे खिलाफ कोई बात यंहा पर कही है वैसे तो राम लाल वधवा जी इतने पुराने पार्लियामैटेरियन है, जितनी मरेी उम्र है । उनका लड़का मरे से आगे पड़ता था । ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात कहने से पहले

इनको यह बात सोचनी चाहिए। स्पीकर साहब, मै तो इन्ही से रिक्वैस्ट करूगा कि मेरे नाम से या मेरे किसी भी रि तेदार के नाम से अगर की भी कोई ऐसा गोदाम बना हुहा हो, तो उस पर मेरा कब्जाा करवा दें या मुझे बता दे, मै उसका जा कर कब्जा ले लूंगा । स्पीकर साहब, उनको कुछ कहने से पहले बड़े इत्मीनान के साथ सोचना चाहिये था कि जो बात वे कह रहे है वह ठीक भी है? मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि इस मामले को प्रिविलिज कमेटी मे दिया जाये। स्पीकर साहब, मै तो किसी का नाम नही लेता कि मोम के काटे कहां दिए गए और किस को दिए गए । स्टील के कोट किस को दिएगए मै किसी का नाम नही लेता स्पकीर साहब मेरे उपर पिछली बार भी ऐसा एलीगे ान लगा था । मैने पिछे भी आपसे रिक्वैस्ट की थी, उससे भी मेरा कोई वास्ता नही था । वह मामला प्रिविलिज कमेटी मे नही भेजा । मै आज आप से हाथ जोड़कर कहता हूं कि यह मामला प्रिविलिज कमेटी मे जरूर दिया जाये ओर इसकी असिलियत का पता लगाया जाये ताकि आगे से कोई सदस्य दूसरे एम0एल0ए0 के बारे मे कोई बात करने से पहले जरा उस बात को सोचे ।

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, एक मैम्बर ने बहुत वैलिड प्वायट रेज किया है । मेरी आप से प्रार्थना है कि यह मामला प्रिविलिज कमेटी मे देना चाहिये। नही तो हम मैम्बर खडा हो करके किसी के खिलाफ कुछ भी एलीगे ान लगाता रहेगा ं अगर थोड़ी बहुत इनको सजा नही मिलेगी तो यह प्रथा

गलत पड़ेगी । मेरी आप से प्रार्थना है कि यह मामला प्रिविलिज कमेटी के सुपुर्द किया जाये ।

Mr. Speaker: A request has been made to me to refer this matter to the Committee of Privileges and I have no ground for turning down that request exvept that Sardar Lachman Singh may be very much busy with the work with the Privileges Committee these days. काम उनके पास ज्यादा है वरना मेरे को कोई आब्जैक ान नही है ।

चौधरी राम लाल वधवाः अध्यक्ष महोदय, ये जो कर रहे है कि मैने इलजाम लगाया है, मैने कोई इलजाम नही लगाया (ाोर) अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनिये (ाोर) अध्यक्ष महोदय, मेरी पहले बात सुल लीजिये, फिर आप उस को देख ले। अध्यक्ष महोदय जब क्वै चन आवर था, उसमे मेरे सवाल का जवाब आया । (ाोर) मैने एक सवाल पूछा कि क्या इन लोगो के गोडाउन्ज लिये हुए है या नही? मैने यह नही कहां कि इन लोगो ने लिए हुए है अध्यक्ष महोदय, मेरी बात पहले पूरी सुन ले।(ाोर)

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जो इन्होने कहा वह कार्यवाही मे नोटिस है इन्होने यह कहा कि देवेन्द्र भार्मा के ओर सरदार तारा सिंह के रि तेदारो का गोडाउन्ज है और उसको उन्होने किराये पर ले रखा है ये सारी बाते रिकार्ड पर है । (ाोर)

श्री अध्यक्षः यह मामला रेज हुआ। मै खुद फील करता हूं कि यह बड़ा छोटा सा चार दिन का सै ान हुआ है । इस मे मैने देखा है कि मैम्ब्र्ज, मिनिस्टर्ज और सब के खिलाफ काफी फील without any check or hindrance इलजाम लगाये जाते रहे है मैने अभी रिपोर्टर्ज ने जो एकच्युल वडिंग लिखी है, वह मंगवाई है। अगर उस मे मेरे को ऐसा लगा कि डायरैक्टर इलजाम लगाया है ।और मैम्ब्र्ज चाहते है then i will refer it to the Privilegec Committe (Noise)

(ii) डा0 मगल सैन द्वारा

डा0 मगल सैन द्वाराः स्पीकर साहब, मै अपने पर्सनल एक्सप्लेने ान देना चाहता हूं स्पीकर साहब, बहिन भाान्ति राठी ने मेरे बारे मे जो कुछ कहा था उसके बारे मे मै अपनी पर्सनल एक्सप्लेने ान मे कह राह हूं कि बहिन भाान्ती राठी मेरी बडी आदरणीय बहिन है । मै इनी बहुत कद्र करता हूं (ाोर) स्पीकर साहब, मेरी समझ मे नही आया कि इस चार दिन के छोटे से अधिसवे ान मे .....(ाोर)

डा मंगल सैनः ठीक है जी। मै उन्ही बातो के बारे मे जिकर करूगा । स्पीकर साहब, बहिन जी ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैने औधोगिक प्र ाक्षण संस्थाओ बहुत ज्यादा खुलवा दी थी । मै मानता हू कि जब हम मंत्री परशिद् मे आये तो उससे पहले कांग्रेस सरकार ने इस प्रकार की बहुत सी संस्थाओ खुलवा रखी थी (ाोर) । हमने आने के बाद इनको

चैक किया और अपने अधिकारीयो से इस बारे मे बातचीत की । उन्होने इस बारे मे मेरा ध्यान दिलाया और मैने इसके लिये नियम लागू किया कि 5 या 7 वर्श से जो लोग ट्रेनिग सैन्टर्ज चलाते है उसको मान्यता मिलेगी या जो रिकोगनाईज्ड स्कूल है उनको मान्यता मिलेगी। हमने उस नियम को अच्छी तरह से लागू किया था चौधरी भजल लाल जी के आने के बाद रोहतक जिले का पुराना हिस्सा यानी सोनीपत जिले के अन्दर एक काण्ड भी हुआ था (ाोर) कई व्यक्तियों ने वहां पर इस प्रकार की दुकाने खोली हुई थी बहिन जी इस बात को चैक ले कि जो रूल बनाये गये थे क्योकि मैने उनके खिलाफ कोई काम किया है ।

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग–

रोहतक तथा हिसार के विधार्थियो मे बेचैनी संबधी ।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, रूल 84 के तहत स्टूडेन्ट्स अनरैस्ट के मामले पर मैने एक मो ान दी थी । रूल 84 का जो आईटेरिया है वह लोक सभा के आईटेरिया के भिंत्र है । इस रूल का लोक सभा का आईटेरिया डिफरेंट है और हमार आईटेरिया डिफरेन्ट है । हमारे हरियाणा मे जो रूलज आफ प्रासिजर है वे डिफरेंट किस्म के है मैने 3–4 सफे की एक रिप्रेजेन्टे ान दी थी (ाोर)

Mr. Speaker: That representation has been disallowed.

चौधरी संत कवंरः स्पीकर साहब, मै सरकार से जानना चाहता हूं कि .....

श्री अध्यक्षः आप किस विशय पर बोलने चाहते है ?

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, पिछली बात हाउस के अन्दर सर चौधरी छोटू रम की जयन्ती इस साल 81 के अन्दर मनाये जाने की अ योरेस दी गई थी। मै आपके द्वारा सरकार से यह जानना चाहता हूं कि...

Mr. Speake: Sant kanwar Ji. Please sit down. हाउस के सामने तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई मामला नही आया।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, इस बारे मे हाउस के अन्दर श्री मेहर सिंह राठी जी ने घोशणा की थी । (ाोर)

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, हमने चौधरी छोटू राम की भाताब्दी 9 फरवरी को रोहतक के अन्दर सरकारी तौर पर मनाने का फैसला कर लिया है ।

श्री अध्यक्षः पहले जैन साहब ने जो प्वाइट रेज किया, वह हिसार तथा रोहतक मे स्टूडैन्टस के बारे मे था इनकी तरफ से जो मो ान आई थी वह मैने डिस अलाउ कर दी थी उसके बाद जैने साहब ने मरे को रिव्यू के लिये लिखा था । I agreed to review the matter. Although normally the decision of the Speaker is not reviewed, yet i reviewed the matter. उस मे जैन

साहब ने कई प्वाइट्स लिखे थे लेकिन उसमे कोई फै ाग्राउन्ड नही थी। कौल एण्ड भाकधर की किताब मे लिखा है that strikes, lookouts, fasts and agiation will not normally form the subject matter of such motions. इन बिनाह पर मैने उसको डिसअलाउ कर दिया है।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, स्टूडैन्ट्स को अरैस्ट किया जा रहा है, वे जेलो मे है उनको तंग किया जा रहा है (ाोर) मै चाहता हू कि इस के बारे मे सरकार की तरफ से स्टेटमैंट आनी चाहिए (ाोर) । Government should come forward to make a statement on this matter.

Mr. Speaker: Dr. Sahib, it is upto the Government to come forward to make a statemen or not

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लालः आप लोग अब भाोर मचा रहे है ओर लड़को को बहका कर बसेा को जलवाते है (ाोर) ।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, मैने जो प्वाइंट रेड किया है उसके मुताबिक रूल 84 के तहत मो ान के बारे मे कौल एण्ड भाकधर की बुक मे यह लिखा हुआ है कि लोकसभा मे स्पीकर की प्रायर कन्सैन्ट लेना जरूरी है लेकिन हमारा जो रूल है उसमे प्रायर कन्सैन्ट लेन जरूरी नही है। मैने अपनी रिप्रेजेन्टे ान मे लिखा है कि आपको इनहे रेन्ट पावर्ज है मे आपसे गुजारि ा करता हूं कि आप दोनो रूलो को कम्पेयर कर ले ं लोक सभा के

रूल मे प्रायर कन्सैन्ट जरूरी है लेकिन हमारे विधान सभा के रूल मे प्रायर कन्सैन्ट जरूरी नही है ।

Mr. Speaker: Babu Ji, on the basis of well established parliamentary practice as given in the book by Kaul and Shakdhar, I have disallowed your reptesentation.

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लालः आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर । क्या आपकी रूलिंग आन के बाद उस पर कोई माननीय सदस्य बहस कर सकता है ?

Mr. Speaker: All right that matter is closed now.

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मै भिवानी के अन्दर जो (ाोर)

Mr. Speaker: Hira Nand Arya Ji please sit down. That matter is colsed now

ध्यानाकर्शण सूचनांए

(i) बिड़ला टी0आई0 टी0 के वर्करो की छटंनी की संबधी ।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, भिवानी के अन्दर बिड़ला टी0आई0 टी0 मिल के मजदूरो को निकाल जा रहा है और उनकी परे ाान किया जा रहा है इस संबध मैन एक काल अटैन् ान दी थी (ाोर)

Mr. Speaker: Arya Sahib, please sit down. I have disallowed your call attention motion as the same was regarding strikes, and strikes lock outs, fasts and agitation can not form the basis of a cell attention motion.

(II) **तहसील जगाधरी तथा जमुनानगर जिला अम्बाला आदि मे औलावृष्टि के कारण हुए नुकसान संबधी ।**

श्रीमती डा0 कमला वर्मा: स्पीकर साहब, अभी पीछे पड़ने से तहसील जगाधरी तथ युमनानगर आदि के कई स्थानो की फसले भात प्रति त नश्ट हो गई है । क्या सरकार गरीब किसानों की कोई सहायता करने जा रही है यदि मुख्यमंत्री चाहे तो मै उन गांवो के नाम भी बता सकती हूं । इस संबधं मे जब एस0डी0एम0 साहब से बात करते है तो वे कहते है कि हमारे पास पैसा नही आया मै चाहता हू कि सरकार उनकी सहायता करे ।

Mr. Speaker: I have disallowed that Call Attention Motion on the ground that it was not a matter of recent occurrence. काल अटेन ान मो ान को मन्जूर करने का आडन्ड यह होता है कि it should be a matter of recent occurrence.

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मै माननीय सदस्यो को बताना चाहता हू कि सरकार ने फैसला कर लिया है कि जहां जहांपर फसल ओला वृश्टि से 25 से 50 प्रति ात तक खराब हुई है, वहांपर 200 रूपये, 50 प्रति ात से 75 प्रति ात तक जंहा पर खराब हुई है वहां पर 300 रूपये और जहां पर 75

प्रति ात से ज्यादा फसल नश्ट हुई है वहा पर 400 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानो को सहायता दी जायेगी ।

वैयक्तिक स्पश्टीकरण–

चौधरी गंगा राम द्धारा

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, अखबार मे 5 अन्धो के बारे मे जिक्र आया है पता नही सरकार ने उन्हे मार दिया है या उन्हे लाठियो से पीटा गया .....(ाोर)

श्री अध्यक्षः क्या आपने लिख कर दिया है ?.....(ाोर)

11.00 बजे

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल अध्यक्ष महोदय, जहां तक अन्धो या लंगडो का ताल्लुक है आपको याद होगा परसों उनका एक डैपुटे ान मुझे मिला था और मेरे से वे सारी बात करके चले गये ं हमने उनको यह वि वा ा दिलाया था कि उनकी सारी मांगो पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मैने उनको चाय भी पिलाई और सार बातचीत की । बाकायदा वे इस बात के लिये राजी होकर चले गये कि हम जाते ही अपनी एजीटे ान समाप्त कर देंगे । कुछ हमारे माननीय सदस्य जिनमे चौधरी गंगा राम जी भी भाामिल है, उन्होने वहां पर जाकर उनको बहकाया । (व्यवधान एवम भाोर) आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिये । उन्होने मुझे कल भाम को.....

Shri. Verebder Singh: Is he on a point of order, Sir ?

Mr. Speaker: That motion has been disallowed.(Interruptions & noise)

Shri Verender Singh: This is not a point of order.

चौधरी गंगा रामः पर्सनल एक्सप्लेने ान, सर ।स्पीकर साहब अभी मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा कि गंगा राम उनको बरगलाने लग रहे है, उनको लाकर यहां पर डिमान्स्ट्रें ान करवा रहा है । उन्होने यह भी कहा कि अन्धो ने इन्हे यह कहा कि हम एजीटे ान वापिस ले लेगे, यह बिल्कुल सदन को गुमराह कर रहे है । उनको तो अब तक भी पुलिस वालो के साथ लठम–लठ हो रहा है । (व्यवधान एवम भाोर)

श्री अध्यक्षः आप ऐसे कहिये कि उन्होने यह कहा है कि आपने उनको गुंमराह किया है लेकिन आपने नही किया है (विघ्न) आप अपनी पर्सनल एक्सप्लेने ान दीजिये । (व्यवधान एवम भाोर)

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, अगर हरियाणा के अन्धो के साथ कोई ज्यायदी होती है तो उनको न्याय दिलाने के लिये आवाज उठाते हर एम0एल0ए0 का और मेरा फर्ज है । हम हरियाणा के किसी भी इननोसेंट आदमी के ऊपर लाठी नही चलने देंगे। स्पीकर साहब, मेरी आपसे यही रिक्वैस्ट है (व्यवधान एवम भाोर)

श्री अध्यक्षः आपकी पर्सनल एक्सप्लेने ान हो गयी, अब आप बैठ जाइए । (व्यवधान एवम भाोर)

ध्यानाकर्शण सूचनाए (पुनरारम्भ)

(iii) **हरियाणा डेरी विकास विभाग के कर्मचारियों मे भारी असंतोश संबधी ।**

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, मै आपसे यह कहना चाहता हूं कि एक डेरी डिवैल्पमेट का एम्पलाई 9 दिन से रोहतक मे मरणव्रत पर बैठा है और डिपरर्टमेंट की सारी डेरीज मे हड़ताल चल रही है ।

श्री अध्यक्षः क्या आप ने इसका नोटिस दिया हुआ है?

डा मंगल सैनः मै यह चाहता हूं कि गवर्नमैंट इस बारे मे जवाब दे ।

Mr. Speaker: Without notice I will not allow it to be raised.

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पकीर साहब, मैने तो नोटिस दिया हुआ है । मेरी डिवैल्पमैंट विभाग के संबध मे मैने एक काल अटेन ान मो ान दिया था । उस बारे मे सरकार को आप यह कहे कि वह इसका जवाब दे । दो महिने से वहां पर कर्मचारियों के काफी असतोंश है । (व्यवधान एवम भाोर)

Mr. Speaker: That has been disallowed.

(IV) **हरियाणा के अकाल प्रभावित श्रेत्रो मे कर्जे माफ करने तथा बिजली व पानी की सप्लाई की वि ोश व्यवस्था करने संबंधी ।**

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, महेन्द्रगढ और भिवानी जिले मे जबरदस्त कहत पड़ा हुहा है, मैने उसके बारे मे एक काल अटेन ान मो ान दी थी । सरकार को इस बारे मे कोई न कोई ब्यान देना चाहिए। (व्यवधान एवम भाोर) अध्यक्ष महोदय, भिवानी जिले मे खास कर लोहारू तहसील मे भात प्रति ात फसल खराब हो गयी है । लेकिन किसानों को कुछ राहत देने के लिये सरकार ने कोई कदम नही उठाया है । मै यह चाहता हू कि सरकार वहां पर बिजली और पानी अधिक से अधिक दे तथा वहां पर दूसरे राहत कार्य भी भाुरू करे ताकि वहां के लोगो जो भूखे मर रहे है उनका गुजारा हो सके । इसके अलावा सरकार इस और भी ध्यान दे कि वहां पर जो टयूबवैल्ज कनैक ानज के के लिए एप्लीके ान्ज पैडिंग पड़ी है और सामान नही मिल रहा है, वहां पर सरकार को सामान मुहैया करवाना चाहिये । वहां की जनता त्राही त्राही कर रही है (व्यवधान एवम भाोर)

श्री अध्यक्ष: आप किस विशय पर बोल रहे है?

श्री हीरा नन्द आर्य: सर, मैने इस विशय मे एक काल अटैन ान मो ान दिया था ।

श्री अध्यक्षः अब तक आप 6 विशय मैन् ान कर चुके है (व्यवधान एवम भाोर)

श्री हीरा नन्द आर्यः सर, मै जो भिवानी और महेन्द्रगढ जिले के इलाके मे जबरदस्त कहत पड़ा हुआ है, उस बारे मे बोल रहा हूं इस बारे मे अब तक कोई भी कार्यवाही नही की गई है । सरकार को आप कहें कि वह कोई स्टेटमेंट दे ।

श्री अध्यक्षः वह काल अटैन् ान मो ान तो मै एडमिट कर चुका हूं लेकिन .....(व्यवधान एवम भाोर)

श्री सुरेन्द्रः स्पीकर साहब, भिवानी और महेन्द्रगढ जिलों मे कहत के बारे मे मै भी यह चाहता हूं कि सरकार ध्यान दे ।

श्री अध्यक्षः जो काल अटैन् ान मो ान कहतजदा इलाको के सबंध मे था वह तो मेने एडमिट कर लिया है but due to lack of time i can not bring it before House that necessary steps would be taken.

Shri Surender Singh: Let the Chief Minister assure this august House that necessary steps would be taken.

(At this storge the Chief Minister, Chaudhri Bhajan Lal, rose to speak)

Mr. Speaker: Chaudhri Sahib, I Will give you time lateron. Please take your seat.

(V) **गन्ने की कीमत बढाने संबंधी।**

श्री अध्यक्षः जैटलमैन, मुझे श्री सतबीर सिंह मलिक और श्री हीरा नन्द आर्य एम0एल0एज0 की तरफ से भाूगरकेन की स्टेट गवर्नमैंट द्वारा कम कीमत फीक्स किये जाने के बारे मे एक काल अटैन्शन नोटिस प्राप्त हुआ है । मै इसको मन्जूर करता हूं । आनरेबल मैम्बर अपना नोटिस पढ दे । .....(व्यवधान एवम भाोर)

Shrimati Sushma Swaraj: I want to draw your attention, sir

Mr. Speaker: On what subject are you speakin?

Shrimati Sushma Swaraj: ----------

Mr. Speaker: Nothing will be recorded which i have not permitted.

Chauhri Satvir Singh Malik: I want to draw the attention of the House towards a matter of urgent improtance that teh sugarcance price of Rs. 20/-

चौधरी रिजक रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सुर । स्पीकर साहब, क्वैचन नम्बर 1885 पर आपने यह फरमाया था कि आधे घंटे की डिस्कशन होगी । क्या उसके लिये आज टाइम मिलेगा या नही ?

श्री अध्यक्षः जरूर मिलेगा ।

I think, it is better if you start reading your motion again.

Chaudhri Satvir Singh Malik: I want to draw the attention of the House towards a matter of urgent importance that the sugar cane price of Rs. 20/- fixed by the State Government is not enough remunetative and on this account the sugar cne growers are agitating aganst the low price and not suppling sugar cnae to the mills. The cost of Sugar is high and according to this, the sugan cane price should be enhaced upto Rs. 30/- All the sugar mills in the State are not running according to hteri capecity and are running in losses. There is qcute shortage of Sugar in the Country and due to this shorage, the people have not got theri quota of November and December. in view of the above focts, this matter is of public importance and require immediate attention of this August House.

वक्तव्य––

कृशि मंत्री द्धारा उस उक्त ध्यानकर्शण सूचना संबंधी ।

श्री अध्यक्षः अब मंत्री महोदय, इस काल अटैन ान मो ान पर अपनी स्टेटमैंट देंगे।

कृशि मंत्री सरदार तारा सिंहः विभिन्त्र राज्यो मे चीनी मिलो द्धारा गन्ना उत्पादाको को दिये जाने वाले गन्ने का मूलय भारत सरकार गन्ना नियन्त्रण आदे ा, 1966 के अन्तर्गत नियत करती है। यह न्यूनतम संविदा मूल्य है जो कि किसी भी किस्म व जाति के लिये दिया जाता है किन्तु गन्ने से अधिक चीनी की प्राप्ति के आधार पर इससे अधिक मूल्य भी दिया जा जाता है जो कि गन्ने की किस्म की विभित्रता तथा विभित्र चीनी मिलो की

अपनी परिस्थितियों पर निर्भर है । राज्य सरकार चीनी मिलों द्वारा दिये जाने वाले गन्ने का मूल्य नियत नही करती किन्तु राज्य के गन्ना उत्पादको के हितों को ध्यान मे रखते हुये राज्य सरकार राज्य की पांच चीनी मिलो (रोहतक, सोनीपत,पानीपत, करनाल व यमुनानगर) को पिछले कुछ वर्शा से अधिक मूल्य देने के लिये प्रेरित करती रही है

इस वर्श उत्पादन लागत के बढ जाने के कारण तथा खाद के भाव वि ोशकर बढ जाने के कारण राज्य सरकार ने चीनी मिलों को आज तक दिये गये गत्रे के मूल्य से ज्यादा मूल्य देने के लिये प्रेरित किया है । इस प्रकार भारत सरकार द्वारा चीनी की 8.5 प्रति ात की प्राप्ति पर 13 रूपये प्रति क्विटंल की दर से संविदा मूल्य नियत किया परन्तु मिल 20 रूपये प्रति क्विटंल की दर से गन्ने के मूल्य का भूगतान कर रही है। राज्य सरकार इस मूल्य को बहुत ही लाभदायक मूल्य समझती है। गन्ना उत्पादक भी इस्र लाभदायक मूल्य समझते है इससे स्पश्ट हो जाता है कि अधिकतम चीनी मिलो से गन्ना पेलने का कार्य नवम्बर, 1980 के अन्तिम सप्ताह मे निर्धारित समय से भी पहले आरम्भ कर दिया है चीनी मिलों को गन्नो की सप्लाई संतोशनजनक है राज्य सरकार को कुछ सूचनाए प्राप्त हर्इ है कि कुछ राजनीति से प्रेरित आन्दोलन रोहतक चीनी मिल क्षेत्र मे चलाने की कोि ा ा की गई है जिसके कारण इस चीनी मिल को गन्ना पेलने का कार्य कुछ देरी से भाुरू करना पड़ा । मुंझे सदस्यो को यह सूचना देते हुये

हर्श हो रहा है कि रोहतक चीनी मिल ने भी दिनांक 16.12.1980 को गन्ना पेलने का कार्य आरम्भ कर दिया है तथा इस मिल मे भी गन्ने की बहुत अधिक कमी होने की आ ांका नही है ।

राज्य सरकार को इस बात की जानकारी है कि गन्ना उत्पादको को वर्श प्रति वर्श मूल्यो के उतार चढाव का गभीरता के सामना करना पड़ता है । यह समस्या उन गन्ना उत्पादकों के लिए है जो कि कुल सख्या का 4/5 भाग है जो अपना गन्ना चीनी मिल क्षेत्रो से बाहर गुड तथा खांडसारी बनाने वाली इकाइयों मे देते है इस विशय के वि लेशण से पता लगता है कि दो ऐसे प्राथमिक कारण है जिन पर राज्य सरकार का बहुत अधिक नियत्रण प्रतीत नही होता । यह कारण है कि गन्ना के अधीन क्षेत्र तथा उत्पादन मे भारी उतार चढाव तथा गुड खाडसारी के भावों मे अस्थिरता । इन दोनो कारणो से केवल गन्ना उत्पादको को सकंट के वर्शा मे ही हानि नही होती बल्कि चीनी मिलों को भी अधिक उत्पादन के वर्शो मे भारी हानि का सामना करना पड़ता है जिसके लिए राज्य सरकार को उनकी सहायता करनी पड़ती है ।

हरियाणा राज्य मे वर्श प्रति वर्श गन्ने के अधीन क्षेत्र तथा उत्पादन मे जो उतार चढाव रहे है जिसके मुख्य कारण चीनी मिल क्षेत्रो तथा उसके बाहर गुड़, खाडसारी तथा चीनी के भाव भी अस्थिर रहे है जो कि किसानो को इस फसल के अधीन क्षेत्र बढाने तथा घटाने के लिये प्रोसाहित करते रहे । हरियाणा राज्य के अस्तित्व मे आने के प चात् गन्ने के अधीन क्षेत्र 1.14 से

1.97 लाख हेक्टेयर तथा उत्पादक 51.40 से 89.70 लाख टन रहा । वर्श 1977–78 मे गन्ने के अधीन क्षेत्र 1.97 लाख हेक्टेयर व उत्पादन 89.70 लाख टन था किन्तु इस वर्श मे गुड़, खांडसारी व चीनी के भाव बहुत ही निम्न स्तर पर रहे । गुड़ का भाव नवम्बर से मार्च तक 85 रूपये प्रति क्विटंल जबकि खांडसारी के भाव 250 रूपये प्रति क्विटंल और चीनी का भाव 325 रू0 390 रूपये प्रति क्विंटल इस समय मे रहा । इस तरह वर्श 1978–79 मे जिस समय गुड़ का भाव 64 रूपये 124 रूपये प्रति क्विटंल था उस समय खांडसारी का भाव 170 रूपये से 182 रूपये प्रति क्विटल तथा चीनी का भाव 215 रूपये प्रति क्विटंल से 235 रू0 प्रति क्विटलं था । इस कम कीमतों का प्रतिकूल असर पड़ा तथा 1979–80 मे गन्ने के अधीन क्षेत्र कम होकर 1.27 लाख हैक्टेयर तथा उत्पादन 39.50 लाख टन रहा गया । वर्श 1977–78 मे गन्ने की अधिकता के कारण चीनी मिले सारा गन्ना नही पेल सकी और खाडसारी यूनिट भी बहुत कम मूल्य दे रहे थे इसके प चात् भी चीनी मिलो ने 25.5.1978 तक किसानो को गन्ने का मूल्य 13.50 प्रति क्विटंल की दर से दिया और सीजन मे देर तक गन्ना पेलकर मूल्य 10 रूपये प्रति क्विंटल दिया तो भी गन्ने के अधीन क्षेत्र तथा उत्पादन कम हो गया इस वर्श चीनी मिल क्षेत्रो मे कुछ गन्ने की मात्रा खेतो मे ही खडी रही तथा चीनी मिलो को इस आगामी वर्श मे पेलने के लिये कहा गया।

वर्श 1977–78 मे चीनी मिलों ने अपनी 16.80 लाख टन से क्षमता के विरूद्ध 18.0 लाख टन गन्ना पेला । वर्श 1978–79 मे भी जबकि गन्ने का उत्पादन 89.70 लाख टन से घटकर 68.90 लाख टन रह गया तो भी चीनी मिलों मे 15.30 लाख टन गन्ना पेला ।

वर्श 1978–79 मे चीनी मिलो ने गन्ने का मूल्य 12.50 रूपये प्रति क्विटंल की दस से दिया जब कि राज्य की चीनी मिलों के लिए नियत न्यूनतम सविंदा मूल्य 10 रूपये से 11.18 रूपये प्रति क्विटंल नियत किया गया था । चीनी का कम मूल्य तथा गन्ने से चीनी की कम प्राप्ति के कारण चीनी मिलो को भारी हानि होने की आं ाका थी और इस कारण वह न्यूनतम सविंदा मूल्य से अधिक मूल्य देने के लिये सहमत नही हो रहे थे राज्य सरकार ने न्यूनतम संविदा मूल्य 12.50 रू0 प्रति क्विटंल के अन्तर का स्वय सहन किया । राज्य सरकार ने 1978–79 मे इस प्रकार 1.76 करोड़ रूपये दिये । 1979–80 मे गन्ने के अधीन क्षेत्र 1.27 लाख हैक्टेयर था तो यह कमी दे ाव्यापी था भारत सरकार ने न्यून्तम संविदा मूल्य 12.50 रूपये प्रति क्विटंल की दर से नियत किया । हरियाणा राज्य ने चीनी मिलों की और से दिया जाने वाला मूल्य 12.65 रूपये से 13.53 रूपये प्रति क्विंवटल था फिर भी राज्य सरकार ने चीनी मिलों को वह मूल्य 14 रूपये प्रति क्विंवटल की दस से देने के लिये कहा किन्तु भारी हानि की संभावनाओ के कारण चीनी मिले चह मूल्य देने के लिए सहमत नही हो रही थी क्योंकि

अक्टूबर, नवम्बर 1979 मे खुले बाजार मे चीनी 300 रूपये प्रति क्विंटल का भाव था । इसलिए राज्य सरकार के न्यूनतम संविदा मे मूल्य 14 रूपये प्रति क्विटंल का अन्तर स्वय सहन किया इस पर 1.73 करोड़ रूपये खर्च हुए किन्तु मिले 1979–80 मे केवल 9.75 लाख टन गन्ना ही पेल सकी । राज्य मे गन्ने का उत्पादन 68.90 लाख टन से घट कर 39.50 लाख टन हो गया। चालू वर्श मे गन्ने के अधीन क्षेत्र तथा उत्पादक मे कोई वि ोश संतोशजनक वृद्धि नही हुई ।

राज्य सरका यह महसूस करती है कि वर्श प्रति वर्श रहने वाले मूल्यों को गन्ने के मूल्य प्रतिदान का आधार नही माना जा सकता । राज्य सरकार उत्पादन लागत को सही आधार प्रतिदान का आधार नही माना जा सकता । राज्य सरकार उत्पादन लागत को सही आधार मानती है । कृशि विभाग द्वारा गन्ने की नौलफ फसल के लिए उत्पादन लागत 16.44 रूपये हरियाणा कृशि वि ववविधालय द्वारा 12.05 रूपये प्रति क्विटंल आकी गई है हरियाणा कृशि वि ववविधालय द्वारा पेडी गन्ने की उत्पादन लागत 10.33 रूपये प्रति क्विटंल आकी गई है इस वर्श गन्ने के कुल क्षेत्र का लगभग 50 प्रति त नौलफ तथा 50 प्रति त पेड़ी फसल के अधीन है यदि कृशि विभाग द्वारा आकी गई उत्पादन लागत को मान लिया जाए और उसमे 10 प्रति त एवम प्रबन्ध के खर्चे जोड़ दिये जाये तो भी उत्पादन लागल 18.08 रूपये प्रति क्विंटल बनती है और चीनी मिलों को इसके अधिक 20 रूपये प्रति क्विटल गन्ने

का मुल्य देने के लिये सहमत किया गया है जो कि बहुत ही उचित है ।

तुलना के लिए चीनी मिलों द्वारा दिया गय मूल्य न्यूनतम चीनी मिलो द्वारा दिया जाने वाला न्यूनतम मूल्य जो कि भारत सरकार द्वारा 8.5 प्रति चीनी की प्राप्ति पर निर्धारित किया जाता है कृशि विभाग द्वारा अंाकी गई उत्पादन लागत जो कि हरियाणा कृशि वि ववविधालय द्वारा आकी गई लागत से अधिक है और नौलफ फसल के लिए ली गई है जबकि पेडी की लागत सदैव कम होती है नीचे दी जाती है :–

वर्श	मिलो द्वारा दिया जाने वाला न्यूनतम मूल्य	मिलों द्वारा साधरण सीजन मे दिया गया गन्ने का मूल्य	कृशि विभाग द्वारा आकी गई उत्पादन लागत	कृशि विभाग द्वारा आकी गई 10 प्रति त आपात एवम प्रबन्ध खर्चो सहित उत्पादन लागत

	रूपयो मे	रूपयो मे	रूपयो मे	रूपयो मे
1977.78	13.50 से 19.80	13.50	9.42	10.36
1978.79	10.00 से 11.18	12.50	9.84	10.82
1979.80	12.50 से 13.53	14.00	12.96	14.25
1980.81	13.76 सें 14.68	20.00	16.44	18.08

यह भी बताया जाता है कि चीनी मिलो को यह अधिक मूल्य देने के कारण काफी हानि होती है जबकि राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदान की रा ि ा इसके अतिरिक्त है सहकारी चीनी मिलों से एकत्रित किए गए पेले गए गन्ने की मात्रा, उत्पादित चीनी तथा हानि के आकड़े निम्न प्रकार से है:–

चीनी मिल का नाम	1977.78	1978.79	1979.80	1980.81
पानीपत.	125.64	74.23	70.67	17.48
रोहतक	94.38	19.27	45.08	13.18

करनाल	126.26	155.05	53.44	54.38
सोनीपत	225.09	116.07	103.23	88.67

उपरोक्त से यह विदित होता है कि जिन वर्शो मे मिलों ने गन्ने का मूल्य 12.50 रूपये से 14 रूपये प्रति क्विंटल दिया है उन वर्शा मे उन्हे भारी हानी हुई है। चालू वर्श मे गन्ने का मूल्य 20 रू0 प्रति क्विटंल की दर से देने पर चीनी मिले और हानि की संभावनाएं किए हुए है जबकि इस बारचीनी के भाव अच्छे होने के कारण हानि का अनुमान कुछ कम है। चीनी का मूल्य नवम्बर मे 960 रूपये प्रति क्विटंल था जो कि अब 750 रूपये प्रति क्विटल रह गया है । जैसे ही मूल्य मे कमी होगी मिलों की हानि बढने की संभावना है इस प्रकार अधिक स्थिति विपरीत हो जाती है और जितना अधिक गन्ना पेला जाएगा उतनी अधिक हानि होगी । चालू वर्श मे 12 लाख टन गन्ना पेलने का अनुमान है पिछले वर्श 9.77 लाख टन गन्ना पेला गया था पिछले वर्श की अपेक्षा इस वर्श गन्ने से चीनी की प्राप्ति कम है और इसके कारण भी चीनी मिलों को अधिक हानि अपेक्षित है इस प्रकार गन्ने के मूल्य मे वृद्धि से आकर्शण की बजाए स्थिति और बिगड़ेगी।

उपरोक्त तथ्यो से यह ज्ञात होता है कि किसानो को दिया जा रहा 20 रूपये प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य लाभप्रद, उचित व उत्पादन लागत से अधिक है अत यह प्रस्ताव रद्द किया जाए ।

इसके अलावा स्पीकर साहब, मै यहां हाउस मे एक बात और बताना चाहता हूं कि सोनीपत और रोहतक के अन्दर कुछ लोकदल के भाईयो ने यह कोि ा ा की कि ये सभी मिलें बन्द रहे। (ाोर) इन्होने वहां पर बिरादरीबाद का नारा भी लगाया । इन्होने कहा कि अगर ये मिलें चल गयी तो हमार मुंह काला हो जायेगा ।स्पीकर साहब, ये लोग अपनी कोि ा ाो मे बुरी तरह से फेल हुए । इन्होने चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर के नारा लगाया । (ाोर) स्पीकर साहब, मै सारे हाउस को दावे के साथ बताना चाहता हूं कि पांचो की पांचो मिले अपनी पूरी कपेसिटी के साथ चल रही है यह हम सब के लिए खु ाी की बात है और इनकी पार्टी की यह पूरी तरह से हारा है, नाकामी है, ये माने या न माने (ाोर)

चौधरी गंगा रामः .....

चौधरी संत कंवरः.....

सरदार तारा सिंहः.....

श्री अध्यक्षः यह रिकार्ड न किया जाए ।

श्री हीरा नन्द भार्माः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया है कि यदि गन्ने की निर्धारित की गयी कीमत मे 10 प्रति त खर्चा आपात एवम प्रबन्ध करने बगैर रह का जोड़ा जाए, तो भी वह 18.08 रूपये प्रति क्विटंल बनता है । लेकिन मै उनको बताना चाहता हूं कि अगर गन्ने की कटाई, छटाई और कैरिज वर्ग

रह का खर्चा जोड़ा जाए तो वह किसी हिसाब से 25 रूपये प्रति क्विंटल से कम नही बैठता । हमारे पडौसी पंजाब वालो ने गन्ने का भाव 29 रूपये प्रति क्विंटल तक तय किया है और इसी तरह यू0पी0 वालो ने भी 22 रूपये प्रति क्विटल गन्ने का भाव निि चत किया है जबकि हरियाणा मे गन्ने की रिकवरी उन से कम नही है बल्कि कुछ ज्यादा ही होगी। इसलिए मै मंत्री महोदय जी से कहूंगा कि कम से कम 30 रूपये प्रति क्विंटल का भव तय किया जाना चाहिये। इसके अलावा स्पीकर साहब, मै एक बात और बताना चाहता हू कि हमरे रोहतक के भागर मिल की मैनेजमेंट से भी बात की है। उन्होने यह एउमिट किया है कि अगर सरकार ज्यादा दे तो हमे भी किसान को उसके भाव 25 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देने कोई एतराज नही है । मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार को ऐसा करने मे क्या एतारज है? अगर सरकार किसानों की भाुभचिन्तक बनी हे तो कम से कम गन्ने का भाव जैसा कि मैने कहा 30 या 35 रूपये तय किया जाना चाहिये । वरना यह सरकार किसानो को अपना मुह नही दिखा सकती और जो इन्होने लोक दल पर इल्जाम लगाया है, वह सरासर बेसलैस है ।

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, मुझे एक बात कहने मे कोई दिक्कत नही है कि मेरे फाजिल दोस्त खुद कन्फयूज्ड है । ये कभी 30 कहते है और कभी 35 कहते है इन्होने सोनीपत और रोहतक मे जाकर किसानों और जमीदारो को बरगलाया कि

असैम्बली बैठने से पहले 30 रूपये भव करवा कर छोडेगे । उन लोगो ने इनकी एक बात भी नही मानी और रोहतक, सोनीपत, और पानीपत के किसानों ने खुला गन्ना देना भुरू कर दिया ।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, सवाल तो यह है कि पजांब ओर यू0पी0 वालो ने कीमत बढा दी है, ये क्यों नही बढा रहे है। मंत्री महोदय और बात कहने की बजाय सवाल का जवाब दे।

सरदार तारा सिंहः मै इनसे कहना चाहता हूं कि ये चार्ट उठा कर देख ले । यू0पी0 के कम्पेरिजन मे हरियाणा का भाव एक दो रूपये हमे ाा नीचे रहा है । हरियाणा की रिकवरी यू0पी0 और पंजाब से कम रही है । भजन लाल सरकार किसानो के हित की सरकार है अगर कोई भी आदमी किसान हित की बात करता है तो हम उसे पूरी करते है लेकिन इनके बहकाने से हम कुछ करने वाले नही है। सबसे पहले हमने 20 रूपये का भाव मुकर्रर किया था।

चौधरी सतबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, इसी सबंध मे मैने एक एडजर्नमैंट मो ान दिया था लेकिन आपने उसको काल अटेन्ा ान मो ान मे तबदील करने मंजूर किया है यह बड़ा जरूरी मामला है और आज किसान गन्नो के भाव से संतुश्ट नही है। आपने मेरे एउजर्नमैंट मो ान को काल अटैन्ा ान मो ान मे तबदील तो जरूर कर दिया लेकिन इस पर हम दो चार सवाल ही

पूछ सकेगे, जिन से बात नही बनेगी। हमारे मुख्य मंत्री जी के पास गन्ने का भाव जांचने का समय नही है। क्योंकि इनके पास और कई धन्धे है ये उनमे ही लगे रहते है । अध्यक्ष महोदय, मै चौधरी भजन लाल जी को एक बात बताना चाहता हूं कि हरियाणा मे किसी भी मिल मे जब क्रि ांग की भाुरूआत होती है तो 8 प्रति त से कम रिकवरी नही पड़ती बल्कि 8 प्रति त से 12 प्रति त तक रहती है। मै पानीपत भाूगर मिल का डायरेक्टर रहा हूं इसलिये मुझे वहां की तथा दूसरे मिलों की रिकवरी का पता है वहां 8 से 12 प्रति त तक रिकवरी चलती है । अगर हम 8 प्रति त या 9 प्रति त भी मान करचले तो उसके हिसाब से एक क्विंटल पर 72 रूपया आता है इसलिये सरदार तार सिंह यह गलत कह रहे है कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने जो 16.40 रूपये का भाव रिकमैंड किया था, वह ठीक था । अगर ये 30 रूपये प्रति क्विंटल का भाव कर दे तब भी मिल को 30–40 रूपये एक क्विटल के पीछे फायदा होता है यानी अगर 8 प्रति त भी रिकवरी हो तब भी मिल को 30 रूपये क्विंटल बचता है । इसलिये किसान को हमारे से कम भाव होता था लेकिन अब पजांब मे किसान का बेटा राज करता है इसलिये उसने गन्ने का भाव 23 रूपये से 29 रूपये तक कर दिया है लेकिन दुख की बात यह है कि सर छोटू राम के साथ जिनके पिता ने काम किया हो और उनका बेटा यह कहे कि 20 रूपये का भाव देकर हम किसान के साथ न्याय कर रहे है । चौधरी भजन लाल से किसान को हमदर्दी की उम्मीद

नही कि जा सकती है । मै चाहता हूं कि साथ कि स्टेट्स को देखते हुए गन्ने का भाव 30 रूपये क्विंटल किया जाए ।

सरदार तार सिंहः स्पीकर साहब, अभी सतबीर सिंह जी ने अपनी बात कहते हुए बडा सैटीमैंट प्रकट किया है मै मानता हू कि मेरे फादर चौधरी छोटू राम जी के खास वर्कर गिने जाते रहे है । ओर उस खून का असर मेरे मे भी है । मै आज भी सदन मे कह सकता हूं कि चौधरी सतबीर सिंह से ज्यादा किसानो के साथ हमदर्दी मेरी है। यह चार्ट इस बात का गवाह है कि हमने कितनी कितनी बढाई है हम प्रो किसान आदमी है और प्रो किसान ही रहेंगे । एक बात इन्होने और कही कि किसान की उपज का भाव जांचने के लिए चीफ मिनिस्टर के पास टाइम नही कहनी चाहिए ।अगर कोई अनपढ आदमी ऐसी बात कर देता तो मै मान सकता था। हम जो करोड़ो रूपया एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पर खर्च कर रहे है, यह केवल किसान की भलाई के लिये ही कर रहे है । उस यूनिवसिर्टी का वाईस चांसलर भी किसान का ही बेटा है । उसने हमे 16 रूपये का भाव तय करके भेजा है औय यह स्टीफाइड भाव है । लेकिन हमने सोचा कि इस भाव से किसान का नुकसान होगा इसलिये हमने 16 की बजाए 20 रूपये किया।

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । यह जो कृशि वि ववविधालय द्धारा भाव तय किया गया है क्या यह किसान की साली लागत को लगा कर तय किया गया

है ? मेरे पूछने का मतलब यह है कि क्या इस भाव मे किसान के सारे खर्चे भाामिल किये गये है या नही ?

सरदार तार सिंहः मेरा ख्याल है कि अगर स्वामी जी यह सवाल न पूछने तो बेहतर था । इनको पता होना चाहिए कि जो भाव तय किया गया जाता है। वह किसान के सारे खर्चे को जोड़ कर ही तय किया जाता है । जब भी किसी चीज का, जिसे किसान पैदा करता है, भाव तय किया जाता है तो उसमे सारे खर्चे भाामिल करके किया जाता है । स्वामी जी ने यह सवाल तो पूछ लिया लेकिन उनको इस बारे मे कुछ पता नही है ।

परीवहन मंत्री श्री जगननाथः स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है । स्वामी जी बार बार किसानों की बात करते है, मजदुरों की नही करते । एक स्वामी जी इधर उधर बैठे है अगर सारा दे ा स्वामियों का बन जाउ तो उनको कमा कर कौन खिलाएगा ?(हंसी)

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, जैसे आपने इनको इजाजत दी है, उसी तरह मुझे भी एक सवाल पूछने की इजाजत दी जाए । वैसे मैने रूल 84 के तहत भाूगर केन प्राइस के बारे मे एक मो ान दी थी जिसे आपने रिजैक्ट कर दिया है। मै इस बहस मे नही पडना चाहता । मै सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि पजांब मे, यू0पी0 मे और अध्यक्ष मे और मध्य प्रदे ा मे जहां

काग्रेस की सरकारे है उन्होने गन्ने की कीमत ज्यादा बढाई है तो क्या ये भी रिकवरी को कम्पेयर करके कीमत बढाने की सोचेंगे या नही ?

सरदार तारा सिंहः हम डाटा इकट्ठा करवा रहे है उसको देख कर अगर कीमते बढानी जरूरी हुई, तो जरूर बढाएंगे ।

वाक आउट

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, यह सरकार कुछ नही समझ पाएगी । यह किसान विरोधी सरकार है ं यह किसान को तबाह करना चाहिए ं(ाोर एवम विघ्न) यदि यह सरकार किसानो के गन्ने का भाव नही बढा सकती है तो हम एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करते है ं(ाोर एवम विघ्न)

(इस समय लोकदल के सभी सदस्य से वाक आउट कर गए)

वैयक्ति स्पश्टीकरण

मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल द्धारा

मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल द्धाराः अध्यक्ष महोदय, माननीय चौधरी सतबीर सिंह मलिक ने यह कहा कि भजन लाल किसान नही है । अध्यक्ष महोदय, मै इनसे ज्यादा बड़ा किसान हूं । जितनी जमीन इनके बाप दादा के पास थी उससे ज्यादा जमीन

मेरे पास आज है ये किस मुह से कहते कि भजन लाल किसान नही है। अध्यक्ष महोदय आज की काग्रेस की सरकार ने जितना कुछ किसानो के लिये किया है उतना आज तक किसी सरकार ने नही किया है (ाोर एवम विघ्न) अध्यक्ष महोदय मै एक मिनट मे ही अपनी बात कह देता हूं । आज की सरकार ने जितना गन्ने का भाव तय किया है, आज तक किसी भी सरकार ने नही किया। मुझे दुख है कि ये लोकदल के भाई आज किसान के हितैशी बनते है ।अध्यक्ष महोदय, आज दे ा मे जो चीनी की महगांई है, उसके जिम्मेदार मेंरे लोकतन्त्र के भाई है (ाोर एवम विघ्न)

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, हमारे रूल्ज आफ प्रोसीजर एण्उ कंडक्टर आफ बिजनैस मे यह लिखा हुआ है कि किसी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के स्टेटमैंट देने से पहले उस स्टेटमैंट की कापी स्पीकर साहब को देना पड़ती है और स्पीकर साहब को ही नही बल्कि उसकी कापिंया सभी मैम्बर्ज को सर्कुलेट करनी पड़ती है इसलिये मै आपसे रिक्वेस्ट करूगा कि (ाोर एवम विघ्न)

Mr. Speaker: Now i would request the Chief Minister to make a statement on call Attention Motion regarding Therin Dam (interruptions)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, उसका जवाब तो मुझे देना है लेकिन एक मिनट मै आपकी सेवा मे इन्होने जो प्वायंट रेज किया है उसका जवाब देना चाहता हूं हमारे मंत्री जी

सारे प्वायंट कवर नही कर सके इसलिए जो प्वायट्स बाकी रह गए है मै उनको कवर करना चाहता हूं (ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, अगर हमने इनको किसान विरोधी कहा भी है तो ये कह दे कि मै किसान विरोधी नही हूं ।(ाोर एवम विघ्न)

चौधरी भजन लालः आप मेरी बात सुनिए ।किसान विरोधी कहने वालो के बारे मे मुझे यह बताना पड़ेगा कि किसान विरोधी कौन है । किसान विरोधी तो आपकी उस समय की सरकार थी (ाोर एवम विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मै आपकी रूलिग चाहता हूं कि क्या कोई मैम्बर, मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की हैसियत से किसी भी विशय पर किसी भी समय कोई बात कह सकता है ?(ाोर एवम विघ्न)

Mr. Speaker: Without the permission of the Speakerऔर जब तक कोई स्पैसिफिक इ ू न हो तो तब तक नही बोल सकते। if the Chief Minsiste wants to speak on a point explanation then he can speak. (Interruptions)

Shri Verender Singh: Speaker, what had been said against him ? (interruptions)

श्री अध्यक्षः इनको फील हुआ है कि आपने कुछ रिमार्कस दिए है उसके उपर अपनी पर्सनल एक्सप्लेने ान दे रहे है। (ाोर एवम विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आप रिकार्ड चैक कर लीजिए, हमने कुछ भी नही कहा है (ाोर एवम विघ्न)

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, आप इजाजत से रूल 64 का हवाला देना चहाता हूं रून 64 यह कहता है कि–

"A statement may be made by a Minsiter on a matter of pyblic importach with the permission of the Speaker but no question shal be asked nor discussion take place thereon at the time the statement is made"

Mr. Speaker: Babu Ji, I entrirely agree with you that when a statement is to be made, copy of the same should be sent to the Speaker. लेकिन पर्सनल एक्सप्लेने ान आपके सामने रोजाना मैम्ब्र्ज ही देते । अगर चीफ मिनिस्टर साहब अपनी पर्सनल एक्सप्लेने ान पर एक मिनट बोलन चाहते है । and when other also on personal explanatious, haw can I stop him from doing so ? (Interruptions)

श्री मूल चन्दः स्पीकर साहब, यह कोई पर्सनल एक्सपलेने ान नही है पर्सनल एक्सप्लेने ान तो वह होती है, यदि हमने इनकी जात पर कोई हमला किया है(ाोर)

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, इन्होने कहा है कि यह किसान विरोधी सरकार है इनको क्या पता कि किसान विरोधी कौन होता है ?(ाोर एवम विघ्न)

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, इस सरकार की किसान विरोधी पालिसी है वह तो क्लीयर है यह चीज पर्सनल एक्सप्लेने ान की मद मे क्लीयर नही हो सकती स्पीकर साहब, मेरी गुजारि ा है कि इस गवर्नमैंट की किसान विरोधी पालिसी चीफ मिनिस्टर की पर्सनल एक्सप्लेने ान के तहत क्लीयर नही हो सकती । (ाोर एवम विघ्न)

Mr. Speaker: These remarks do show that Shri Bhajan Lal is also anti farmer (Interruption),

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आप रिकार्ड चैक कर ले हमने यह नही कहा । (ाोर)

श्री अध्यक्षः रिकार्ड तो मै चैक अप कर लूगा but i cannot refus the Chief Minster when he has requested to make a personal explanation (interruptions)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होने इस सरकार पर एक इल्जाम लगाया कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है । मुझे यह बात सुनकर इतना खेद है कि ये मेरे लोकदल के भाई किसानों के हित की बात कर रहे है मै इनको बताना चाहता हूं कि जिस समय इनकी सरकार थी उस समय किसानों के साथ क्या बीती ? यह सार दे ा जातना है और सारे दे ा का किसान

जानता है कि आज से लगभग दो साल पहले (ाोर एवम विघ्न) आप भाोर क्यों कर रहे है जरा भााति से मेरी बात सुने । (विघ्न)

श्री मूल चन्द जैनः अध्यक्ष महोदय, ये सारी बाते स्टेटमैंट मे आ चुकी है और अब चीफ मिनिस्टर साहब हाउस का समय जाया कर रहे है (विघ्न)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, उस समय की इनकी सरकार ने साढे तीन रूपये क्विंटल के हिसाब से भी किसानो का गन्ना नहीं उठाया। जब चौधरी चरण सिंह केन्द्र मे वित मंत्री होते थे, उस समय सारे दे ा के किसान इकट्ठे हो कर उनके पास गए । चौधरी देवी लाल हरियाणा मे मुख्य मंत्री हुआ करते थे, उनके पास भी हरियाणा के किसान आए थे और कहा थ कि आप किसानों को गन्ने पर सबसिडी दीजिए वरना किसानों की बहुत बुरी हालत होगी । उस समय चौधरी चरण सिंह ने किसानो को यह कहा कि आपने किस को पूछ कर गन्ना बोया था। अगर कोई जगह बाकी नही है तो मै टोपी उतार देता हूं आप मेरे सिर पर और वो दें । अध्यक्ष महोदय उस समय किसानों की क्या हालत हुई थी यह बात सारी दुनिया जानती है उसके बाद किसानों को अपने खेत मे खड़ा गन्ना जलाना पड़ा जिसके कारण गन्ने का एरिया कम हो गया । अगर उस समय किसानों की मदद हो जाती तो आज गन्ने का एरिया कम न होता और आज दे ा मे चीनी की महंगाई इतनी न होती । इस मंहगाई के जिम्मेदार कौन है ? मेरे लोकदल के भाईयो की सरकार थी, ये लोग है ।(ाोर

एवम विघ्न) अध्यक्ष महोदय आज ये मेरे भाई किसान के हितैशी बनते है जो उस साइड मे मेरे भाई बैठे है, उनसे ज्यादा बडा किसान मै अपने आपको समझता हूं

श्री अध्यक्षः आर्डर प्लीज आर्डल प्लीज

चौधरी गंगा रामः आपको यह भी नही पता कि एक किला जमीन मे कितने कट्ठे गेहूं के पड़ेगे कितने पानी लगेगे तथा कितने कट्ठे खाद के पड़ेगे ।

श्री अध्यक्षः गंगा रम जी आप बैठ जाइए ।(ाोर एवम विघ्न)

चौधरी भजन लालः मैने अपने हाथ से हल चला रखा है ंआपके पास एक खूड जमीन का नही और आपका पिता के पास भी एक खूड नही आप कैसे किसान है । मैने अपने हाथ से हल चला रखा है ।

Mr. Speaker: I would request the hon Members to kindly give one minute's time to the Chief Minister to complete his personal explaimtion (Interruptions)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अगर उस समय के लोग किसान के हमदर्द होते और किसानों को उस समय गन्ने पर सबसिडी दे जाते या गन्ने का भाव ठीक दे जाते तो आज दे ा मे चीनी की इतनी महगाई न होती । अध्यक्ष महोदय उस समयकी सरकार ने किसानो को कोई इनसैटिव नही दिया इसलिए किसानों

को खड़ा गन्ना अपने खेत मे जलाया पड़ा यदि किसान खडा गन्ना खेत मे जला देगा तो क्या अगले साल उस फसल को किसान बोएगा । जब किसान खडाा गन्ना जलाना पड़ा ते अगले साल गन्ने का एरिया कम हो गया । उसी कारण से आज दे ा मे चीनी की मंहगाई है और इसकी सारी जिम्मेदारी उस समय की सरकार पर है आज काग्रेस सरकार ने गन्ने का भाव 20 रूपये प्रति क्विटंल कर दिया है और सारे दे ा मे इस सरकार ने गन्ने का भाव 20 रूपये प्रति क्विटल देने की पहल की है । अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकदल के भाई अपने आपको किसानों के हितैशी कहते है ं ये लोग गावां मे जो करके लोगो को भड़काते है और कहते है कि मिलों मे गन्ना लाओ मै जानता हू कि आपने क्या कया मिला है? यदि मै आपकी पोल खोल दू .....(ाोर एवम विघ्न)

Mr. Speaker: Order Please, No interruptions, please.

चौधरी भजल लालः आपने क्या क्या किया है अगर मै उस बात पर आउगा तो फिर आपके पास उसका कोई जवाब नही होगा। मै किसी के बारे मे ऐसी बाते नही कहना चाहता । अध्यक्ष महोदय, ये लोग गांवो मे जा कर लोगो को बहकाते है ।

श्री अध्यक्षः यदि आप चीफ मिनिस्टर साहब को भी बोलने के लिए एक मिनट का टाईम नही देगे तो फिर काम कैसे चलेगो ? (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः क्या यह पर्सनल ऐक्सप्लेने ान है? ये तो हमे भडकाते है । (ाोर)

श्री अध्यक्षः आर्डल प्लीजः (ाोर)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आज की सरकार ने गन्ने का ठीक भाव दिया है । आज हरियाणा की सरकार को देख कर बाकी प्रान्तो की सरकारों ने भी किसानों को ठीक भाव दिए है ताकि किसान गन्ना और ज्यादा बोए और चीनी का भाव ठीक हो ।

बाबू मूल चन्द जैन जी ने कहा कि कई स्टेट्स ने हरियाणा से भी ज्यादा भाव दिया है। हम उसे भी ऐग्जामिन कह रहे है। हम किसानों के इनसे भी ज्यादा हितैशी है और उन्हे उनकी उपज की ज्यादा से ज्यादा कीमत देगे । हम उस सरकार की तरह, जिसमे ये भी मंत्री थे, नही करेगे ।

वक्तव्य

मुख्य मंत्री द्वारा रावी नदी पर थोन बांध के निर्माण संबधी।

Mr. Speaker: Now I Would request the Chief Minister make a statement on a Call Attention Motion regarding consturctiou of thein Dam.

कृश्य मंत्री चौधरी भजन लालः आदरीणय अध्यक्ष महोदय, मै नही जानता कि माननीय सदस्य ने किस आधार पर

यह बात की है पजांब सरकार थीन डैम परियोजना को एक तरफा कार्यान्वित कर रही है और हरियाणा सरकार ने निश्किय रूख अपनाया हुआ है माननीय सदस्यो का याद होगा कि मैने 21.3. 1980 को इसी प्रकार के ध्यान दिलाओ प्रस्ताव के उतर मे हरियाणा के केस की विसतृत व्याख्या प्रस्तुत की थी। इसके बाद मैने प्रधानमत्री को लिखा और उनसे इस मामले मे दखल आन्दाजी के लिए प्रार्थना की और मुझे उतर प्राप्त हुआ कि चीन डैम से पैदा होने वाली बिजली के हिस्से के लिए जिसका अभी निर्णय होना है, राज्यो के हकदारी के प्र न पर संबधित राज्यों के साथ बातचीत की जाएगी ।मैने केन्द्रीय उर्जा मंत्री को भी दो विस्तृत पत्र लिखे और उन्होने मुझे सूचना दी कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है ।यह सिर्फ पिछले महीनें की बात है जबकि उर्जा मंत्री को थीन डैम पर संसद के प्र न के सिलसिले मे सूचना भेजते हुए हरियाणा ने दोबारा अपनी स्थिति को दोहराया।

2. हरियाणा हर वक्त इस बात पर बल देता रहा है कि निर्माण कार्य आरम्भ करने से पहले भागीदार राज्यों के अन्तर्राज्जीय नियत्रण बोर्ड की स्थापना हो जानी चाहिए और उस नीति विशयक निर्णय लेने और पजाब सरकार को उचित हिदायते देने की जिम्मेदारी सौंप दी जानी चाहिए । यह निर्णय तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता मे 3.10.1977 को हुई बैठक मे लिया गया था। मै निर्णयों के रिकार्ड मे पढ कर बता रहा हूं ।

''विचार विम र्श के बाद यह तय पाया कि अत्तर्राज्यीय नियत्रण बोर्ड की स्थापना की जाएगी जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय कृशि एवम सिचाई मंत्री, उपाध्यक्ष केन्द्रीय उर्जा मंत्री और सदस्य संबधित राज्यों के मुख्य मंत्री तथा बिजली एवम सिचाई मंत्री होगे बोर्ड नीति विशयक निर्णय लेगा और पंजाब सरकार को निर्माण अवस्था के दौरान तथा परिचालक के समय हिदायते देगा तथापि परियोजना को पजांब कार्यान्वित करेगा ं।

इस से स्पश्ट है कि भारत सरकार ने 1977 मे निर्णय लिया था कि परियोजना के निश्पादन की जिम्मेवारी पंजाब को सौपी जाए परन्तु यह अन्तर्राज्जीय बोर्ड के पर्यवक्षेण और नियत्रण मे होना चाहिय ।

3. माननीय सदस्यों को पता है कि थीन डैम की बिजली मे हरियाणा के हिस्से का मामला अभी तय होना बाकी है ।आप को याद दिलाना जाता है कि तत्तकालीन प्रधानमंत्री महोदय की अध्यक्षता 14.2.1979 को एक बैठक हुई थी । हरियाणा, हिमाचल प्रदे ा, जम्मु का ामीर, पजाब और राजस्थान की सरकारो ने अपने अपने दावे प्रस्तुत किए थे प्रधान मंत्री महोदय का कहना था कि सारे मामले का फैसला विभिन्न राज्यो के कानूनी हक्को के आदर पर किया जाना है। तद्नुसार प्रधानमंत्री महोदय इस मामले के सबंध मे भारत के महाधिवकता को अपनी राय जाहिर करने के लिए लिखा था हरियाणा सरकार को ज्ञात

नही कि भारत के महाधिवकता महोदय ने इस मामले के संबध मे राय दी या नही ।

4.हरियाणा कि स्थिति मे कोई परिवर्तन नही हुआ हरियाणा ने यह बात बल पूर्वक कही है कि थीन डैम की बिजली मे हरियाणा का हक रावि ब्यास के फालतू पानी मे उसके हिस्से के आधार पर है जो कि भूतपूर्वक पजांब, राजस्थान और जम्मु क ामीर को 29.1.1955 की अधीसूचना के आधार पर दिया गया था । इसकी उतरवर्दी 24.3.1976 की अधीसूचना मे सयुक्त पजांब के पानी का हिस्सा पजांब हरियाणा मे 50:50 के अनुपात से बाटा गया था

5. सक्षेप मे हरियाणा का केस इस प्रकार है कि वह भूतपर्व पजाब का उतरवर्ती राज्य होने की हैसियत से रावी ब्यास के फालतू पानी के प्रयोग से होने वाले लाभ को प्राप्त करने का पूरा पूरा हकदार है । परियोजना की स्थिति का जैसा कि पजांब ने आग्रह किया है उसके साथ कोई सबंध नही है । इस पानी का अधिक से अधिक लाभ संतलुज ब्यास लिंक, पौग डैम माधोपुर ब्यास लिंक, सरहिन्द फीडर और थीन डैम जैसे प्रमुख निर्माण कार्यो के माध्यम से किया जाना संभव था और हरियाणा इन की लागत और फायदो का भागीदार है । थीन डैम परियोजना को रवी ब्यास के फालतू जल से अधिकतम सिचाई और बिजली के विकास की मुख्य योजना मे भाामिल किया गया था और इसे हमे ाा ब्यास पिरयोजना का अभिन्त्र अंग माना जाता रहा है जैसा

कि डा0 ए0एन0 खोसला के परामर्श पर 17.6.1970 को जारी की गई भारत सरकार की अधिसूचना से स्पश्ट है। ब्यास यूनिट 1 और 11 की लागत भूतपूर्व पजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच आबटिंत कर दी गई थी और यह तय किया गया था कि जैसे जैसे रावी पर संग्रहण निर्माण कार्य भ्रारू हो जायेगा तो इसकी लागत और ब्यास परियोजना जैसे जैसे रवी पर सग्रहण निर्माण कार्य भ्रारू हो जायेगा तो इसकी लागत और ब्यास परियोजना की लागत भागीदार राज्यो के बीच आबटित की जा सकती है पीछे 1973 से ही भारत सरकार ने तदर्थ आधार पर यह प्रस्ताव भी किया था कि चीन परियोजना बिजली मे से 10 प्रतिशत का हिस्सा हरियाणा को दे दिया जाये । तथापि हरियाणा ने इस आधार पर अधिक हिस्से के लिये भी आग्रह किया है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.3.1976 के अधीन पंजाब हरियाण को 50:50 अनुपात से जल आबटिंत किया गया है अत हरियाणा भूतपूर्व पजांब के हक मे से 50 प्रतिशत बिजली का तर्क सगंत नीति से हकदार है ।

6. हरियाणाा का यह दृढ मत है कि अन्तर्राज्यीय नियत्रण बोर्ड की स्थापना के बाद पजांब स्कीम को कार्यान्वित करे। इस बोर्ड मे रावी ब्यास के फालतू पानी की बिजली के लाभ के हकदार लाभ प्राप्त करने वाले के रूप मे हरियाणा को नुमांयेदगी मिलगी। 9 अक्तूबर 1980 को मैने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री महोदय को लिखा था कि चूकि 1980–85 की योजना को अतिम रूप दिया जा रहा है। अत यह निसान्त वांछनीय होगा कि थीन डैम और बोर्ड की स्थापना करने से बंधित अत्तर्राज्यीय मामलों का निर्णय करने मे देरी न की जाए । दिनांक 16.10.1980 के अपने उतर मे केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने मुझे यह सूचना दी है कि वे मामलें की जांच पड़ताल करवा रहे है। यह स्पश्ट है कि चूकि इस मामले का कोई निर्णय नही हुआ है इस लिये आयोजना आयोग ने अभी तक अतिम अनुमति प्रदान नही की है ।

7. अध्यक्ष महोदय, मुझे वि वास है कि माननीय सदन इस बात से सहमत होगा कि माननीय सदन ने जो यह निश्कर्श निकाला है कि हम लोगो ने इस समस्या की ओर निश्किय रूख अपनाया है, ठीक नही है । वास्तव मे असली बात यह है कि हम पिछले साल भर मे इस मामले पर ध्यान पूरी तरह से केन्द्रित किए रहे है और हम अपने हकों के लिए आग्रह करते रहे है हमे वि वास है कि भारत सरकार अन्तर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करने के लिए और थीन डैम परियोजना बिजली मे

हरियाणा का हिस्सा सुरक्षित करने के लिये भीघ्र कार्यवाही करेगी ।

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, जो ब्यान मुख्य मंत्री ने पढ कर सुनाया है उनसे हर हरियाणावासी को बड़ा सदमा लगेगा । स्वय मुख्य मंत्री जी ने अपने ब्यान मे माना है कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हरियाणा का हिस्सा थीन डैम की बिजली मे है या नही that point had already been settled. But Sir, you will be shocked to note that the letter which Government has reveived from the present Prime Minister has reopened them the matter again, I will draw your attention to para I wherein it is mentioned:-

''That the question of the entitlement of the States to a share in the Power generated at Thein dam which had remained undecided will be taken up with the concerned State"

MR. Speaker: That refers to the quantum of share.

Sh. Verender Singh: No, Sir,It Says about entitlement of the share. That is not about quantum of share.

श्री वीरेन्द्र सिहः बहिन सुशमा जी, जो इसमे लिखा है आप उसको हिन्दी मे पढ दे ताकि सब की समझ मे आ सके ।

श्री मति सुशमा स्वाराजः इसमे लिख है इसके बाद मैने प्रधानमंत्री को लिखा और उनके इस मामले मे दखलआन्दजी के लिए प्रार्थना की और मुझे उतर प्राप्त हुआ कि थीन डैम से पैदा

होने वाली बिजली के हिस्से के लिये जिसका अभी निर्णय होना है ।

श्री वीरेन्द्र सिहः मुख्यमंत्री जी ने इसी जवाब मे यह भी माना है और से और भी आगे जाना चाहूंगा । जब पजांब के चीफ मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह जी हुआ करते थे उस टाईम पर उन्होने गवर्नर साहब के एड्रेस मे माना था कि थीन डैम मे हरियाणा का हिस्सा है । यह असैम्बली मे दिया गया ब्यान है । गवर्नर एड्रैस जो मार्च मे पड़ा जाता है, उसमे यह पढा गया है । अब मुझे साल तो याद नही है लेकिन उन्होने असैम्बली मे थीन डैम मे हमारा हिस्सा माना है ।गवर्नमैंट आफ इण्डिया ने एडहाक बे सिज पर इनकी स्टेटमैंट के मुताबिक सैटल किया है और इन्होने खुद भी माना है that Government of India hed already settled that there was 10% share of Haryana.झगड़ा स्टेट का था लेकिन इस सरकार ने और इन्दिरा गांधी ने हरियाणा की जनता के साथ वि वासघात किया है । मुझे तो यह कहते हुये भार्म आती है कि जो भोयर पहले ही सैटल हो चुका है और जिसके हम इनटाइटल्ड है, उसको री ओपन क्यो किया गया ? मुझे इस बारे मे मुख्य मंत्री जी जवाब देने का कश्ट करे।

चौधरी भजन लालः स्पकीर साहब, चौधरी वीरेन्द्र सिंह को जो ीला भाशण सुन कर मुझे बडी हैरानी हुई । चौधरी देवी लाल की सरकार मे ये इरीगे ान एण्ड पावर मिनिस्टर थे । (विघ्न)

Sh. Verender Singh: Kindly ask him to reply my question.

श्री अध्यक्षः आपको उनका जवाब तो सुनना पड़ेगा और चीफ मिनिस्टर को बैकग्राउन्ड भी बतानी पड़ेगी ।

चौधरी भजन लालः स्पकीर साहब, जब ये बोलते है तो हम कभी इनको बीच मे नही टोकते ।किसी बात को दोबारा कहने से पहले ये मेरी बात तो सुने।

श्री अध्यक्षः चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी, आपने खुद ही दस परसेन्ट भोयर वाली बात कही है, उसकी वे कग्राउन्ड तो बतानी पड़गी ।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मुझे यह तो बताना पड़ेगा कि किन की मेहरबानी से यह काम हुआ और इसका जिम्मेदार कौन है?

एक सदस्यः अब तो मामले खराब हो चुका है ।

चौधरी भजन लालः मामला खराब कुछ नही हुआ । अगर कोई बात है तो सब इसकी मेहरबानी से है । मैने मुख्यमंत्री बनते ही इस मामले को उठाया और भारत सरकार को लिखा । इस मामले को अटारनी जनरल की राय के लिये भेजा गया। अब अटारनी जनरल की राय आ चुकी है, उतना ही हिस्सा हमे बिजली का भी मिलेगा । मै यह दावे के साथ कहता हूं ये आज किसानों के हितो की बात करते है देवी लाल की सरकार मे यही चौधरी

वीरेन्द्र सिंह जी इस महकमे के इन्चार्ज होते थे इन्होने एक भाब्द भी नही लिखा और न ही एक भाब्द कभी इस बारे मे कहा । आज यहां हाउस मे खडे हो कर यह बात कहते है कि हमने हरियाणा के हितों को बेच दिया। हमने तो हरियणा के हितो की रक्षा की है जहां तक नाथपा झाकड़ी की बात है, जिसमे हरियाणा का हक भी नही था, हम हिमाचल प्रदे ा से बिजली ले कर आये है । हम एस0वाई0एल0 के पानी का मसाला भी जल्दी ही हल करने जा रहे है।

श्री अध्यक्षः चीफ मिनिस्टर साहब ने अ योरेन्स दी है कि जो हरियाणा का हिस्सा है, वह बिल्कुल कम नही होगा ।

चौधरी भजन लालः मे यहां पर मगरमच्छ के आसू बहाते है ओर लोगो को गुमराह करते है ।

श्री वीरेन्द्र सिंहः इन्होने कहा है कि हमारी इन्टाइटलमेंट है लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमे लिखा है कि राज्यो के हकदारी के प्र न पर संबधित राज्यो के साथ बातचीत की जाएगी ।

श्री अध्यक्षः आपने अपने सवाल पूछने वक्त यह कहा कि थीम डैम मे हरियाणा के हिस्से के लिए मुख्यमंत्री ने और हिन्दुस्थान की प्रधानमंत्री ने खिलवाड़ किया है ।

श्री वीरेन्द्र सिंहः मैने यह नही कहा।

श्री अध्यक्षः आपने बिल्कुल यही कहा है । मैने तो बहुत छोटे लफज इस्तेमाल किये है लेकिन जो कुछ चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे है उसको सुन तो लीजिए । गवर्नमैंट वैचिज वाले भी बड़ी भाान्ति से सुन रहे थे लेकिन आप रोला मचा रहे है, आप भी खामो ाी से सुनिये ।

श्री वीरेन्द्र सिंहः मै भोयर की बात पर डिफर करता हूं ।

श्री अध्यक्षः आपने ये लफ्ज कर रहे है कि हरियाणा के भोयर के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री ने और मंत्री ने वि वासघात किया है । आप उनकी बात तो सुने।

श्री वीरेन्द्र सिंहः मैने भोयर के बारे मे नही, इनटाइटलमेंट के बारे मे कहा है । आप रिकार्ड चैक करवा ले ।

Sh. Speaker: The record will be checked up properly. Do not worry about it.

चौधरी भजन लालः जैसा कि मैने अर्ज किया है कि आज की सरकार को हरियाणा के हितों की पूरी चेश्ठा है और उसके हितो की रक्षा करेगी ।उस वक्त की सरकार की मेहरबानी से आज हरियाणा सफर कर रहा है ।

चौधरी गंगा रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर ।

श्री अध्यक्षः आप बीच मे इन्ट्रप्ट न करे । बीच में इन्ट्रप्ट करने से आप अपने नालेज को जाहिर नही कर रहे है।

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, बाद मे मुझे टाईम दे दे।

श्री अध्यक्षः इस पर आपको कतई भी टाईम नही दूंगा। काल अटैन ान मो ान के बारे मे रूल कलियर है कि जो मैम्बर मो ान सूब करता है वही मैम्बर केवल एक सवाल पूछ सकता है । मै एक सवाल जो बजाए दो दो सवाल अलाऊ कर देता हूं लेकिन जनरल डिबैटअलाऊ नही की जा सकती । चौधरी भाम ोर सिंह जी एक सवाल पूछना चाहते थे, मैने उन को भी रोक दिया।

चौधरी भजन लालः उस वक्त जब चौधरी देवी लाल सरकार थी तो चौधरी वीरेन्द्र सिंह इरीगे ान एण्ड पावर मिनिस्टर होते थे। इन्होने रावी ब्यास के पानी को लेने मे जो कार्यवाही की है वह आपके सामने है ।आज पानी और बिजली के लिए हमारे प्रान्त मे कितनी भारी समस्या बनी हुई है । अगर उस समय समस्या का समाधान हो जाता तो आज यह प्रोवलम ही न खड़ी होती। इसके बावजूद भी आज ये लोग किसानो के हितैशी बनते है माननीय सदस्यो को बताना चाहता हूं कि आज की सरकार को हरियाणा के हितों के लिए चाहे कितने ही ठोस कदम उठाने पड़े लेकिन हिचकिचायेगी नही, हरियाणा के हितों की रक्षा करेगी । हमे प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा है । कि वे हमे इन्साफ देगी ।

इन्होने जो प्रधनमंत्री पर इल्जाम लगाया है, यह बहुत अफसोस की बात है उनके सामने सारा दे ा एक है। कौन से प्रान्त मे किस प्रकार की समस्या है यह उन्हे भली भांती मालूम है । प्रान्तो के जो आपसी झगड़े है, उन ंझगडो को वे बहुत जल्दी सुलझायगी और जिस प्रान्त का जितना हक है उसे पूरी दिलायेंगी। मै दावे के साथ कहता हूं कि यह बहुत गहराई का मामला है इस मामले को मजाक मे न ले । इस मामले को जितना भी उलझाया है, वह उस वक्त की सरकार ने उलझाया है । हमारी सरकार हरियाणा का पूरा हिस्सा ले कर देगी ।

श्री वीरेन्द्र सिंहः मेरा तो प्वांइट वाला छोटा सा सवाल था, उसका जवाब नही मिला ।

Mr. Speaker: Chaudhri Verender Singh Ji, I can allow you one more question but please make it short. (Interruptions)

श्री वीरेन्द्र सिंहः मैने जो पहले सवाल पूछा था वह भाार्ट ही था। अब इसके दो छोटे छोटे पार्ट बनते है।इन्होने अपने जवाब मे माना है कि 14.2.1979 को उस समय के प्रधनमंत्री ने मेटर को अटार्नी जनरल को रैफर कर दिया था लेकिन उस मैटर पर आज तक कोई भी ओपिनियन नही आई है । डेढ साल से यह तखत पर पड़े रहे है(ाोर) स्पीकर साहब, मै पूछना चाहता हूं कि इन्होने इस दौरान क्या किया? दूसरा मेरा क्वै चन यूनिलेट्रल

एग्जीक्यू ान का था । उसके बारे मे भी मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी स्टेटमैंट से कोई जवाब नही दिया है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, अटार्नी जनरल की राय मानी गई थी। मुझे पता लगा है कि अटार्नी जनरल की ओपीनियन आ गई है । ओपीनियम तो उनकी फाईल पर ही होगी। वह मै हाऊस मे नही बता सकता कि उनको क्या ओपीनियम है। मै सदन को वि वास दिलाता हूं । कि आज की प्रधान मंत्री हरियणा के साथ कोई अन्याय नही करेगी, इसांफ करेगी ।

श्री वीरेन्द्र सिंहः मै आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री तो न्याय करेगी आप क्या करेगे ?

चौधरी भजन लालः यह हमारी वजह से ही होगी । (ाोर)

श्री अध्यक्षः मे यह भी पूछ रहे है कि क्या पंजाब ने काम भारू कर दिया है

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, पजांब सरकार ने अभी तक कोई काम भारू नही किया है क्योंकि योजना आयोग ने उन्हें अभी तक स्वीकृति नही दी है ।

श्री अध्यक्षः अब एक मंत्री रूल 16 के तहत प्रस्ताव पे ा करेगे (ाोर)

डा0 मंगल सिंहः स्पकीर साहब.....(ाोर)

श्री अध्यक्षः आप किन विशय पर बोलना चाहते है?

डा0 मंगल सिंहः स्पीकर साहब, जस्टिस दुलत साहब ने महार्शि दयानन्द यूनिवार्सिटी के बारे मे जो रिपोर्ट दी है, मैने उस पर डिस्क ान के लिए डिमान्ड की थी, उसके बारे मे आपने क्या निर्णय लिया है ?

श्री अध्यक्षः वह तो मैने अलाऊ कर दी थी but there is no time before the House for its discussion मै 3 काल अटैन ान मो ान भी एडमिट कर रखो । लेकिन समय ही नही (ाोर) What can I do? (Interruptions) टाईम तो बडी कीमती चीज होती है। Once Nepolean had told to his Gereral that ask for anything but do not ask me for time. Now the parliamentary Affairs Minsister will move the motion under Rule16

Dr. Mangal Sein: Mr. Speaker, one more things. Sir (Interruptios)

श्री अध्यक्षः विजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग मे इन सब चीजों के बारे मे एक घन्टा बहस हुई थी (ाोर) Now I can not go outside the report of the Business Advisory Committee.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now the Minister for Parliamentary Affairs may please move the motion under Rule 16.

स्थानीय भाासन मंत्री चौधरी खुरदी । अहमदः मै प्रस्ताव करता हू।

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर साइने डाई एडजर्न रहेगी ।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर साईन डाई एडजर्न रहेगी ।

श्री हीरा नन्द आर्य लोहारूः: अध्यक्ष महोदय, पालियामेट्री अफेयर्ज के मिनिस्टर साहब ने यह प्रस्ताव जो पे । कर दिया लेकिन जो काल अटैन् ान मो ान एडमिट हो चुके है, उन का क्या बनेगा ?

श्री अध्यक्षः यदि सदन के अन्दर इतना मंहगा न होता, तो मै अव य काल अटैन् ान मो ान को आज टेक अप करवा देता। But there had been too much waste of time. अब यह एडमिट होने के बाद भी टेक अप नही हो सकता becuse there is no time left now. One and a half hour has been wasted in side talks. सदन को मै यह बताना चाहता हूं कि मैने अपने सैकट्री से कह कर जो दो काल अटैन्' ान मो ान एडमिट कर रखे थे, उनके बारे मे बहिन कमला वर्मा जी और आर्य साहब को खबर भेज दी थी कि अपने अपने काल अटैन् ान मो ान पढने के लिये तैयार रहे Bill when i saw the time, i felt helpess.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, अगर इनके राज मे रोजना इतनी घटनांए घटेगी तो यह सै ान यदि अढाई महीने तक भी चले तो भी समय कर रहेगा । जब तक मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल रहेगे तब तक इनके राज मे रोजाना इतनी घटनांए घटती रहेगी ।

श्री अध्यक्षः जब वे घटनाये आयेगी तब देखा जायेगा ।

श्री हीरा नन्द वर्माः स्पीकर साहब, बहुत से काल अट ौन मो ान एडमिट हो चुके है और बहुत से दूसरे मामले भी है जिन पर बहस की जा सकती है इसलिए मै चाहता हू कि सदन का समय कम से कम एक दिन के लिए और बड़ा दिया जाए(ाोर)

चौधरी राम लाल वधवा करनालः अध्यक्ष महोदय अभी आपने फरमाया है कि दुलत कमी ान की रिपोर्ट पर बहस अलाउ कर दी है। मैने भी इसका नोटिस दिया हुआ है अभी आप ने फरमाया कि काल अटैं ान मो ान और भी स्वीकार किए है । अध्यक्ष महोदय, यह बहुत छोटा सै ान हुआ । यह सै ान कोई बजट सै ान नही थां ं यदि बजट सै ान हो तो उसके अन्दर सारे मसले बजट और गवर्नर एड्रेस पर डिस्क ान के समय उठाये जा सकते है । अभी एक साल के अन्दर इस सरकार के आने के बाद इतनी बातें हुई जिनको कहने के लिए काफी समय चाहिऐ । पिछले सरकार मे जब हम रहे तो दस दस और पन्द्रह पन्द्रह दिन

तक सै ान चलता रहा था। मै और बाबू मूलचन्द जैन उस सरकार मे पालियामैट्री अफेयर्ज के मिनिस्टर रहे । आप स्वंय अध्यक्ष है आपको भी मालूम है कि हमने कितने दिन सै ान चलवाया ।

अध्यक्ष महोदय, टेबल पर कुछ कागज रखे गए है लेकिन भी डिस अलाऊ कर दिया है यह ठीक है कि आप की भी समय की कमी कें कारण मजबूरी थी ं बिजैनस एड वाईजरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक तो सै ान चार दिन ही चलता था ।लेकिन हम पूछना चाहते है कि हमने जो मो ान दी यदि उन पर डिस्क ान ही नही हो सकती तो उन्हे टेबल पर रखने का क्या फायदा है? जब सै ान समाप्त हो जायेगा तो वे सारे लैप्स हो जायेगें फिर नए सिरे से अलग सै ान मे नये कागजात आएगे । इस तरह से स्पीकर साहब, मैने एक मो ान रूल 84 के तहत दिया था जिसमे सरकार की कार्यकृतियां का जिकर दिया गया था उसमे मैने 20 मसले उठाये थे एि ायाई गेम्ज जो राई मे आई और उस पर करोडो रूपये खर्च हुआ वह फिर चली गई, टीचर्ज का मसला, इसी तरीके से पब्लिक अन्डर टेकिग्ज मे चेयरमैन की पावर्ज तथा उसकी मिसमैनेजमैंट हुई थी रूलज इन्डस्ट्रियलाईजे ान का काम स्लो रहा, स्टूडैन्टस के अन्दर टीचर्ज के अन्दर और एम्पालाईज के अन्दर अनरैस्ट है। इसी तरीके से जितने भी एडहका एम्पालाईज है वे सभी एजीटे ान कर रहे है ।स्टूडैन्टस पर लाठी चार्ज हुआ। डबवाली कांड की जो रिपोर्ट

छपी है वह भी सरकार सदन के सामने नही लाई है इस प्रकार की कितनी ही मिसाले है जो आज डिस्कस करनी थीं। लेकिन इन सब चीजो के लिए चार दिन का सै ान यह बहुत बडा अन्याय है । लाखो रूपया इसलिये खर्च होता है ताकि हम सरकार की गलतियों जनता के सामने और हाउस के अन्दर सदस्यों के सामने रख सके । अध्यक्ष महोदय अभी टाईम है और आप बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मिटिंग अभी अपने चैम्बर मे बुला ले मै आपसे रिकवैस्ट करता हूं कि बडे अहम मसले है ।इसलिये सै ान को कम से कम दो दिन और बड़ा लेना चाहिये ताकि इनको डिस्कस किया जा सके । मै आपसे हाथ जोड़ कर अपील करता हूं कि यह सारे हाउस के मैम्बरो की इच्छा है इसलिये आप इस पर जरूर कर अपील करता हूं कि यह सारे हाउस मे मैम्बरो की इच्छा है इसलिये आप इस पर जरूर विचार करे। वरना मै इस प्रस्ताव की पुरजोर मुखालफत करता हूं ?

श्रीमती सुशमा स्वराज अम्बाल छाबनीः अध्यक्ष महोदय जो प्रस्ताव संसदीय कार्यो के मंत्री चौधरी खुर ाीद अहमद जी ने सदन के सामने रखा है और हमसे यह मन्जूर करवाना चाहते हे कि सदन आज की बैठक से उठने पर अनि ाचत काल के लिए स्थगित रहेगा मै इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं अध्यक्ष महोदय अगर सदन के सामने कोई बिजनैस न होता तब तो इस प्रस्ताव को पास करने से हमे कोई एतराज न था लेकिन चूकि अभी सदन के सामने बिजनैस है और हाउस सुप्रीम है

इसलिये हाउस बिजनैस एडवाइजारी कमेटी की रिपोर्ट को बदल सकता है। क्योकि बिजनैस एडवाजरी कमेटी की रिपोर्ट सदन मे रखी जाती हे और हाउस उस रिपोर्ट को एडाप्त करता हूं इसलिए हाउस को यह अधिकार है कि वह इस प्रस्ताव पर दोबार विचार करे । श्री जगनाथ जी की और से जगनाथ जी, आपके यहां तो अधिकार नही लेकिन यहां पर तो है।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब चौधरी खुर ाीद अहमद ने जो यह प्रस्ताव पे ा किया है वह इसलिए कि वह बहिन जी को घर भेजना चाहते है लेकिन ये उसमे भी नाराज है (व्वहधान एवम हंसी)

श्रीमती सुशमा स्वराजः स्पीकर साहब, राज्य मे इतनी दुखदायी घटनाए होती हे कि हमारा घर भी आराम मे बैठने को जी नही चाहता है कि सदन मे घटनाओ का ब्यारो रखे।

स्वीम आदित्यवे ाः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि जब हाउस बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट सोमवार को पास कर चुका है तो इस प्रस्ताव पर बहस करने का इनका कोई औचित्य नही है। मेरी रिक्वैस्ट यह भी है कि सदन की एक पैटी ान कमेटी बनी हुई है । अगर कोई मामला है वह पैटी ान कमेटी को लिख कर भेज दे।

श्रीमती सुशमा स्वराजः रूलज आफ प्रासीजर का तो इनको पता नही है कहां से आ गये ये बाबा बीच मे बोलने के लिए ?

डा0 मंगल सिंहः स्पीकर साहब, हमारे एक सदस्य चौधरी रिजक राम जीने यह कहा कि हम बहिन जी को घर भेजना चाहते है लेकिन वह जाना नही चाहती । बूढापे मे उनको घर कैसे याद आ रहा है ?(हंसी)

चौधरी भजन लालः डाक्टर साहब आपको क्या पता है कि घर किसे कहते है ?(हंसी)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब इनको कई घरों का तजुर्बा है इनके घर तो साथ ही चलते रहते है।

श्रीमती सुशमा स्वराजः स्पीकर साहब, ऐसा मजाक जो आपस मे चलता ही रहेगा । अगर तो सदन के सामने कोई मसले न हो, कोई बिजनैस न हो, और सदन को स्थगित कर दिया जाये तो कोई एतराज वाली बात नही, मगर जब आपन भी यह महसुस किया है कि कुछ काल अटैन्ान मो ान्ज आप एडमिट कर चुके है। लेकिन चूकि समय थोडा है और सदन आज स्थगित हो जायेगा, इसलिये वे आज नही आ सकेगे । कहने का मतलब यह कि उनका जवाब नही आ सकेगा । इसके अलावा रूल 84 के अन्गर्त आप चौधरी राम लाल वधवा द्धारा मागी गयी दुलत कमी ान की रिपोर्ट पर चर्चा भी मजूर कर चुके हो, इसलिये वह

मजूर ाुदा डिस्क ान भी आज समय के प्रभाव के कारण नही हो सकेगी । आज जीरो आवर के दौरान दृश्टि विहीनों के सबंध मे मुख्यमंत्री अपनी स्टेटमैंट देना चाहते थे, वह भी नही दे सके क्योकि बीच मे चौधरी गंगा राम जी ने बोलना भाुरू कर दिया। समय क अभाव के कारण मुख्यमंत्री जी जो स्टेटमैंट अन्धो के बारे मे देना चाहते है वह भी नही आ सकेगी ंइसलिये मै यह कहना चाहती हूं कि काफी मसले है। हाउस सुप्रीम है इस रिपोर्ट को चेंज किया जा सकता है सारे बाते बडी अहम है, बडे अहम मसले है जो सदन के सामने अभी आने है और डिस्कस होने है। मुख्यमंत्री जी से मै यह निवेदन है करना चाहूगी कि क्या फर्क पड़ता है यदि एक दिन का सै ान और बढा दे ? कल भी हमारा सै ान साढे चार बजे तक चला । आज भी सै ान एक्सटैंज करना पड़ेगा । इसलिए कम से कम मन्जूर की हुई चीजों पर तो हम चर्चा का मौका ही मिलना हो चाहिये। मै प्रार्थना करूंगी कि केवल एक दिन का सै ान बडा दिया जाये । ताकि हम इन आव यक विशयों पर चर्चा कर सके, उसके बाद बे ाक सदन स्थगित हो जाये। मै एक बार फिर मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगी कि कम से कम व एक दिन का सै ान इन मन्नूर ाुदा चीजों पर चर्चा करने के लिए तो बढवा दे। मुख्यमंत्री महोदय इतने दयानतदार है।

Mr. Speaker: I must point out one thing to the House that जब बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की मीटिगं हुई, उस वक्त दुलत इन्कवायरी कमी ार की रिपोर्ट भी आ चूकी थी और

इसका सब मैम्ब्र्ज को पता था । जितने काल अटैन्ा ान मो ान और बाकी मो ान्ज दिये गये थे, उनका भी सब मैम्बर साहेबान को पता था। उस वक्त बिजनैंस एउवाइजरी कमेटी के सामने सिर्फ एक दिन की एक्सटें ान के लिए प्रैस किया गया जिसे मुख्यमंत्री जीने मानलिया और मैने भी उसको एक्सैप्ट कर लिया। उस वक्त मैम्बर्ज को पता था कि इतना बिजनैस है। उस वक्त आपको चाहिये था कि दो दिन के लिए प्रैस करते है (व्यवधान व भाोर)

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, हमे पता नही था कि अन्धे पीटे जायेगे, यह पता नही था कि स्टूडैन्ट्स पकड़े जायेगे और हमे यह भी पता नही था कि एम0एल0एज0 भी जेल मे भेजे जायेंगें। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी गंगा राम गोहानाः स्पीकर साहब, मै आपका बड़ा धन्यवाद करता हू कि आपने मुझे बोलने का पहली बार अच्छे मौके पर टाईम दिया । मै केवल इतना ही कहतना चाहूगंा कि इस रैज्योलू ान के बारे मे चौधरी रामलाल वधवा जी और बहिन सुशमा जी ने जो बाते कही है उनकी स्पोर्ट करते हुए मै इसका विरोध करता हूॅं मै यह भी कहना चाहूंगा कि इस असैम्बली का सै ान कम से कम दो दिन तक और बढा दिया जाना चाहिये । आज सारे हरियाणा मे अन्दर स्पीकर साहब, एक किस्म की आग लगी हुई है सारे हरियाणा मे किसान आन्दोलन कर रहे है, सारे हरियाणा मे भाूगर मिले बन्द है, सारे हरियाणा मे अन्धे सरकार को रो रहे है, सारे हरियाणा मे विधार्थियों की आखो मे ग्रीज

डालकर उनको अन्धा किया जा रहा है और साारे हरियाणा मे आयुवैदिक कालेजो की लडकी सडको पर भटर रही है, इसलिये मसले बहुत से है । स्पकीर साहब, मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत अच्छी भाशा मे कहा कि हरियाणा के इन्ट्रैस्टस को हर साइड से सुरक्षित रखेगे।

स्पीकर साहब, मै आपके जरिये मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पजाब के मुख्यमंत्री ने यह एलान किया है कि चण्डीगढ पजाब का है इन्होने आज तक उसकी कन्ट्राडिक ान नही की।(व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्षः अखबार के बारे मे जो रेफर किया गया है, वह सारा एक्सपंज किया जाये।

चौधरी गंगरामः स्पीकर साहब, मै केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज हरियाणा मे लोगो की बहुत सी सम्साये है हम आपके जरिये थोडी बहुत समस्यो हल कर सकते है। इसलिये मै आपसे यह रिक्वैस्ट करूगा कि हाउस दो दिन तक के लिये और बढा दिया जाये।

स्थानीय भाासन मंत्री(चौधरी खुरदी ा अहमद): स्पीकर साहब, जब हाउस का सै ान बुलाया गया था हमारे पास बहुत बिजनैंस था । हम हाउस को बडी खु ाअसलूबी से चलाने की कोि ा ा करते हे ओर चला भी पाते है लेकिन ज्यादा टाईम किस चीज पर लग जाता है? स्पीकर साहब, वह टाईम लग जाता

है जैस अभी मेरे दोस्त चौधरी गंगा राम बोल रहे थे वे आधा टाईम तो बिना इजाजत के बोल जाते है। चौधरी राम लाल वधवा सारे मामले को पे ा करने की कोि ा ा करते है। जैसे आजकल सर्दी पड़ रही है, वे ऐसे मामले भी एडजर्नमैंट मो ान और दूसरे मों ान के द्वारा लाना चाहते है स्पीकर साहब, कितनी छोटी छोटी चीजों को लेकर राई का पहाड बनाया जाता है जरा जरा सी बातो को लेकर हाउस का टाईम जाया किया जाता है । ऐसी बात नही । हाउस को ऐक्सटैन्ड करने की कोई जरूरत नही है। हमने सारे मंसले पर गौर किया है बहिन सुशमा जी के बारे मै तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हू:—

या रब न वह समझे न समझेगे मेरी बात

दे उनको दिल और न दे मुझको जबां और

इसलिए मेरी गुजारि ा है कि इस मो ान को पास किया जाये और बजट सै ान मे फिर जब हम मिलेगे तो मेरे साथी अपने दिल का अरमान निकाल लेगं।

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि सभी अपनी आज की बैठक मे उठने पर साईने डाई एडजर्ज रहेगी ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

दि पजाब एग्रीक्लचर प्रोड्यूस मार्किटस हरियणा थर्ड अमैडमैंट एंउ वैलिडे ान बिल, 1980

श्री अध्यक्षः मुझे सर्वश्री रामलाल वधवा, संत कबर और जगदी ा कुमार बैनीवाल एम0एल0एज0 की और से पजाब एग्रीक्लचर प्रोड्यूस मार्किटस हरियणा थर्ड अमैडमैंट एंउ वैलिडे ान बिल, 1980 (हरियणा अमैडमैंट सख्या 6) और सबंधी राम लाल वधवा मंगलजैन, सत कवंर और जगदी ा कुमार बैनीवाल की और से पजांब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किटस हरियणा थर्ड अमैडमैंट एंउ वैलिडे ान बिल, 1980 (हरियणा अमैडमैंट सख्या 7) की डिसएप्रूवल के नोटिस मिले है। अगर हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय बचाने के लिये इन प्रस्तावों तथा बिल की कंसिड्रे ान मो ान पर इकट्ठा विचार कर लिया जाए ।

अवाजेः ठीक है जी ।

चौधरी रामलाल वधवाः मै प्रस्ताव करता हूं–

(1) कि यह सदन पजांब कृशि उपज मंडी हरियाणा तृतीसय स ाोधन अध्यादे ा 1980 (1980 कर हरियाणा अध्यादे ा सख्या 6) को अस्वीकर करता है।

(2) कि यह सदन पजांब कृशि उपज मंडी हरियाणा तृतीसय मान्यकरण अध्यादे ा 1980 (1980 कर हरियाणा अध्यादे ा सख्या 7) को अस्वीकर करता है।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रसतु हुआ ।

(1) कि यह सदन पजांब कृशि उपज मंडी हरियाणा तृतीय स ाोधन अध्यादे ा 1980 (1980 कर हरियाणा अध्यादे ा सख्या 6) को अस्वीकर करता है। को अस्वीकर करता है।

2) कि यह सदन पजांब कृशि उपज मंडी हरियाणा तृतीसय मान्यकरण अध्यादे ा 1980 (1980 कर हरियाणा अध्यादे ा सख्या 7) को अस्वीकर करता है।

अब एक मंत्री दि पजाब एग्रीक्लचर प्रोड्यूस मार्किटस हरियणा थर्ड अमैडमैंट एंउ वैलिडे ान बिल, 1980 विचार के लिए प्रस्तुत करेगे।

Afeiculture Minister (Sardar Tara Singh): Sir I beg to move-

That the Punjab Agrucultural Produce Markets Haryana Thire Amedment and Vaildation Bill be taken in to considerstion at once.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रसतु हुआ कि ।

दि पजाब एग्रीक्लचर प्रोड्यूस मार्किटस हरियणा थर्ड अमैडमैंट एंउ वैलिडे ान बिल, 1980 विचार किया जाए ।

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, दो अध्यादे ा और एक बिल सदन मे प्रस्तुत हुए हैं स्पीकर साहब, मै बिल स्टेटमैंट आफ आगजैक्टस एण्ड रीजन्ज जिसकी बिनाह पर ये अध्यादे ा जारी हुए और यह विधेयक सदन मे लाया गया है उसको सदन के सामने पढना चाहूंगा। इसमे लिखा है–

'' With a vied to achieving better efficiency, closer supervision and effective coordina tin the working of the Haryana State Agricultural marketing Board, a new post of Chief Administator has been created recenly. The Punjab Agricultural produce Markets Act 1961 as amended upto date does not specify the function and power of the Chief Administrator. It was considered necessary to amend the Act in order to specify the duties and responslblities powers and functions of the Chief Administrator..."

अध्यक्ष महोदय, इस बारे मे मै यह कहना चाहूंगा कि जितनी पावर्ज चैयरमैन को थी वह सारी पावर्ज निकालकर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को दी गई है। अध्यक्ष महोदय, यह भी हो सकता है कि आजकल बोर्डज ओर कार्पोरे ांज के जो चैयरमैंन लगे हुए है, उनको कुछ विधायक हो या पब्लिक के ऐसे आदमी लगे हो जिनको सरकार ने उपायुक्त समझा हो कि ये कार्य संचालन को ठीक तरह से चला सकते है अध्यक्ष महोदय, चीफ एडमिनिस्ट्रेट लगाने का बिल जब पहले आया था उस वक्त मैने उसको विरोध करते हुए यह कहा था कि सरकार पहले यह निर्णय कर ले कि आया व आई0 ए0एस0एस0 आफिसर्ज पर ज्यादा वि वास करती है

या जिन लोगो को उपायुक्त समझकर कि ये लोग ठीक तरह से काम कर सकते है, चैयरमैन बनाया था उन पर वि वास करती है या सरकार इनके हाथ से काम छोडकर आई0 ए0एस0एस0 आफिसर्ज को देना चाहती है। इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नोटिस मे बहुत सारे केसिज आए है कि जहा पर चीफ एण्ड मिनिस्ट्रेटर या मैनेजिंग डायरेक्टर करते है। मै पब्लिक अन्डटेकिग्ज कमेटी का मैम्बर रहा हूं और जो भी बाते हमने देखी है वे सारी यहां नही कही जा सकती है उसको रिपोर्ट सदन के सामने आ जाएगी । आमतौर से देखने मे आया है कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजिंग डायरेक्टर एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करते है और ये बोर्ड की कोई परवाह नही करते है। फाइल्ज मे कार्यवाही देखने के बाद हमारे नोटिस मे यह बता आई है कि नीचे के एम्प्लाइज से लिखा लिया जाता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर से यह बात डिस्कस कर ली गई है और बोर्ड से एप्रवल तक नही ली जाती । मै मंत्री महोदय से यह गुजारि ा करना चाहूंगा कि वे इस पर दोगारा सजीदगी से विचार करे । चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को और पावर्ज दी जा रही है इससे कही बोर्ड का ओर इनका क्लै ा न हो जाए । कही ऐसा न हो कि जो बोर्ड बनाया हुआ है वह सही मायनों मे काम ही न कर पाए । चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को इतनी पावर्ज आप डेलीगेट न कर दें कि चैयरमैंन लेजिस्लेटर्ज बनाए हुए है। तो सरकार को उन पर वि वास होना चाहिए । जब वहां पर जनरल मनेजर और सैक्टरी लेगे हुए है तो मुझे समझ नही आता कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर

लगाने की क्या जरूरत है या तो सरकार पब्लिक मैन और लजिरलेटर्ज को इनएफि ाएंट समझती है या उन पर सरकार को भाक है इसलिए चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लगा रही है अगर यह बात ठीक नही है तो इनको लगाने की क्या आव यकता है और जो इस बिल के जरिए चेयरमैन की पावर्ज छीनकर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को इतनी वाइड पावर्ज दी जारही है मे इसका विरोध करता हूं ।

दि पजाब एग्रीक्लचर प्रोड्यूस मार्किटस हरियणा थर्ड अमैडमैंट एंउ वैलिडे ान बिल,

डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी बात स्टेटमैंट के एमज एण्ड आबजैक्ट्स मे कही गयी है–

2. Further, recently by an enactmen levy, imposition assessment, collection and recovery of market fee in excess of 2 per cent has been validated, which has been retained by the dealers or the licensee and has been deposited with Market Committees by them, This has been challenged in the Superem Court. The Superme Court has granted stay in certain cases against bank guarantees whcih were discharged subsequently by the Supreme Court. The siad legislation did not provide for effecting recovery from them. The plea taken in the Challenge before the Court is that the impugned legislation is discriminatory. In order to enable the Board to recover the exces amout of market fee which was detained by the dealers after the discharge of the bank guarantees from the Courts it has been considered expedient to remove this lacuna.

यह दूसरा कारण है । इसके साथ की क्लाज 13 मे लिखा है–

"Nowtwithsanding anything contained in the principal Act, For in any other law for the time being inforce or judgement, decree or order of any court, any amout purportred to have been collected by a dealer or licensee as fee, in respect of any transaction in excess of the fee ieviable under section 23 of the principal Act and not deposited with any Committee, the burden of which has been passed on by the dealer or license to the next purchaser or whcih has been added towards the cost of the agricultural produce or the goods processedor manufactured out of it shall be deemed to have been validly levied, imposed, assessed or collected and spent for meeting the cost of services to be rendered towards the development and improvement of existing services to be rendered toward the develpment and improvement of existing markets where from the collection of such fee was made and accordingly (A) no suit or other legel proceedings shall be maintained or continued in any court for the refund of whole or andy part of the fee so collected and (b) no courts shall enforce any decree or order directing the refund the whole or any part of the fee so collected.

उपाध्यक्ष महोदय इसकी बैक ग्राउड यह है कि जो 2 से तीन परसेन्ट मार्किट फोस कर दी गई थी उसके खिलाफ लोगो ने रिटे दायर की और ये हाई कोर्ट ओर सुप्रीम कोर्ट के अन्दर गये। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसकी कापी मेरे पास है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एक तो जो 2 परसेन्ट से 3 परसेन्ट

मार्किट फीस बढाई गई है, यह गलत है और दूसरे यह कहा कि मार्किट फीस जिस परपज के लिय ली जाती है उसी ही परपज के लिये वह खर्च होनी चाहिऐ इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले मे यह भी है कि जो पैसा टैक्स के रूप मे लिया जाए उसका यूज तो दूसरे परपज के लिये भी हो सकता है लेकिन मार्किट फीस तो सिर्फ मंडियों की भलाई के लिये ही खर्च की जा सकती है मै आपको सिविल अपील नम्बर 1083 आफ 1977 और सिविल अपील न0 1616 आफ 1978 का हवाला देना चाहता हूं । जजमैंट के पेज 10 मे लिखा है।

" we may now extract some very useful and leading priciples form the decision of this court in Shirur Mutt's (1954S.C.R, 1005 Supra) pointing out the differences between tax and fee. At pages 1040-41 says Mukharjee J,, he than was"

:The second characteristic of tax is that it is an impoistion made for public purpose wihout reference to any special benefit to be conferred on the payer of the tax. This is expressed by saying that the levy of tax is for the purpose of general revenue, with when collected forms part of the public revenue of the State. As the object of a tax is not confer andy special benefit upon any particular indivdual, there is, as it said, no element of quid pro quo between the taxpayer and the publice authority----------"

(चौधरी राम लाल वधवा)

"a fee is generally defined to be a charge for a special service, rendered to individuals by some Governmental agency"

इसके बाद पेज 67 मे यह लिखा हुआ है–

"But taking a reasonable and practical view of the matter and on appeciation of the true picture of justifiable and legal expenditure in relation to the market fee incom, even though it had to be done on teh basis of some reasonable guess work we are not inclined to distrub the raising of an imposition of the rate of market fee up to Rs. 2/- per hundred rupees by the various market Committess and the Boards both in the State of Punjab and Haryana. After All considerable development work seems to have been done by many market committees in their respective markets. The Charging of fee Rs. 2/- therfore is justfied and fit to be sustained. We accordingly do it, As pointed out earlier the dealers of Haryan did not feel aggrieved whin the High Court maintained the raising of market fee to the extent of Rs. 2/-per hundred rupees. We are, however not inclined to up hold the raising of the fee from Rs. 2/- to Rs. 3/- as on the materials placed before us it is clear that amount of market fee can be spent for any develpment of agriculture and the welfare of the agriculturists. On the basis of the facts and figures placed befor us from the High Court records and also some new materials filed here we have come to the conclusion that there was no justification in law in raising the raising the fee Rs. 2/- to Rs. 3/-. The High Court was wrong in maintaining this rise on an erroneous view of the matter. We therefore allow the appeals and the Writ petitions to the extent in the manner indidcated abvoe and direct the

Market Committees and the State Marketing Boards not to realize market fee at the rate of Rs. 3/- per hundered ruppees on the basis of their impugned decisions and actions which have been found to be invalid by us. We leave the parties to bear their own costs throughout"

चौधरी रिजक रामः डिप्टी स्पीकर साहब, यह मामला पहले भी हाउस मे डिस्कस हो चुका है और हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अच्छी तरह से अवगत है इसलिये मै चौधरी राम लाल जी को यह प्रार्थना करूगा कि समय के अभाव के कारण मुक्तसर कर के कोट कर सके तो अच्छा रहेगा ।

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहब, पहली बात तो यह है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया है उनके खिलाफ अब सरकार दोबारा बिल ला रही है, यह कोई उचित प्रतीत नही होता । सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सरकार का उस पैसे पर कोई हक नही है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी फैसला है कि हाई कोर्ट द्वारा जो फैक्ट्स एण्ड फिगर्ज हमारे सामने रखे गये है और जो नये कागजात हमारे सामने रखे गए है, उनको देखने से पता चलता है कि मार्किट फीस 2 परसेन्ट से 3 परसेन्ट बढाने का सरकार का कोई औचित्य नही है मेरा कहने का मतलब यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि सरकार का इस पैसे के उपर कोई हक नही तो फिर सरकार यह बिल लाकर, जबरदस्ती रूपया वसूल करे तो यह एक गल्त प्रेसीडेन्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट के आडरों की स्पश्ट तौर

पर अवहेलना होगी । सरकार ने कहा कि हम वह रूपया वसूल करना चाहते है जब कि वह रूपया केवल डीलर्ज को ही मिलना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, जब सुप्रीम कोर्ट यह भी कह चुकी है कि यह जो लैवी लगायी गयी थी, वह उचित नही तो फिर मुझे समझ नही आती कि सरकार किस पैसे पर अपना हक जमाने के लिये यह बिल यहां पर लाई है ? फैसले मे स्पश्ट तौर पह कहा गया है कि 2 परसेन्ट मे 3 परसेन्ट जो मार्किट फीस बढायी गयी है वह ला के अनुसार उचित नही था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सरकार ने बैक गारन्टी दे रखी थी, वह भी सरकार ने वापिस ले ली है। तो फिर देखने की बात तो यह है कि आज सरकार किस बिनाह पर लोगो से रिकवरी करने के लिए यह बिल यहां पर लायी है ? इसलिये मै आपके द्वारा सरकार को कहूगा कि वह इस बिल को वापिस ले ले क्योकि पहली बात तो यह है कि यह लीगली बिल्कुल गलत है सरकार को ऐसे बिल को इस समय पर नही लाना चाहिए था मै इसका विरोध करता हूं ।

चौधरी जगजीत सिह पोहलू पाईः डिप्टी स्पीकर साहब, यह बात जरूरी बिल है और मै आपके जरिये सरकार को कहना चाहता हूं कि अभी बजट सै ान नजदीक है इसलिये इस बिल को विद्डा किया जाए । इसको विद्ड़ा करके इस पार्टी मीटिंग मे अच्छी तरह से डिस्कस करके तब इसमे अमैडमैंट लाई जाए । डिप्टी स्पीकर साहब, आज कल सरकार का सिर्फ तीन

कामों से ही काम नही चलेगा कि सरकार जान माल और इज्जत की रखवाली करे । हमारी स्टेट एक वैलफैयर स्टेट है और यह पर कांग्रेस भाई का राज है कांग्रेस भाई से हमे सबसे बडी उम्मीद यह है कि वह आम जनता का भला करें लेकिन आज कल आम जनता का भला नही हो रहा है बल्कि कुछ खास खास आदमियों का भला हो रहा है किसान हमारा अत्रदाता है और वह बहुत मुि कल से अत्र पैदा करता है। खेतो मे अपने परिवार के साथ वह दिन रात काम करके अपना अनाज मडियों मे लाता है और मडियो मे किसानो को पूरा इन्साफ नही मिलता है। इससे साफ जाहिर है कि जो आढती और दुकानदार आज लाखो पति बने बैठे है वे हमारे सिर पर ही बने बैठे है किसान बेचारा अपने अनाज को स्टाक नही कर सकता और ये दुकानदार लोग उस स्टाफ कर लेते है। आप जाकर देखे आज अनाज को स्टाक नही कर सकता और ये दुकानदार लोग उस स्टाक कर लेते है आप जाकर देखे आज अनाज की कई हजार बोरिया उन दुकानदारो के पास पडी है और आम जनता को वह दो सौ या पौने दो सौ बोरी के हिसाब से मिल रही है इसलिये मै सरकार से प्रार्थना करूगा कि ये जो दुकानदार है या मिडलमैन है इनको बीच से निकाल जाए। जितने भी कच्चे या पक्के आढती है इनको नौकरी के तौर पर मंडियो मे रखा जाये तभी किसानो का भला हो सकेगा । डिप्टी स्पीकर साहब, आज हर एक चीज मंहगी हो गई है और महगाई के टाइम पर सरकार की जिम्मेदारी और बढ जाती है इसलिये मै यह कहूगा कि जैसे हमारे पडौसी दे ा रि ाया मे

आज कोई भी गरीब आदमी नजर नही आता उसी प्रकार से हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस दे ा से गरीबी को दूर किया जाये।आज गरीबों की हालत बहुत खराब है उनके पास कपड़ा नही है जूता नही है और रहने के लिये मकान नही है और दुसरी तरफ कुछ आदमी बहुत ज्यादा साहूकार होते जा रहे है आज यहां पर बेरोजगारी का मसला आया है औन सुशमा जी तथा स्वामी जी रोज कहते है कि बेरोजगारी दूर करो। मै कहता हूं कि आप लोग मेरा साथ दो फिर मै बताऊगा कि बेरोजगारी कैसे खत्म होती है। इसके बाद जो इस बिल मे अमैडमैंट करक आफिसर्ज को पावर दी जारही है मै उसके खिलाफ हूं । अभी हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब सरदार तार सिंह जो सर छोटू राम के चेले है उन्होने इस बात को माना है कि हर एक भाुगर मिल मे घाटा है मै दावे के साथ कह सकता हू कि अगर इन मिलों पर अच्छा कन्ट्रोल हो तो ये दो तीन गुना ज्यादा फायदा दे सकते है। इसका मतलब यह है कि वहां पर गडबड है पूरी सुपरविजन नही है कुछ ही आदमियों ने उनका ठेका ले रख है डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा मे इतने गाव है और जितने भी मिनिस्टर यहा बैठे है ये किसी गांव मे नही जाते । ये यहां सैक्रेटोरिएट मे बैठते है और यहां से सीधे हरियाणा भवन मे जाकर ठहरते है बीच मे नही ठहरते । मैने राठी सहब से प्रार्थना की है कि आज कल नहरे पक्की हो रहीहै आप उनकी पूरी देख भाल करो आप जाकर देखे कि कहीं पर भी पूरा सीमेंट नही लग रहा हैं। मै मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूगां कि वे मौके पर जाकर छापे मारे और दोशी

अफसरो के खिलाफ कार्यवाही करके उनको हरियाणा से बाहर निकाले। मै सरकार से कहूंगा कि वह हर महकमे पर पूरी सुपरवीजन करे। बाबू मूल चन्द जी मेरे बुजुर्ग है ये पहले भी वजीर रह चुके है और अब पीछे तायल साहब की जगह भी वजीर रह चुके है लेकिन इन्होने किसानों का भला नही किया । इसके बाद मै गन्ने के भाव के बारे मे कहना चाहता हू कि जैसे यू0पी0 और पजाब ने गन्ने के भाव बढाए है उसी प्रकार से हरियाणा को इनसे भी ज्यादा गन्ने के भाव बढाने चाहिये क्योकि हमारा गन्ना किसी से कम नही है इन भाब्दो के साथ भाुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे टाइम दिया ।

स्वमी आदित्यवे I: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । आप नियम 100 देखे उसमे लिखा है

"The matter of egvery speech shall be strictly relevant to the matter before the Assembly"

चौधरी संत कवर हसनगढः डिप्टी स्पीकर साहब, मै आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। इस बिल मे जो अमैडमैंट आई है मै उसका विरोध करने की के लिये खडा हूं इसके सैक ान 3ए के अन्दर जो अमैडमैंट की जा रही है उसके जरिये चेयरमैन की बजाए तमाम पावर्ज चीफ एडमिनिस्ट्रेट को दी जारही है इस तरह से सैक ान 9 के तहत एक और अमैडमैंट लाई गई है जिसके जरिये सैक्रटरी की पावर भी चीफ एडमिनिस्ट्रेट को सोपी जा रही है। ये सारी की

सारी ताकत एक आदमी के हाथ मे सोपने जा रहे है। इससे हमारा और हाउस को डर है कि चीफ एडमिनिस्ट्रेट इस पावर का मिसयूज करेगा। डैमोक्रेसी के अन्दर और खास तौर पर जब यह एक्ट पजांब मे लागू हुआ था तो इसे सबसे पहले सर छोटू राम ने लागू किया था अब इस प्रदे ा की बदकिस्मती यह है कि इस प्रदे ा की सरकार ने.....

श्री उपाध्यक्षः जिस बात की इस बिल से कोई रैलेवसी नही है यह रिकार्ड न की जाए।

लोक निर्माण मंत्री कवर राम पाल सिहः डिप्टी स्पीकर साहब, जो भाब्द चौधरी संत कवर जी ने कहे है वे एक्सपंज हो गए है या नही ?(ाोर एवम विध्न)

13.00 बजे

श्री उपाध्यक्षः यह मैने पहले ही कह दिया कि वे भाब्द रिकार्ड मे नही आएगे। (ाोर)

डा0 मंगल सैनः डिप्टी स्पीकर साहब,..... (ाोर एवम विध्न)

Local Government Minister Chaudhri Khurshid Ahmed: That has got no relevancy with this Bill.

चौधरी संत कवरः डिप्टी स्पीकर साहब, सरदार तार सिंह जी ने जो बिल हाउस मे पे ा किया है इन्होने इस बिल की

क्लाज 13 मे कुछ कमिया छोड दी है । मै आपके माध्यम से उन कमियों के बारे मे इनको कुछ सुझाव देना चाहता हूं अभी वधवा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे मे बताया कि पहले जो एक परसेंट मार्किट फीस बढाई थी और उससे जितना पैसा वसूल हुआ था वह पैस मंडी की जुरिसडिक ान के अन्दर ही खर्च किया जा सकता है डिप्टी स्पीकर साहब, मै आपके द्धारा मंत्री जी को इस बारे मे एक सुझाव देना चाहता हूं कि इस बिल मे यह भी अमैडमेंट आनी चाहिये थी कि जो किसान गड्डो मे या गाडियो मे लाद कर जिस रास्ते से या सड़क से अपन अनाज मण्डियो मे लाते है, वह पैसा उन सड़को की मुरम्त के लिय, जो उन सड़को पर पुलियां वगैरह टुटी पडी है उनकी मुरम्मत के लिए गावो को मडियो से जोड़ने के लिये सडक बनाने के लिये, किसानो के लिये मंडी के पास धर्म ाला बढाने के लिय जिसमे किसानो को इस किस्म की व्यवस्था हो कि वे अपने बैल उसमे बाध सके ओर उन के लिये चारा बगैरह रख सके ऐसे कामो पर खर्च होना चाहिए था डिप्टी स्पीकर साहब, इसके अलावा मै आपके द्धारा एग्रीक्लचर मिनिस्टर साहब को एक और सुझाव देना चाहता हू कि जो मार्किट फीस का पैसा है उसके तहत फसल बीमा योजना भी बनाई जा सकती है तो चाहे किसानो पर टैक्स न लगे। यदि आप फसल बीमा योजना बना दें तो चाहे किसानो पर एक करोड रूपए के टैक्स लगा दे, हमे इसमे कोई एतराज नही है । डिप्टी स्पीकर साहब, इन भाब्दो के साथ मै आपका भाुक्रियां अदा करता हू ओर

इस बिल का विरोध करते हुए मै मंत्री साहब जी से प्रार्थना करूंगा कि मैने जो सुझाव दिए है उनके उपर गौर करे । धन्यवाद

श्री मांगे रम गुंप्ता जींदः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पजांब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किटस हरियाणा थर्ड अमैडमैंट एण्ड वैलीडे ान बिल, 1980 सदन मे पे ा हुआ है मै उसका समर्थन करने के लिए खडा हुआ हू उपाध्यक्ष महोदय, जब 1977 मे हरियाणा असम्बली के चुनाव हुये थे उस समय जनता पार्टी ने लोगो से यह कर वोट मांगे थे अगर जनता पार्टी की सरकार बनी तो जो आप लोगो पर इतने टैक्स लगे हुए है और जिनका बोझ कज्यूमर्ज पर पडता है जिसके कारण महगाई बढती है, वह हम कम कर कम देगे । उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा समय आया कि जनता पार्टी की सरकार बनी और चौधरी देवी लाल जी उस सरकार के मुख्यमंत्री बने तथा डा0 मंगल सैन जी उस सरकार मे नम्बर 2 मे मंत्री बने थे भाोर । उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी राम लाल वधवा अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि जो एक फीसदी मार्किट फीस बढाई गई थी उससे जो पैसा वसूल हुआ है वह मडी की जरिसडिक ान के अन्दर खर्च होगा ।उपाध्यक्ष महोदय, वधवा साहब उस समय की जनता पार्टी की सरकार के लीगल एडवाइजर थे इन्होने उस वक्त यह नही देखा कि इस मार्किट फीस को दो से तीन परसेंट क्यों बढाया जा रहा है हमने भी उस समय इस फीस को दो से तीन परसेट बढाने का विरोध किया था लेकिन

इन्होने उसकी परवाह न करते हुए मार्किट फीस दो से तीन परसेंट बढा दी । उपाध्यक्ष महोदय, हमने उसकी मुखालफत यहां हाउस मे ही नही की बल्कि बाहर पब्लिक मे भी की थी । यह रिकार्ड की बात है । हमने मुखलफत इस अदें ो से नही की थी जो मैरे विरोधी भाईयो को अदें ा है ये उस समय टैक्स की दर चाहे कितनी ही बढा देते उससे हमे कोई एतराज नही था। और न ही उससे व्यापारियों को कोई फर्क पड़ता था लेकिन इस फीस को बढाने से आज जितने भी व्यापारी है, वे सब टैक्स की चोरी करने के आदी हो गए है और उनको इस टैक्स की चोरी करने को बढाया मिला है । अभी पिछले दिनों चने का भाव 500 रूपये पर क्विटंल था अगर कोईं कज्यूमर एक बोरो चने की खरीदता है तो उसे 40 रूपये टैक्स के रूप मे देने पड़ेगे यदि वह 40 रूपये टैक्स के देता है तो उसे बहुत महसूस होता है इसलिये वह टैक्स चौरी करेगा । जैसे एक जमीदार अपनी पांच बोरी चने की रेहडी या गड्डे मे डाल कर मंडी मे बेचने के लिये ले जारहा है और रास्ते मे उसको एक चक्की वाला कहता है कि भाई तू ये पांच बोरियां मुझे देदे और मे तेरे को 500 रूपये क्विटंल के हिसाब से इसके दाम यही पर दे देता हूं वरना तू मडी मे जाएगा तो सारा दिन तेरे को सड़क पर धूप मे रहना पड़ेगा। इसलिए डिप्टी स्पीकर साहब, यदि वह जमीदार अपनी पांचो बोरिया उस चक्की वाले को दे देता है तो उसकी वही पर 500 रूपये के हिसाब से दाम मिल जायेगे लेकिन उस चक्की वाले को, यदि वह मंडी मे जाकर खरीदता तो उसको 8 परसैंट के हिसाब से जो टैक्स देना पड़ता

उससे वह बच जाएगा । इस तरह से लोग टैक्स को चोरी की बात नही है।

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मै तो वह कह रहा हूं कि टैक्स बढाने से लोग दो नम्बर का काम करेगे के आदी हो गए है। जितने टैक्स बढते जाएगे उतना ही ज्यादा दो नम्बर का काम करेगे । इस फीस को बढाने पर व्यापारियों ने एजीटे न किया था उस समय जो मेरे भाई इधर उधर बैठे है, इनकी सरकार थी । उसने व्यापारियों पर अत्याचार किए और पुलिस ने उन पर लाठिया बरसाई। उसके बाद व्यापारियों ने मजबूर हो कर एक परसेंट मार्किट फीस बढाने के खिलाफ हाई कोर्ट मे अपील की थी लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी अपील नही मानी। फिर उसके बाद उन्होने सुप्रीम कोर्ट मे अपील की । उन्होने सुप्रीम कोर्ट मे अपील इस पैसे को वापिस लेने के लिये नही की थी । बल्कि इसलिये की थी कि वह जो दो से तीन परसेट मार्किट फीस बढाई गई है वह गलत है और यह नही बढानी चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहब, अगर आज हमारी सरकार की तरफ से भी इस बिल मे यह बात आती कि मार्किट फीस दो से तीन परसेंट कर दी जाये तो मै इस बिल का विरोध करने के लिये खडा होता । डिप्टी स्पीकर साहब, उस समय की जनता पार्टी की सरकार ने जो एक परसेंट मार्किट फीस बढाई थी औा उससे जो पैसा वसूल हुआ था वह खर्च हो चूका है तो अब वह पैसा वापिस करने के लिए किस को कहा जाये ? दूसरी टैकनीकल बात इसमे यह है कि जो एक

परसेंट फीस बढाने पर पैसा वूसल हुआ था वह किसको वापिस किया जाए। क्योंकि पैसा किसी इडिवीजुयल की जेब से नही निकला ? किन किन की लिस्ट बनाई जाये ओर किन किन से कलैक ान की जाए ।इस बात से मै समझता हूं कि सारे हरियाणा मे एक फीसदी कंज्यूमर को भी फायदा नही हो सकता और न ही किसी व्यापारी को फायदा हो सकता है। केवल एक फीसदों ऐसे व्यापारी है जिन्होने अपील की है छोटे व्यापारियों मे से किसी ने अपील नही की । डिप्टी स्पीकर साहब, मै कहना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के साथियों ने जो हमदर्दी दिखाई है वह सही हमदर्दी नही है। क्योकि यह जो आज दिक्कत आई है यह इनकी करतूस से आई है (विध्न) डिप्टी स्पीकर साहब, मै आपके द्धारा सरकार ने दरखास्त करूगा कि चाहे मार्किट फीस हो चाहे कोई और टैक्स हो उसके रेट को बिना सोचे समझे बढाने की कभी कोि ा ा नही करनी चाहिए । इन भाब्दो के साथ मै इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री मूल चन्द जैन सभालकः डिप्टी स्पीकर साहब, पहले तो बिल क्या है इसको अगर हम समझ ले तो बेंहतर रहेगा। जहा तम मै समझा हू सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ दिक्कत आई है । जब दो परसेंट से बढा कर मार्किट फीस तीन परसेंट की गई तो कुछ व्यापारी हाई कोर्ट मे गए । हाई कोर्ट ने पोजि ान वैसी की वैसी रखी । फिर वे लोग सुप्रीम कोर्ट मे गए। सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ फीस तीन परसेट से घटार कर दो परसेंट की बसि घटार

कर दो परसेंट की बल्कि और भी कुछ ऐसी बाते कह दी जिसकी वजह से आज यह परीस्थिति पैदा हुई । उस परिस्थिति को हल करने के लिये एक बिल तो पहले आया जिसे हाउस मजूर कर चुका है। बात यह थी कि मार्किट फीस का रेट दो से तीन परसेंट होने के कारण जो फालतू रूपया इकट्ठा हुआ था उसे कुछ डीलर्ज ने तो मार्किट कमेटीज के पास जमा करवा दिया लेकिन कुछके ने अपने पास रख लिया ।पिछले सै ान मे हमने जो कानून बनाया उसमें यह था कि जो पैसा मार्किट कमेटीज के पास डिपाजिट किया जा चुका है । उसे वापस न किया जाये। इससे क्या हुआ ? डीलर्ज फिर सुप्रीम कोर्ट मे चले गए ओर कहा कि यह जो कानून बना है यह डिसकिमिनेटरी कानून है क्योंकि जिसने पैसा डिपाजिट कर दिया है उसे तो पैसा वापस नही दे रहे है लेकिन जिन डिलर्ज ने उस पैसे को अपनी वही खाते और तिजेरियों मे रखा है। उनसे से नही रहे है लिहाजा डिसक्रिमिने ान ने आधार पर इस कानून को रद् किया जाये। आज उस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये कि जो रूपया मार्किट कमेटीज के पास जमा हो चुका है वह भी वापस न हो तथा जो व्यापरियों की तिजोरियों मे रह गया है वह भी मिल जाये यह बिल लाया गया है। यह इस बिल का एक आसपैक्ट है लेकिन इस अमल कहा तक होगा इस बात का मुझे भाक है।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक अवजवै ान मे और करना चाहता हूं ये अब चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को पावर्ज देना चाहते है।

पहले इन्होने आडिनेंस द्वारा और अब कानून बनाना चाहते है। यह तो तारा सिंह भी मानेंगे कि इसके मायने ये है कि जो इन्होने मार्किटिंग बोर्ड का चैयरमैंन बनाया है उस पर इनको एतबार नही है।

सरदार तारा सिंहः बाबू जी, आप पोलिटिकल बात न करें ं हमे चेयरमैन साहब पर पूरा एतराम है।

श्री अध्यक्षः बाबू जी जरा जल्दी समाप्त कीजिए ।

श्री मूल चंद जैनः मै ज्यादा देर नही लगाऊगां लेकिन मुझे एक बडी इम्पोटैन्ट बात की तरफ हाउस की तवज्जह दिलानी हैं ।डिप्टी स्पीकर साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो परिस्थिति पैदा हुई उसका मुकाबला हमारी सरकार ने पूरी तरह से नही किया ।सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4.5.1979 को हुआ था । मार्किटिंग एक्ट की धारा 16 और 28 तथा उनकी बहुत सी क्लाजिज को उन्होने गलत करार दे दिया। उन क्लाजिज मे से कितनी सारी क्लाजिज के नीचे उस वक्त से पहले किसानों की भलाई के लिये पैसा खर्च हुआ करता थां लेकिन उन्होने कह दिया कि मार्किटिंग कमेटीज अब उस खर्च को नही कर सकती । यही नही उन्होने यह भी कह दिया कि मार्किटिंग बोर्ड अब उस खर्च को नही कर सकती। नतीजा क्या हुआ? इस वक्त मेरे ख्याल मे 10.11 करोड़ ंरूपया मार्किट कमेटीज के पास जमा पड़ा है लेकिन वे उसे खर्च नही कर सकती क्योकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके हाथो

मे हथकडिया डाल दी है । डिप्टी स्पीकर साहब, मैने इस संबध मे एक मो ान दी थी लेकिन मै जानना चाहता हूं कि उसका क्या हुआ ? फायदा यह है विधान सभा सचिवालय मे मो ान दी जाती है और आप उस पर गवर्नमैंट से कमैन्टस मांगते है परन्तु अफसोस यह है कि गवर्नमैंट के कर्मचारियों ने, तारा सिंह जी के कर्मचारीयों ने उस पर अजीब सी बात लिख दी। डिप्टी स्पीकर साहब,जैसा मैने पहले कहा कि करोडो रूपया जो हर साल हरियाणा के कंसौलिडेटिज फण्ड मे मार्किटिंग फीस से जमा होता था वह अब जमा होना बन्द हो गया है और ज्यों का ज्यों कमेटीज के पास पड़ा हुआ है मेरे यहां अकेली संभालका मार्किट कमेटी की 30–40 लाख रूपये की आमदनी है लेकिन उस रूपये का क्या करें क्यो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके खर्चे पर पाबन्दी लगा दी है।एल0आर0 का रैफर करते है। वह कह देते है कि चूकि सुप्रीम कोर्ट ने पाबन्दी लगा रखी है इसलिये यह रूपया खर्च नही हो सकता । इस परिस्थिति का मूकाबला हरियाणा सरकार को करना चाहिये।सन् 79 का यह फैसला है इन्होने डेढ वर्श तक कोई विचार नही किया मैने जब मो ान दी ता पता नही सैकेटरी ने या डिप्टी सेक्रेटरी ने उस पर लिख दिया कि जैन साहब जो यह बात कर रहे है वह यह जो बिल आ रहा है इसमे आ जाएगी। मिनिस्टर साहब मुझे बात कर रहे है वह यह जो बिल आ रहा है इसमे आ जाएगी। मिनिस्टर साहब मुझे बताएं कि इस बिल मे वह बात कहां कवर होती है ? इसके डिपार्टमैंट ने इनको यह कह कर मिसगाईड किया है कि जो बात जैन साहब कर रहे है

वह ऐटिसिपेटरी है। जब मुझे इस बात का पता लगा तो मैने ऐटिसिपे ान वाली बात को स्टडी किया और कल कालावाली केस मे हाउस मे कहा भी कि चीफ मिनिस्टर साहब मामले को ऐटिसिपेड करना चाहते है। लेकिन मेरी मो ान ऐटिसिपेटरी नही थी । मै सरदार तारा सिंह जी को कहना चाहता हू कि वे अपने अफसरान को, जिन्होने लिख दिया कि मेरी मो ान ऐटिसिपेटरी है वार्न करे।

चौधरी खुरदी ा अहमदः बाबू जी कोई ठोस सुझाव दीजिए ।

श्री मूल चंद जैनः मेरा सुझाव यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत से अबजर्वे ान्ज ओबिटर डिक्टा होते है तथा उन पर अमल करना जरूरी नही होता। ये जो आपके लीगल ऐडवाजर्ज ए0एल0आर0, एल0आर00 और दूसरी आफिसर्ज कर रहे है कि मक्खी पर मक्खी मारो यह ठीक नही है। जो रैलैवेन्ट बात थी, जिसक उपर सुप्रीम कोर्ट न डिसिजन देना था, वह तो ला बन गया, ला आफ दि लैंड बन गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अबजर्वे ान्ज कर दी है, उन पर अमल करने के लिये हमारी सरकार और सरकार के कर्मचारी पाबन्द नही है।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि कम से कम इतना नैरो इन्टरप्रटे ान न करे । मै सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग लाया हूं यह आल इडिया रिपोर्टर जुलाई 1956 मे छपा है।

"That construction of link roads, culverts and bridges anywhere is a notified market area is not covered by clause viii os section 28. In the context of the Languplain that what is meant by"construction and repari of approach roads; culverts, bridges" is only for the puropose of the facillity of going into the market from the nearest public road. Supposing a market has been established consisting of principal market yard or sub-market yeads carts or the trucks and other vehicles to go, then approach road and if necessary even culverts and bridge may be constrcted, or repaired out of the Market Committee fund"

मुझे अफसोस है कि किस अफसर ने क्या कहा , क्या नही कहा लेकिन इतनी नैरो इन्टरप्रटे ान दी है जिसके बारे मे कुछ नही जा सकता । सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है कि मार्किट कमेटी यार्ड बनाये। सरकार ने लीगल एडवाईजर कहते है कि एक सड़क दे सकते है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ले लिखा है कि अगर 6 या 10 अप्रोच रोड चाहिये तो दे सकते है एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हाथ बांध हुए दिए दूसरी तरफ हमारे लीगल एडवाइजरी ने हाथ बांध दिए कि एक ही अप्रोच रोड बना सकते हो। मैने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ कर सुनाया कि किसी पर्टिकुलर जगह पर पहुचने के लिये कई अप्रोच रोड जो जरूरी हों वे सब ही बनाई जा सकती है।

तीसरी बात मै यह कहना चाहता हू कि बजट सै ान से पहले एक कमेटी बनायी जाय जिसमे सीनियर अफसर भी हो और अपोजि ान के मैम्बर भी हों । वे इस बात पर विचार कर

कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो परिस्थिति पैदा हुई है, उसको कैसे हल करे, यानि इस पैसे को कैसे खर्च करे ? छटी प्लान के बारे मे हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने हाउस मे कहा था कि मार्किट कमेटियां से 100 करोड रूपया वसूल करैगे। कैसे करेगे? इसलिये यह जरूरी है कि संजीदगी से विचार करे। हमारी भी पूरी को–आप्रे ान होगी ।

बैठक का समय बढाना ।

श्री उपाध्यक्षः अगर सदन सहमत हो तो बैठक का समय 3 बजे तक बढा दिया जाये। क्योंकि हाउस के सामने अभी बिजनैस है?

आवजेः ठीक है जी ।

श्री उपाध्यक्षः बैठक का समय 3 बजे तक बढाया जाता है।

दि पजाब एग्रीक्लचर प्रोड्यूस मार्किटस (हरियणा थर्ड अमैडमैंट एंड वैलिडे ान) बिल, 1980 (पुनरारम्भ)

श्री मूल चन्दः डिप्टी स्पीकर साहब, जो बिल हाउस के सामने आया है मै उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ है जंहा पर सरकार चीफ एड मिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने जा रहे है वहां पर पहले ही चेयरमैन मोजूद है। उस चेयरमैन की निगरानी के लिए चीफ एडमिनिस्ट्रेटर क्यों लगाया जा रहा है? मै जानता हूं कि

सरकार जो अमैडमैंट लायी है उसमे खर्चा बढा है, घटा नही है । सरकार जनता के उपर और बोझ डाल रही है अगर कोई चैयरमैंन इनएफीि ायंट हो और उसको हटाकर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जा रहा हो तब तो ठीक है । लेकिन डुप्लीकेट खर्चा करके बहुत ज्यादती होगी।इस बिल के स्टेटमैंट आफ आब्जैक्टस एंड रीजन्ज मे लिखा है कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लगाने जा रहे है। मै तो कहता हू कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की कोई जरूरत नही ।

डिप्टी स्पीकर साहब, जब सरकार ने 3परसेंट मार्किट फीस की थी, उस वक्त भी मैने विरोध किया था। मैने कहा था कि ऐसा करने मे महंगाई भी बढगी और गरीब आदमी भी परे ाान होगे जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि बढाई हुई फीस को वापिस करो तो अब उन लोगो से भी इस बिल के जरिए वसूल करना चाहते है, जिन्होने पैसे जमा नही करवाए जबकि मार्किट फीस का पैसा गरीब किसानो और गरीब दुकानदार से ही वसूल किया जाता है इसलिए उनका पैसा वापिस होना चाहिए।

जैसा कि जैन साहब ने कहा है कि जो पैसा मार्किट कमेटिया मे जमा है वह गरीब किसानों और गरीब मजदूरो का है । इसलिए यह उन्हे वापिस किया जाये। जो फैसला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो अगर उसको हम न माने, तो बडी ज्यादती होगी। अगर इस प्रकार की ज्यादती होती रहे तो हरियाणा सरकार पर से लोगो का वि वास हट जायेगा । जो सरकार लोगों की रक्षक न हो वह ज्यादा दिन नही चल सकती।

उपाध्यक्ष महादेय, एक बात और चाहता हू कि आगे जो बिल आ रहा है उसमे प्राईवेट कालेजो को जो 70 परसेट ग्रान्ट दी जा रही है वह बहुत कम है। जब वह बिल आयेगा तो उस टाईम पर मै बोलूगां आ ाा है कि आप मुझे टाईम भी देगे। उस समझ सही बताऊगा अब मै चाहता हू कि यह बिल पास न किया जाये।

श्रीमतीसुशमा स्वराज(अम्बाला छावनी): उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब कृशि उपज मण्डी हरियाण तृतीय सं ाोधन तथा विधि मान्यकरण विधेयक, 1980, कृशि मंत्री महोदय ने सदन मे पे ा किया है(ाोर) अगर आपका कोई वास्ता नही है तो कम से कम मुझे तो बोल लेने दीजिए। (ाोर) उपाध्यक्ष महोदय दो अलग अलग अध्यादे ा जारी करके इस बिल को लाया गया है इसलिये इस बिल के पास होने पर इसके परिणाम भी दो ही होने है और इस बिल के पार्ट भी दो ही है। उपाध्यक्ष महोदय, जंहा तक पहले पार्ट का ताल्लुक है, मै सरकार को बधाई इस बात के लिये देना चाहूंगी कि कम से कम पहली बार तो इन्होने अपने उपर लगेहुए इनएफिसिएंसी के आरोप को कबूल किया है। (ाोर) उपाध्यक्ष महोदय, आपने असैम्बली के अन्दर बहुत बार हम लोगो को बोलते हुए सुना है। (ाोर) उपाध्यक्ष महोदय, असैम्बली के बाहर और असमैबली के अन्दर अपोजि ान ने यह आरोप तो सरकार पर बहुत बार लगाया है कि सरकार अपने प्र ाासनिक ढांचे मे बिल्कुल ही इन एफि िाएंट रही है और कोई भी काम

कार्यकु ालता ने नही किया जा रहा है लेकिन इस बिल के जो ऐम्ज और भाव जैक्टस है उसकी तरफ मै आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं उसमे लिखा हुआ है कि हरियाणा राज्य कृशि मण्डी बोर्ड के कामकाज मे बढिया, दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण और प्रभाव ाली तालमेल लाने के उद्दे य से सरकार यह बिल लाई है जिस का अग्रेजी मे ट्रांसले ान यह होता है with a view to achieving better efficiency, closer supervision and effective coordination in the working of the Haryana St te Agricultural Marketing Board.यानी ये मानते है कि उनके बोर्ड मे अब तक न कोई कलोजर सुपरविजन थी न वैटर एफि िाएंसी थी और न ही इफैक्टिव कोग्राडिने ान जी। तो मै कहना चाहती हू कि इनको इनके आगे वि ोशण लगाने की कोई आव यकता नही थी ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो एक रवायात हो गई है। इसको सीधे सीधे भाब्दो मे यह कहा जा सकता है कि इनके बोर्ड मे अब तक न तो वैटर एफि सएंसी थी न ही क्लोजर सुपरविजन थी और न ही इफैक्टिव कोग्रोडिने ान थी। अब ये चीजे लाने के उद्दे य से यह सं ाोधन इस बिल मे लाये है उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव मे ये भी क्या करे ? इनकी भी मजबूरी है। चौधरी भजन लाल जी की तो यह मजबूरी है कि उन्होने तो किसी भी हालत मे सुक्ष्य मंत्री रहना है और इस के कारण यह भी उनकी मजबूरी है कि अगर उनको मुख्यमंत्री रहना है तो अपने साथ बहुमत भी रखना जरूरी है। यदि बहुमत रखना है तो यह भी जरूरी है कि अपने साथ साथियों को रखने के लिये किसी को मंत्री पद की

झण्डी, किसी को उपमंत्री पद कीा झंडी और किसी को चेयरमैन का पद देना है। इसी मजबूरी के कारण ही ये उनको सुविधा दे रहे है वरना उनका मुख्यमंत्री पद छूट जायेगा। इसी मजबूरी के कारण उनको ये पोलिटिल पोस्टे बाटनी पड़ी है। लेकिन इतनी पोलिटिकल फेवर्ज बाटने के कारण इनएफि ाएसी भी आती है जिसकी वजह से इनको सफर करना पड़ता है। कोई भी मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिये यदि सारे प्र ाासनिक ढाचे को खराब कर दे तो यह बर्दा त नही होता। मार्किटिंग बोर्ड का काम चलाने के लिए एक अच्छे मुख्य प्र ाासक की जरूरत है उपाध्यक्ष महोदय, अपना अपना दृश्टिकोण होता है । वास्तव मे मेरा तजुर्बा इस पूरी समस्या के प्रति अब तक यह रहा है कि पैसा कम खर्च करे और काम न चले । इसकी बजाय अगर पैसा ज्यादा खर्च करे और कम खर्च और काम चले तो वह कम ज्यादा अच्छा है आप जैसे बिल्कुल खर्च न करें और इस वजह से आपके सारे वीर्डज और कार्पोरे ान्ज मे इनएफि ाएसी आए तो इसकी बजाये कही ज्यादा अच्छा है कि हम ऐसा अधिक खर्च करे ताकि हम उनमे एफि ाएंसी ला सके । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इसी सिद्धान्त को सामने रखते हुए और इसी प्रिसिपल को मानते हुये पहले भी इस तरह, के बिल आये थे । वे बिल हाऊसिंग बोर्ड के मुतालिक, ऐग्रोइण्डस्ट्रीज कारपोरे ान के मुत्तालिक और खादी एण्ड विपेज बोर्ड के मुत्तलिक थे। जब हमने इन का समर्थन किया था । उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम लोंगो ने अपने काम मे एफि ाएंसी लानी है तो उसके लिये अगर हमे ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़े

तो कोई हर्ज नही । मै नही चाहती कि बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ हमारे बीर्डज और निगमो पर पडे लेकिन अगर ज्यादा पैसा खर्च करके हम एफिि ाएंसी ला सकते है । तो वह कही ज्यादा अच्छा होगा। इस लिये पहले पार्ट का तो इस सिद्धान्त को ध्यान मे रखते हुए समर्थन करती हू लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक दूसरे पार्ट का तालुक है, मुझे यह कहना पडेगा कि ट्रेजरी बैचिंज के लोगो ने भी इस की स्पिरट को नही समझता है कि मेरे से पहले बोलने वाले मेरे साथी श्री मूल चन्द जैने जी ने इस बात को समझा है कि इस का आप्रेटिव पार्ट क्या है उपाध्यक्ष महोदय, इसके मुत्तालिक मै यह कहना चाहूगी कि पिछले अधिवे न मे इस बिल मे जो अमैडमैंट आई थी उसमे कहा गया था कि हम डिपाजिटिड फीस का रिफण्ड नही करेगे । उस बिल से तो हमारा विरोध था और बहुत पुरजोर विरोध हम लोगो ने किया भी था ।लेकिन हमारे विरोध था और वह बिल पास हो गया था। आज जो अमैडमैन्ट आई है, यह विरोध के काबिल नही है क्योकि उस पुराने बिल मे जो कमी रह गई थी उस कमी को इस अमैडमैंट द्धारा दूर किया जा रहा है पुराने बिल का वाकई ही विरोध किया जाना जरूरी था । जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जो मार्किट फीस बढी है, वह गलत है और एक्स्ट्रा वसूल की गई फीस वापिस की जाये लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उस बिल को ले आये और यह कहा कि इस फीस को वापस करना प्रैक्टिकेबल नही है, व्यवहारिक नही है उपाध्यक्ष महोदय, इनसे एक नई परिस्थिति पैदा हो गई कि जिन लोगो ने फीस जमा करा दी थी

उन को तो रिकण्ड नही करेगे लेकिन जिन्होने जमा नही कराई है वह उनके पास रहेगी । इसलिए जिन लोगो की फीस ये रिकण्ड नही कर रहे थे उन लोगो ने सुप्रीम कोर्ट मे एक रिट दायर कर दी और कहा कि बडा भेदभाव पूर्ण लैजिस्ले ान हरियाणा विधान सभा ने पास कर दिया है ।हम जिन लोगो ने फीस दे दी है, हमे तो वापस नही कर रहे है और जिन्होने नही दी है उनसे उगाही या वसूली का कोई प्रावधान इस बिल मे नही किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज का बिल महज इतना है कि जिन लोगो ने उस समय फीस डिपाजिट नही की थी उनसे भी अब वसूल की जा सकेगी। यह इस बिल की स्पिरट है तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि मार्किट फीस दो फीसदी रहनी चाहिये तो मै समझती हू कि एक फीसद फीस रिफण्ड होनी चाहिए थी । उसको रिफण्ड कराने का कोई भी तरीका निकाला जा सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते है कि इस दुनिया मे कोई भी चीज असभव नही है, ब ार्ते कि नियत उसके पीछे करने की हो । भाई मांगे राम गुप्ता ने यह कह दिया कि वापस तो होनी चाहिए थी लेकिन उनको वापस करने का कोई प्रैक्टिकल वे नही था मै पूछना चाहती हू कि क्या सरकार के पास भी किसी चीज का कोई प्रैक्टिकल नही है। आप पहले डीलर्ज को वापस करे फिर डीलर्ज ने जिन लोगो से वसूल की है वे उन को वापस करे । वाकई मे ही यह एक डिसक्रिमिनेटरी लेजिसले ान था जो

पिछले सै ान मे पास हुआ था। डिसक्रिमिनेटरी लेजिसले ान होने के कारण यह स्टक डाउन भी हो जाता । सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को रैगुलेट करने के लिये ही आज यह बिल लाया गया है इसमे यह प्रोविनज है कि जिन्होने फीस डिपाजिट कर दी है उनको तो रिफण्ड नही करेगे और जिन्होने डिपाजिट नही की है उनसे वसूल करके सबको समान रास्ते पर लाना है।मै इस बिल के सैकिण्ड पार्ट के बारे मे तो यही कहना चाहूंगी कि आज भी अगर सरकार के अन्दर कोई गैरत है और न्यायालय के किसी आदे ा को इनको मानने की इच्छा है तो सुप्रीम कोर्ट के उस पुराने डीसीजन को वैलिड करार देते हुए इनको पेयरेन्ट एक्ट भी वापस लेना चाहिए ताकि डिपाजिटड फीस वापस हो सके और दूसरे से वसूल करने की जरूरत न पडे । यह कहते हुए मै अपना स्थान लेती हू।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह उचांना कलाः डिप्टी स्पीकर महोदय, जो बिल सदन के सामने पे ा किया गया है इसको दो हिस्सो मे तकसीम किया जा सकता है एक मे तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को जो पावर्ज दी गई है, उन का वर्णन है उनकी डिटेल मै तो मै जाना नही चाहूगा सिर्फ यही करूगां कि देखने की बाता यह है कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लगने से जो हमारी कारपोरे ानज या बोर्डज है उनमे एफि ाएंसी आयेगी भी या नही । यह बात अभी कहना कि एफि ाएसी नही आयेगी ंया आ सकती है यह गलत सी बाता होगी दूसरी बात इस बिल के बारे मे हमारे

विपक्ष नेता श्री मूलचन्द जैन जी ने कहा है उन्होने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसकी लाईट मे बात करने का मोका सदन को मिला है यह बात तो दरूस्त है कि 10 करोड़ रूप्ये के करीब जो इस अमैडमैंट द्वारा प्रस्ताव होगा वह कन्जयूमर्ज या डीलर्ज मे तो वापस बाटा नही जा सकता । लेकिन इसके साथ ही साथ एक और स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो मार्किट फीस होगी वह सिर्फ मण्डी के एरिया मे यानी मण्डी की जुरिसडिक ान के अन्दर खर्च होगी । वह पैसा मण्डी की चार दिवारों के अन्दर ही खर्च हो सकता है उपाध्यक्ष महोदय, मण्डी एक्ट आज के करीब 40 साल पहले किसाने के हित के लिये बनाया गया था उस समय किसान की अज्ञानता के कारण उनके भोलेपन के कारण उन्हे काफी परे ाान होना पडता था चौधरी छोटू राम ने किसानो की अज्ञानता को और उनके भोलेपान को ध्यान मे रखते हुए यह बिल बनाया था उसके बाद कुछ कुदता ने भी साथ दिया। देहांत के अन्दर भी जागृति आई और आज किसान का बेटा पढा लिखा हो गया है आज के दिन यह माना जा सकता है कि मार्किट कमेटीज के अन्दर जहा किसान फसल बेचने जाता है यदि उनकी लूट के बारे मे कही से भी थोडा बहुत सुराख मिलता है तो उसके खिलाफ जददोजहद करते है और सत्याग्रह करते है इसलिये आज के किसान मे बहुत ही जागृति आ गई है लेकिन जो मार्किट फीस है वह करोडो रूपये मे जमा हो रही हैं। यदि 2 प्रति ात मार्किट फीस लेकर भी चले तो भी 14 करोड़ रूपये सालाना के करीब पैसा बनता है उपाध्यक्ष महोदय, आप देख कि अगर 14 करोड

रूपये को मण्डी मे ही खर्च करेगे then we are only making pyramid of caoncerete in the madies. उसका कोई लाभ किसानों को या जो वहां का व्यापारी है या जो वहां का कमी ान एजेट है नही पहुच सकता ं इस ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते है। हम वहां पर किसानों के लिय रैस्ट हाउस बना सकते है मण्डी के अन्दर किसानो का प ुओ या बैलो के ठहरने के लिये और उनके ट्रेक्टर्ज खडे करने के लिए जगह बना कर उनको अच्छी सुविधा दे सकते है मण्डी के अन्दर सडके बना सकते है और कितने ही काम कर सकते है लेकिन उसकी भी एक हद है उसके बाद वहां पर जब कोई काम बचेगा या नही तो वह पैसा कहा से खर्च होगा ? इतना पैसा इकटंठा हो रहा है यहा कहा से खर्च कर सकेगे? यह जो कानून बनाया गया था यह किसान की बहबूदगी के लिये बनाया गया था ताकि पैसा उसकी बहबदूगी के लिये खर्च हो उसकी फसल मे चने मे हर किस्म की सुविधा हो इस बारे मे मै यह कहना चाहूगा कि मै भी पब्लिक अन्डरटेकिग्स कमेटी का सदस्य हू । वहां पर हमने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बहुत अच्छी तरह से डिसक्स किया हैकि जो यह रोक लगायी गयी है इससे छुटकारा कैसे पाया जाये। बाबू मूल चन्द जी ने यह सुझाव दिया है कि इसके लिये हाउस की एक कमेटी बना दी जाये । जिसमे हमारे कुछ सीनियर आफिसर्ज हो ला डिपार्टमैंट के अफसर हो कुछ सदस्य हो या कोई मन्त्रिगण भी इसमे भाामिल हो । वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की लाइट मे जो एनोमली पैदा हो गई है वह कैसे दूर की जा सकती है इस पर विचार करे। एनोमली यह

है कि हम मंडी के एरिया के अलावा इस मार्किट फीस की कही पर खर्च नही बन सकते । इससे छुटकारा कैसे पाया जाये। इसके लिये मै बडे दुख के साथ यह बात कहता हू कि एक साल हो गया है सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट आये हुए लेकिन अब तक न तो सरकार की और से इस बारे मे कोई कमेटी बनाई गई है और न ही इस पर विचार किया गया है ।

सहकारिता तथा योजना मंत्री ठाकुर बीर सिंहः इसके लिये आलरेडी एक कमेटी बनी हुई है (व्यवधान एवम भार्ोर)

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अगर कमेटी बनी हुई है तो हाउस के कानफीडैस को लिये बिना ही बनायी गयी होगी। हमे जो सूचना पब्लिक अन्डरटेकिग कमेटी मे सरकार के अफसरो ने दी है उसके मुताबिक इस एक्ट को तरमीम करने के लिये अभी तक कोई भी कदम नही उठाया गया है मै इस बारे मे आपकी मार्फत सरकार को एक सुजै ान देना चाहता हूं । सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मसला था और आनरेबल जजिज के सामने दोनो पक्षो ने जो बात रखी उन्होने बिदइन दैट फ्रेम वर्क फैसला दिया । पिछली बार सन 1975 मे हमारे दे ा की प्रधानमंत्री ने यह चाहा कि इस दे ा मे गरीब जनता को न्याय मिलना चाहिऐ सो ाल जस्टिस मिलना चाहिए । जब उन्होने यह बात की तो हमारे विरोधी पक्ष के भाईयो ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट मे यानी जुडीि ायरी मे जजिज को सुपरसीड करना न्यायपालिका पर एक आघात वाली बात है । इसके न्यायपालिका को बहुत बडा आघात लगेगा ।

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जिस आदमी के पास 10 रूपये जेब मे नही है दिल्ली तक जाने का किराया नही है वह हजारो रूपये वकीलो की फीस देकर कई पेि ाया भुगत कर किस तरह से न्याय प्राप्त कर सकता है ? इस केस मे भी ऐसा हुआ बडे बडे धनी लेाग जो इस सारे खर्चे को उठा सकते थे, वे सुप्रीम कोर्ट मे गये और वहां से यह फैसला आ गया। उस फैसले के बारे मे मै कुछ न कहते हुए यह कहना चाहूगा कि अगर हम उस फैसले को मददेनजर रखते हुए इस रोक से छुटकारा पा सकते है तो हमे पाने की कोि ा ा करनी चाहिये । मै यह सुझाव देना चाहता हू कि पजाब एग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किटस एक्ट के प्रिएम्बल मे थोडी सी चेंज कर दी जाये । जो इस एक्ट का प्रिएम्बल यानी जो मेन आब्जैक्ट है उसने लिखा हुआ है

"Better regularization of purchase, sale and processing of agricultural produce and establishment of mandis for agricultural produche in the State Haryana."

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर सिर्फ एक भाब्द जोड दिया जाये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर लागू नही हो सकता । इसमे यह कर दिया For better regularization of arrival, sale,puchase and thranport. उसके प्रिएम्बल मे, एक भाब्द जोडने से सारा रूपया आप कही पर भी खर्च कर सकते है जो कि किसानों कीा बहबूदगी के लये हों । कहने का मतलब यह

है कि किसान की फसल को मण्डी तक अच्छी तरह से पहुचाने के लिये आप कैसे भी रूपया खर्च कर सकते हो । इस एक भाब्द को जोडने के सारे का सारा मसला हल हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद जो कैसा ब्लाक पड़ा है इस तरह की अमैडमैन्ट करने के बाद आप किसानो के भले के लिये उसे खर्च कर सकते है । उपाध्यक्ष महोदय, मै आपसे यह दरखास्त करूगां कि इस फैसले को इनइफैक्टिव बनाने के लिये मंत्री महोदय से आप यह इस बारे मे जल्दी ही हाउस की एक कमेटी बनाये व हाउस मे यह आ वासन दे कि अलगे बजट सै ान तक इस लैकूना को दूर करने के लिये कोई अमैडिंग बिल लाया जायेगा ताकि हम किसानों के भले के लिये वह पैसा खर्च कर सके। जो अभी तक ब्लाक पडा हुआ है?

श्री भाम ांर सिंह नरवानाः उपाध्यक्ष महोदय, जो तरमीम सरकार ले कर आयी है उसके बारे मे हाउस के दोनो पक्षो की तरफ से काफी रो ानी डाली जा चुकी है । जो बात यहा पर कह दी गयी है, मै उनको रिपीट नही करूगा । उपाध्यक्ष महोदय, मै एक नयी बात की तरफ एक नये मसले की तरफ आपके माध्यम से हाउस का ध्यान आकर्शित करना चाहता हू। इस मार्किटिंग एक्अ की ब्रीफ मे या सक्षिप्त मे पृश्ठ भूमि मे अगर जाया जाये तो यह पता चलेगा कि सन 1917 मे सोवियता रूस मे एक क्रान्ति हुई थी उस क्रान्ति के फलस्वरूप वैस्टर्न यूरोपियन कन्ट्रीज मे जहा पर डैमोक्रिस थी वहा पर किसानों की लुट खमूट हो रही थी उसको

रोकने के लिये यह बिल उस वक्त लाया गया था उस समय किसानों की एक बडी लहर चली और उन्होने काफी स्ट्रगल की । उसके फलस्रूप जिस तरह से वैस्टर्न यूरोपियन कन्ट्रीज मे मार्किटिंग एक्ट बनाया गया था, उसी तरह से उस समय चौधरी छोटू राम जी यह बिल लाये थे । यह उस समय पजांब एगीकल्चरल प्रोडयूस मार्किटिग एक्ट के रूप मे जाना गया । अग्रेजो के वक्त के बाद आजादी मिलने के 20 साल तक भी इस एक्ट मे यह प्रोविजन रहा कि यानी मार्किट कमेटियों के स्तर पर प्रान्तो मे किसानो और व्यापरियों के चुने हुए नुमायन्दे होगे। यानी मार्किट कमेटियों चुनी हुई होगी और स्टेट लैबल पर मार्किटिग बोर्ड भी चुना हुआ होगा लेकिन पिछले कई सालो मे सरकार ने कही पर भी चुनाव नही करवाये है । एक सरकार आयी फिर दूसरी सरकार आयी और फिर तीसरी सरकार आयी लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आप को अच्छी तरह से पता होगा कि आज तक इनका काम नामिनोटिड चैयरमैन बगैरहा ही करते रहे है। कृशि मंत्री जी को भी पता है कि यह कोई उनके लिये क्रैडिट की बात नही है डैमोक्रेसी मे इस बात का उनको क्रैडिट नही जाता है कि उन्होने चुने हुए लोगो की जगह नामिनेटिड लोग रखे हुए है इमे इस बात मे कोई एतराज नही है कि सैक्रैट्री या चैयरमैन की पावर्ज किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी जाये या चीफ एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर चैयरमैन या सैक्रेट्री को दे दी जाये, क्योकि न आपका सैक्रैट्री या चैयरमैन चुना हुआ है और न ही चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। यह कोई डैमोक्रेटिक ढग नही है कि चुनाव मैने प्वायट किया मुझे

उम्मीद है कि सरकार जल्दी ही मार्किट कमेटीज मे और मार्किटिंग बोर्ड मे चुनाव करायेगी। इसके साथ ही मै एक बात ओर कहना चाहूगा । चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने एक बात कही, मै उस बारे मै कोई बहुत लम्बा चौडा भाशण नही देना चाहता । निहायत अफसोस की बात है कि एक्ट का जो मुद्दा था वह हम अचीव नही कर पा रहे है । जब हम चुनाव लड़ते है उस समय तो हम गरीब आदमी के आगे पीछे फिरते है, उनसे वायदे भी बहुत करते है, उनसे बडी हमदर्दी भी जताते है लेकिन जब चुनकर एक बार चण्डीगढ आ जाते है और यहा आये हुए 6 महीने या एक साल हो जाता है तो हम सही तौर पर उनकी नुमायन्दगी नही कर सकते, यह सही बात है । हमारे यहां आने के बाद वहा पर जो हमारी रूटस होती है, वे खत्म होनी भाुरू हो जाती है यहा पर सरकार होती है, बडे बडे आदमियों के साथ तालमेल होता है । देखने मे यह आया कि मार्किट कमेटियां के स्तर पर जितना रूपया खर्च होना चाहिये, वह खर्च नही होता । वहा पर जो बढिया बढिया रैस्ट हाउसिज बनते है, उनमे आज तक किसी भी किसान भाई के ठहरने का सवाल ही पैदा नही होता उनकी बेचारी की हिम्मत ही नही पडती कि वे वहां पर दाखिल भी हो जाये। दूसरी तरफ आप देखे कि अभी सरकाद ने पिछले दिनो एस0डी0एमज0 को मार्किट कमेटीज का एडमिनिस्ट्रेटर मकर्रर किया है । सरकार इन एडमिनिस्ट्रेटर्ज को फर्नीचर, करटेन और दूसरी साधन मुहैया नही करती इसलिये ये सारे साधन मार्किट कमेटी के पैसे खर्च करके प्राप्त किए जा रहे है । मुझे इस बात की नालेज है और मे बिना

सकोंच के यह बात कर रहा है यें एस0डी0एमज0 कमेटी के पैसे के ऊपर ये सारी बाते कर रहे है एक तरफ तो हालत यह है कि किसानों को जिन्स जैसे जीरी है गेहू है ये कई कई दिन तक मण्डी मे बोली के लिये पडी रहती है किसान की चीज ठीक प्रकार से मंउी से रहे उसकी पिलफेज न हो उसको देखने के लिये कोई नही है ं किसान के बैलो, किसान की गाड़ी, ट्रैक्टर के लिये मण्डी मे कोई सुविधा नही है। उसकी चीज की चोरी न हो जाए उसको रोकने के लिये कोई सुविधा नही है किसानों को प्रोटैक ान देने के लिये जो कुछ कानून बनाए हुए है उनका कोई प्रचार नही है, किसानो को अपने हक का पता नही है । और दूसरी तरफ मंडी के पैसे से फर्नीचर और करटेज खरीदे जा रहे है। किसान की भलाई के लिये जो एक्ट गुलामी के टाईम मे बनाया गया था और यह सोचकर बनाया गया थ कि इससे किसान को प्रोटेक ान मिलेगी आज उस एक्ट की यह हालत है कि मंडी मे किसान को कोई सुविधा उपलब्ध नही कराई जा रही है डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे याद है कि पजाब मे जब यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार पावर मे आई तो उस वक्त काग्रेस पार्टी विरोधी पार्टी थी । काग्रेस पार्टी ने इस एक्ट का विरोध किया । पडित जवाहर लाल नेहरू ने काग्रेस वालो को बुलाया और उनको कहा कि आजादी के बाद तेजी से अमल किया जाये । डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे बडे अफसोस से कहना पडता है कि आजादी मिलने के बाद चाहे काग्रेस सरकार पावर मे रही या जनता सरकार पावर मे रही किसी ने भी इस पर कोई अमल करने की कोि ा ा नही की मै चाहता

हू कि सरकार जो किसानों के हित की बाते है उन पर सख्ती से अमल करे।

स्वामी आदित्यवे ा हथीनः उपाध्यक्ष महोदय, पजांब कृशि उपज मंडी हरियाणा तृतीय सं ाोंधन तथा विधि मान्यकरण विधेयक, 1980 सदन के सामने प्रस्तुत है । मै इस का समर्थन करने के लिए खडा हुआ हू उपाध्यक्ष महोदय इसमे दो बाते है एक तो यह है कि मुख्य प्र ाासक नियुक्त करने का बिल तो हमने पास कर दिया था लेकिन उस समय उसके अधिकारो का बटवारा नही किया था। अब इस बिल मे सं ाोधन करके अधिकारी का बटवारा किया जा रहा है उपाध्यक्ष महोदय जिस तरह से एक मंत्री होता है उसको एक प्राईवेट सैक्रेटरी दिया जाता है ठीक उसी प्रकार से जो चैयरमैंन होता है वह तो पालिसी बनाता है पालिसी बनाने के बाद उसको कार्यान्वित करने के लिये अलग स्टाफ होता है । कई बार कोई ऐग्रीमेन्ट करना होता है और भी कई काम करने पडते है इन सब के लिये स्टाफ होता है कई लोगो ने यह कहा कि ऐसा करके सरकार ने कार्यहीनता का सबूत दिया है लेकिन वास्तविकता यह है कि चेयरमैन जो होता है वह काफी कु ाल होता है और इस बोर्ड का चैयरमैन भी काफी कु ाल है लेकिन कार्य काफी बढ रहा है वर्ल्ड बैक ने मडियों के निमार्ण के लिये कई करोड रूपया दिया है जिससे कि बहुत सी जगहों पर मडिया बनती है कही पर जमीन एक्वायर करनी है । इस जगह पहुच कर चेयरमैंन ऐग्रीमैंट करे यह चेयरमैन के लिये मुसकिन

नही है। इसलिये चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का फैसला लिया गया । उपाध्यक्ष महोदय, जो रूलज बने हुए है उनमे सारी पावर्ज बोर्ड को दी है ऐग्जोक्टिव को नही दी है । उपाध्यक्ष महोदय, मै कह रहा था कि सारी पावर्ज बोर्ड मे एग्जिस्ट करती है, चैयरमैंन या चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मे नही करती है । आखिरी बात जो मै कहना चाहता हूं और उसमे कोई ज्यादा विवाद की बात भी नही है । वह यह है कि एक क्लाज एड कर के उसके द्वारा फीस का बडा हुआ पैसा वसूल किया जाएगा। मेरे विचार से इसमे किसी को कोई एतराज नही होना चाहिये।

कृशि मंत्री सरदार तारा सिंहः डिपटी स्पीकर साहब, इस बिल पर काफी मैम्बर साहेबान बोले है । और खासतौर से चौधरी राम लाल ने तो सारा एक्ट ही पढ दिया । मै मुनासिब नही समझता हूं कि उन बातो को दोहराऊ। दो चार मोटी मोटी बाते ही कहूंगा खासतौर से चेयरमैंन की पावर्ज के बारे मे यहा कहा गया है कि वे विदड्रा की जा रही है । डिप्टी स्पीकर साहब, यह बिल्कुल गलत बात है। हमारे चैयरमैनं चौधरी गया लाल निहायत काबिल, निहायत मेहनती और अच्छे इन्सान है ऐसी बात नही है कि इनको इग्नोर करके चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जा रहा है। सारे हाउस को पता है और लीडर आफ दि अपोजि ान ने यह बात मानी है कि मार्किटिंग बोर्ड के पास काफी पैसा है हम चाहते है कि इस पैसे को पड़े न रहने दिया जाये, इस पैसे का खर्च किया जाये। इस पैसे से किसान की भलाई के लिये काम हो और

उन कामों को तेजी से किया जाये । डिप्टी स्पीकर साहब, जब इतने सारे काम करने है तो उनको करने के लिये स्टाफ चाहिये मेरा कहना यह है कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर का काफी ज्यादा है वर्ल्ड बैक की स्कीम के तहत काफी काम होना है जमीन ऐक्वायर करनी है, ये सारे काम चेयरमैंन नही कर सकता था चेयरमैंन का काम पाालिसी बनाना होता है और उस पालिसी को एक्जीक्यूट करना सरकारी अफसरों का काम होता है पिछली दफा चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को लगाये जाने संबधी बिल पास हुआ था उस वक्त उसकी पावर्ज डिफाइन नही की गई थी, कोई डिसीजन नही ले सकता थ इस तरह की कुछ डिफिक्लटीज थी। उन डिफिकल्टीज को रिमूच करने के लिये हम अमैडमैंट लाए है । चैयरमैनं की पावर्ज उतनी ही है जितनी पहले थी । चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के डे टू एग्जैक्टिव काम के लिये यह अमैडमैंट लाये है दूसरी अमैडमैंट जो हम लाये है वह कुछ आदमियों से पैसा वसूल करने लिये लाये है । तीसरी बात यह है कि बाबू मूल चन्द जी ने एक सुझाव दिया थर कि एक कमेटी बनाई जाये। इस बारे मे ठाकूर बीर सिंह ने कहा है कि कमेटी पहले ही बनी हुई है ओर वह कमेटी सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट को देख रही है मै यह बात मानता हू कि बाबू जी काबिल आदमी है और काफी अच्छे सुझाव देते है मै यह भी महसूस करता हू कि बाबू जी ने जो सुझाव दिये है वे काफी अच्छे है मै बाबू जी को अ योरेंस दिलाता हू कि अगले बजट सै ान मे अगर कोई अमैडमैंट लाने का हमारा विचार हुआ तो बाबू जी की

काबलियत का जरूर फायदा उठाएगे। हम बाबू जी को अपनी मीटिंग मे बुलाकर बात करेगे , उनके सुझाव लेगें

14.00 बजे

पोहलू साहब ने हमे यहा पर कई सुझाव दिये है, उनको भी मदेनजर रख जायेगा। चौधरी संत कवंर जी ने यहा सरकार के खिलाफ बोलते हुये किसानों के साथ काफी हमदर्दी दिखायी है । मेरी समझ मे नही आता है कि इस अमैडमैंट के साथ किसानों को क्या नुकसान हो रहा है? सरकार पैस तो डीलर्ज से ले रही है जिनसे हम पहले नही ले पाये, किसानों का इसमे क्या नुकसान है? डिप्टी स्पीकर साहब, श्री मांगे राम गुप्ता जी ने यहा पर बोलते हुये कुछ बात कही और मंगला साहब ने भी कई बाते कही, हम इन सभी भाईयों के सुझाव पर पूरा पूरा ध्यान देगे। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि इसमे ट्रासपोर्ट भाब्द भी इकलूड किया जायें, हम इनको भी कसिडंर करने का पूरा प्रयत्न करेगे । चौधरी भाम ेर सिंह जी ने बोलते हुये रि ायन पेट्रन की बात कही। मु कल तो डिप्टी स्पीकर साहब, यह है कि वे अकेल ही बाहर चले जाते है अगर हम जैसी को भी कही साथ ले जाते तो ठीक रहता । एक और साथी ने यंहा पर कहा कि माकिर्टिग कमेटियों ओर माकिर्टिग बोर्ड के इलैक ान होने चाहिये। मै यहा हाउस को यह बताना चाहता हू कि एक छोटा सा इलैक ान करवाने के लिये किसान का 40–40 हजार रूपया लग जाता है और जिसका बाद मे कोई खास फायदा नही होता है इन

बातों के साथ ही डिप्टी स्पीकर साहब मै प्रस्ताव करूगा कि यह बिल पास किया जाये।

श्री उपाध्यक्षः अब मै जो मो ान्ज चौधरी राम लाल वधवा ने मूव की है, यह पुट करूगा। प्र ान है –

कि सदन पजाब कृशि उपज मडी हरियाणा तृतीय सं ाोधन अध्यादे ा, 1980(1980 का हरियाणा अध्यादे ा स0 6) को अस्वीकार करता है

कि सदन पजाब कृशि उपज मडी हरियाणा तृतीय सं ाोधन अध्यादे ा, 1980(1980 का हरियाणा अध्यादे ा स0 7) को अस्वीकार करता है

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है –

कि पजाब कृशि उपज मडी हरियाणा तृतीय सं ाोधन तथा विधि मान्यकरण विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्षः अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाजिज 2 से 14

श्री उपाध्यक्षः प्र न है –

कि क्लाजिज 2 से 14 बिल पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री उपाध्यक्षः प्र न है –

कि क्लाज 1 बिल पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्षः प्र न है –

कि अनैक्टिग फार्मूला बिल का अनैक्टिग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाइटल

श्री उपाध्यक्षः प्र न है –

कि टाइटल बिल टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कृशि मंत्री सरदार तारा सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मै प्रस्ताव करता हूँ–

कि बिल पास किया जाये ।

श्री उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

कि बिल पस किया जाये।

चौधरी गंगा राम गोहानः डिप्टी स्पीकर साहब, आज हरियाणा के अन्दर जितनी मडिया है उनसे 14 करोड़ रूपये सालाना फीस के तौर पर आमदनी होती है। ये सारी मडियां किसानों के सहारे पर ही चल रही है और सारी मडियों मे लेन देन तथा कारोबार, सब किसानो के सहारे ही होता है , लेकिन किसानो की बदकिस्मती यह है कि उस 14 करोड़ रूपये की रा ि मे से एक पैसा भी उनकी भलाई के लिये खर्च नही हो रहा है । मै हाउस से रिक्वैस्ट करना चाहता हू कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को देखते हुए इस एक्ट के अन्दर अमैउमैंट लानी चाहिए कि यह जो इतना पैसा किसानो से इकट्ठा किया जाता है वह किसानों की भलाई के लिये ही खर्च किया जाऐगा (ाोर)

श्री उपाध्यक्षः गंगा राम जी, समय कहा है आप जल्दी अपनी बात को कहकर खत्म कीजिए।

चौधरी गंगा रामः ठीक है जो । डिप्टी स्पीकर साहब, मै तो यहा तक भी कहने के लिये खडा हू कि अगर सुप्रीम कोर्ट

की रूलिग से बचने के लिये हमे नया एक्ट भी बनाना पडे जो कि किसानो की भलाई के लिये हो, तो हमे उस हालत मे भी कोई गुरेज नही करना चाहिये। मडियो की चार दीवारो के बाहर किसान जब अपने गाव से माल लेकर आता है तो उसे अपनी गाडी,ट्रैक्टर खडे करने मे काफी दिक्कत महसूस होती है । इसके अलावा जो वहां की सडके होती है, वे मुकम्मल तौर पर टूटी हुई होती है और किसानो को आने जाने मे काफी दिक्कत का सामना करना पडता है मंडी तक आने के लिये रास्ते मे कई पुलियां पडती है वे भी टूटी फूटी पडी है, इसलिये सरकार को इस तरफ भी पूरा ध्यान देना चाहिये जो यह 14 करोड़ रूपये के लगभग सालाना इकट्ठा होता है, उस पैसे को किसानो की भलाई के लिये लगाया जाना चाहिये। इस तरह की तरमीम एक्ट के अन्दर होनी चाहिये । अगर सरकार सचमूच किसानों का भला चाहती है सचमूच किसानों के इट्रैस्ट को वाच करना चाहती है और किसानों के साथ सचमूच हमदर्दी दिखाना चाहती है तो इस तरह के भलाई के काम किसानों के लिये करे।किसान के खून पसीने की कमाई को सरकार की भलाई के लिये हो खर्च करे।

श्री उपाध्यक्षः गंगा राम जी, आप सभी पुरानी बाते जो कि आगे भी हाउस मे आ चुकी कह रहे है। कोई नई बात नही। आप बैठिये। आपको बोलते हुये काफी समय हो गया है (घटी)

चौधरी गंगा रामः डिप्टी स्पीकर साहब, मै एक दो बाते कह कर ही समाप्त करता हू । डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा

कहना यह है कि आज तक सरकार ने इस बारे मे कभी भी लीगत एक्सपर्टस से बातचीत नही की है। मेरी प्रार्थना है कि अगर सरकार सचमूच ही किसानों का भला चाहती है और किसानों की सही हमदर्द है तो सरकार को सच्चे दिल से कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिये। जिस से किसानों को किसी तरह की परे ाानी न हो इस काम के लिये सरकार को एक कमेटी भी नियुक्त करनी चाहिये।

श्री हीरा नन्द आर्यः डिप्टी स्पीकर साहब, यहां जिस बिल पर चर्चा हो रही है मै भी उस पर बोलने के लिये खडे हुआ हूं। एक्ट की मन् ाा यह थी कि किस प्रकार से किसानों के हितो को वाच किया जाए और किस तरह से उनके हितो की रक्षा की जाए। उनके हितो की रक्षा के लिये मार्किटिंग बोर्ड बनाये गये थे और उसके अन्दर चुनावो की व्यवस्था भी की गयी थी तथा कृशकों के प्रतिनिधि भााामिल करने का प्रोवीजन भी किया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, अब वह प्रोवीजन बदल कर वह कानून बदल कर किसान के प्रतिनिधी भााामिल न करके नामिने ान का प्रोवीजन कर दिया है मै समझता हू यह कतई तोर पर गैर प्रजातत्रिक है और किसानों के हितों के साथ खिलावाड है इसलिये यह सरकार अगर थोडा बहुत प्रजातन्त्र मे वि वास रखती है तो वह नामिने ान को खत्म करके दोबारा इलैक ान का प्रोवीजन लाए ताकि लोग अपनी इच्छानुसार अपने प्रतिनिधि भेज सके। यह एक्ट 1919 मे सर छोटू राम की कोि ा ो से बना था

किसानों पर 1929 से 132 करोड रूपये कर्जा था और 1934 से 152 करोड रूपये का कर्जा था उसके बाद जब पहली पंचवर्शीय योजना 1952 मे बनी उस वक्त आप सुन कर हैरान होगे कि जो कर्जा एजेंसियों द्वारा किसानो को दयिा गया था वह 9200 करोड़ रूप्ये था । उस वक्त पजाब मे पाकिस्तान भी भाामिल था मौजूदा पजाब भी भाामिल था और मौजूदा हरियाणा और हिमाचल प्रदे ा का हिस्सा भी भाामिल था । आज अगर आप अकेले हरियाणा की फिग्गर को देखे तो उससे कई गुन्ना ज्यादा कर्जा किसानो के ऊपर है। पिछेल सै ान मे मुख्यमंत्री जी ने एक आ वासन दिया था कि सर छोटू राम की जन्म भाताब्दी सरकार तौर पर मनाई जाएगी। अगर हम उस भाताब्दी को सही मायनों मे मानना चाहते है तो मैने एक प्रस्ताव भेजा था उसको असल मे लाया जाना चाहिए। वह प्रस्ताव यह था कि उनकी भाताब्दी मनाने के वक्त उनकी मन ाा का ध्यान रखा जाए। उनकी मन ाा थी कि गरीबो का कर्जा खत्म किया जाए । यानी जिसकी आमदनी 6000 रू0 सालान से कम हो, उसका कर्जा माफ किया जाए एक बात मै और कहना चाहता हूं कि आज किसान की जरूरत की चीजो की कीमतें बहुत बढ चुकी है। इसलिये किसानो की प्रोड्यूस और कारखानों की प्रोड्यूस के खर्चे का कम्पेयर करके किसान को उसकी उपज की कीमत दी जाए। अगर इन बातो का ख्याल रखा जाता है तो सारे दे ा का और प्रदे ा का भला हो सकता है।

श्री भले राम बडौदा अनुसूचित जातिः डिप्टी स्पीकर साहब, मै केवल ही सुझाव देना चाहता हू कि मंडी का जो बोर्ड बनता है उसमे व्यापारियों का भी नुमायंद होता है ओर ि ाडयूल्ड कास्टम का भी होता है लेकिन जो स्टेट लैवल पर बोर्ड होता है उसमे ि ाड्यूल्ड कास्टम का नुमायदा नही होता मेरा सुझाव है कि स्टेट लैबल के बोर्ड मे भी ि ाड्यूल्ड कास्टम का नुमायंदा होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्षः प्र न है –

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव–

हरियाणा राज्य मे प्राईवेट कालेजो की हालत आदि तथा राज्य सरकार की राश्ट्रीय करण नीती सम्बधी।

श्री उपाध्यक्षः अब श्री राम लाल वधवा रूल 84 के तहत हरियाणा राज्य मे प्राईवेट कालेजो की हालत, मजूर किए गए अनुदानों तथा राश्ट्रीयकरण संबंधी अपना मो ान मव करेगें ।

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हू–

कि हरियाणा राज्य मे प्राईवेट कालेजो की हालत, मजूर किए गए अनुदानों तथा राश्ट्रीयकरण संबंधी राज्य सरकार की नीति तथा उससे उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार किया जाए।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the policy of the Saate Government and situation arisen therefrom in regard to the condition of the private colleges in the State of Haryana grants sanctioned and nationalisation, be taken into consideration and be discussed.

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहूत महत्वपूर्ण विशय है इसलिये मैने इस पद अपना मो ान दिया था। इसके लिए मै अध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हू जिन्होने इसको स्वीकर करके सदन मे इस पर चर्चा का समय दिया। इससे पहले कि मै एक एक विशय पर बात करू मै एक बात कहने की आव यकता समझता हू कि हमारी जो ि ाक्षा प्रणाली है वह सरकार की नीतियों के कारण कहां तक वास्तविक ि ाक्षा प्रणाली है उसके अन्दर हमे कहा तक सफलता प्राप्त हुई है । उपाध्यक्ष महोदय, मै बताना चाहूगा कि ि ाक्षा के बारे मे भारत सरका ने बहुत से कमी ान बनाए, उनकी रिपोर्टस बनी आई वे आई।यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमी ान बना, कोठारी कमी ान बना और एक रिपोर्ट आफ स्टैडर्ड आफ यूनिवर्सिटी एजूके ान बनी। इस तरीके से बहुत सी रिकमैडे ान्ज है जो ि ाक्षा के बारे मे होती रही। लेकिन भारत की आजादी के 33 साल गुजर जाने के

बाद क्या हम आज छाती पर हाथ रख कर कह सकते है कि हमारी ि ाक्षा प्रणाली उस प्रकार की है जिस प्रकार की हमे चाहिए थी जिस प्रकार की हमे देनी चाहिए थी । उपाध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट आफ स्टैडर्ड आफ यूनिवर्सिटी एजूके ान है, इसके पेज 3 पर एक विद्धान ने लिखा है–

"Where is the wisdom we have lost in knowledge ? where is the knowledge we have lost in information ? The cyvles of Heaven in twenty centuries, bring us farther from God and nearer to the dust"

ऐजुके ान क्या होना चाहिए इसी रिपोर्ट के अन्दर जवाहर लाल नेहरू जी के कुछ भाब्द है वे भी पढना चाहता हूं –

"A university stands for humanism, for tolerance, for reason, for the adventure of ideas and for the search of truth. It stands for the onward march of the human race towards even higher objectives. If th universities discharge their duty adequately then it is well with the nation and the people"

इनमे से 33 साल की आजदी के बाद कितनी चीजे आज हमे मिली है, उन पर मै चर्चा नही करना चाहता । उपाध्यक्ष महोदय, यह एक हिसाब है मै इसकी ज्यादा तफसील मे न जाते हुए एक एक बात करूगां कि क्या होना चाहिए । ये सारी बाते मै केवल पाच मिनट मे बता देना चाहता हू।

जो इस किताब मे रिकमैड्रे ांज है क्या उसके अनुसार इस सरकार की नीति चल रही है और क्या ि ाक्षा का स्टैडर्ड उसी प्रकार है ? जो भी रिकमैडें ाज इस किताब मे दी हुई है क्या उनके अनुसार इस सरकार ने काम किया । यह मेजर रिकमैडे ांज आफ दि एजूके ान कमी ान 1964–66 वाई श्री जे0सी0 अग्रवाल की बुक है । इसके पेज 9 पर लिखा हुआ है कि इसलिए तो ि ाक्षा का बेडा गर्क हो रहा है आप यह समझने की कोि ा ा करो कि ये 1966 की रिकमैडमंज है और आज 1980 चल रहा है अभी तक उन पर अमल नही किया गया (भाोर एवम विघन)

श्री दीप चन्द भाटियाः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है चौधरी राम लाल वधवा साहब काफी देर से बोल रहे है। ये बोलते ही रहेगे क्या किसी और मैम्बर को बोलने के लिए समय नही मिलेगा?

श्री उपाध्यक्षः भाटिया साहब, आप बैठिये । यह कोई प्वाइट आफ आर्डर नही है।

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, आप जरा इनको समझना दीजिए कि इस बारे मे बोलने के लिए मूवर का किताना टाईम होता है । (भाोर एवम विघन)

"A member other than a Minister may not read his speech but may refersh his memory by reference to notes"

Mr. Deputy Speaker: Swami Ji, please sit down. He can quote from documents to support his arguments.

चौधरी राल लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहब, स्वामी जी क्या कर रहे है? इनको क्या पता कि रूल क्या होता है? (भाोर एवम विघन) मे खडे तो हो गये लेकिन इनको अपना नही पता कि वे क्या पढ रहे है तो मेरा इनको क्या पता है कि मै क्या पढ रहा हूं (भाोर एवम विघन)

श्री उपाध्यक्षः स्वामी जी, आप बैठिये। (भाोर एवम विघन)

चौधरी राल लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, स्वामी जी को समझा दीजिए। ये हाउस का टाईम जाया कर रहे है (भाोर एवम विघन)

स्वामी आदित्यवे ाः उपाध्यक्ष महोदय, मै पूछना चाहता हू कि क्या ये सारी किताब पढ सकते है ?

"A member other than a Minister may not read his speech but may refersh his memory by reference to notes"

श्री उपाध्यक्षः स्वामी जी, ये सारी किताब थोडे ही पढ रहे है । मे तो ि ाकायत मे से रैफैस कोट कर रहा है । (भाोर एवम विघन)

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहब, स्वामी जी को पता होना चाहिए कि हम रफ्रेंस कोट कर सकते है। मै

सारी किताब थोडे ही बाद पढ रहा हूं मै तो रैप्रेस कोट कर रहा हूं और यह वह कर सकता हूं ।(भाोर एवम विघन)

स्वामी आदित्यवे ा: उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय से इन्होने बोलना भाुरू किया है उस समय से ये किताब खोल कर खडे है। (भाोर एवम विघन)

चौधरी राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी रूलिंग के बाद भी स्वामी जी को समझ नही आ रहा है और समझ इनको इसलिए नही आ रहा है क्योकि ये सरकारी वैचिज के है। ये आपकी रूलिंग को मानते की नही। (भाोर एवम विघन)

श्री उपाध्यक्ष: स्वामी जी आप बैठिए ।(भाोर एवम विघन)

चौधरी राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहब, मै निवेदन कर रहा था कि इस किताब के पेज 9 पर लिखा हुआ है कि–

"Objectives of Education-

The most important and urgent reform needed in education is to transform it, to endeavour to relate it to the life, needs and aspirations of the people and thereby make it a powerful instrument of social, economic and cultural transformation necessary for the realization of the national goals. For this purpose education should be developed so as to increase productivity, achieve social and national integration, strengthen democracy, accelerate the process of modernisation and cultivate social, moral and spiritual value."

तो डिप्टी स्पीकर साहब, ये बाते इस किताब के आब्जैक्टिव आफ एजूके ान मे कही गई है आप अदाज लाग सकते है कि आज ि ाक्षा की हालत कहां तक ठीक है।ि ाक्षा की हातल ठीक होना तो दूर की बात है बल्कि दिन प्रतिदिन और भी खराब होती जा रही है डिप्टी स्पीकर साहब प्रोडक्टिविटी हुई, स्टूडैटस तथा लैक्चरर्ज मे अन्रैस्ट है जिससे कालेजो और स्कूलो की हालत बहुत खराब है । इस सरकार की नीति इस प्रकार की है हजारों की तादादा मे लैक्चरर्ज और टीचर्ज आज एजीटे ान कर रहे है। और उनको जलील किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मै इस सरकार से यह कहना चाहता हू कि आखिर कालेजों और स्कूलो की हालत का सुधार क्यो नही किया जा रहा है? आज कही कालेजो को टेक ओवर करने की बात की जा रही है कुछ प्राईवेट कालेज टेक ओवर किए गए हैं और कुछ नही किए गए है। उपाध्यक्ष महोदय, कालेजिज टेक ओवर करने के लिए एजूके ान डिपार्टमैंट की एक सर्वे कमेटी बनी थी । आप उस सर्वे कमेटी की रिकमैडे ांज देख लीजिए कि कालेजिज को टेक ओवर करने का क्या आईटेरिया है उस कमेटी ने कालेजिज को टेक ओवर करने के लिए जो आइटेरिया बनाया हुआ है उसके मुताबिक कालेज टेक ओवर नही किए बल्कि इस सरकार ने अपनी मर्जी से कलेजिज टेक ओवर किए है। आपको मै एक उदाहरण देता हू कि सम्भालका के पास एक प्राईवेट कालेज है जोकि उस सर्वे कमेटी की रिकमैडे ान के मुताबिक टेक ओवर किया जाना चाहिए था लेकिन वह टेक ओवर नही किया गया । इसलिए डिप्टी स्पीकर

साहब, आप की ि ाक्षा की हालत के बारे मे यह सरकार स्वय जान सकती हैकि क्या हालात है आप देखते है कि गवनमैंट कालेजिज मे क्या हालात है किसी भी कालेज मे स्टाफ पूरा नही है ।लैक्चरर्ज और टीचर्ज एडहक बेसिज लेगे हुए है उनको रैगुलर नही किया जा रहा है । बिल्डिग्ज की हालत भी खराब है । उनके अन्दर फर्नीचर नही है। फर्नीचर तो दूर की बात है उनके अन्दर बैठने के लिए टाट तक नही है। उपाध्यक्ष महोदय सबसे बडी बात यह है कि आज लैक्चरर्ज और टीचर्ज को सडको पर एजीटे ान करने , भुख हडताल कर बैठ कर, नारे लगा कर और अपना पेट पालने के लिए इस सरकार से रोटी नही मिलेगी तो वे ि ाक्षा क्या देगे ? उपाध्यक्ष महोदय ि ाक्षा के बारे मे इस किताब की रिकमैडे ांज के पेज 16 पर दो लाईन मै आपकी इजाजत से पढ देता हूं ताकि इस सरकार को पता लग सके कि काग्रेस पार्टी की सरकार ने जो कमी ान बनाए थे। उन्होने लैक्चरर्ज और टीचर्ज के लिए क्या किया था और आज वह सरकार उनके साथ क्या कर रही है।

"The efficiency of teaching profession and its contribution to national development in general and educational improvement in particular, will depend largely on its social status and morale. This will in the turn depend on two interrelated factors economic status and civic rights of teacher and their professional competence, character and sense of dedication."

Sir, in these ecommendations, it has further been stated

" Intensive and continuous efforts are necessary to raise the economic, social and professional status and to feed back talented young persons into the profession"

और उनकी सैलरीज के बारे मे कहा है कि –

"All teacher salaries should be reviewed every five years and the dearness allowance paid to teacher should be related to that paid to Government servants"

उपाध्यक्ष महोदय, आप उन रिकमैडे ाज को भी देखे और आज इस सरकार की नीति के अनुसार उन लैक्चरर्ज और टीचर्ज की हालत का अदांज भी लगाए। हमे बहुत सी सस्थाओ के लैक्चरर्ज और टीचर्ज बडे बडे मैम्मोरैडस की कापियां दे कर गए है, जिनको मै पढना नही चाहता । मै तो सिर्फ इस सरकार को उनका तात्पर्य बताना चाहता हू कि अगर लैक्चरर्ज और टीचर्ज इकोनोमिकल ठीक ढग से खडे नही हो सकते तो उनके मन को इत्मीनान नही होगा और जो ि ाक्षा की हालत है उनको वे ठीक तरह से नही सुधार सकेगे। उनकी मांग है कि यह जो ग्रान्ट कालेजिज को दी जा रही है। वह थोडी है। मै उनकी इस डिमाड का समर्थन करता हूं कि उन्हे ट्रेजरी से तनख्वाह मिलनी चाहिए और पूरी ग्राट उन कालेजिज को दी जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः चौधरी साहब आप जरा जल्दी करे। इस प्रस्ताव पर डिसक ान के लिए आधा धटा रखा गया है। जिसमे पन्द्रह मिनट आपने ले लिए है।

चौधरी राम लाल वधवाः उपाध्यक्ष महोदय, जो प्राईवेट कालेजिज टेक ओवर किए जा रहे है वे पालिसी के मुताबिक नही किए जा रहे है उपाध्यक्ष महोदय प्राईवेट कालेजिज चन्दा इकट्ठा करके कालेज की बिल्डिंग बनाते है, स्टूडैन्टस को बिठाने के लिए बैच प्रोवाईड करते है। और अन्य दूसरे खर्च करते है। उन्हे मु ि कल यह आ रही है कि उसमे से अगर लैक्चरर्ज को पूरी तन्ख्वाह देते है तो कालेज खडा नही हो सकता । सरकार जहा कालेज बनाती हे वहा उसकी बिल्डिंग पर करोडो रूप्या लगाती है, उसके लिए बैचमुहैया करती है, लैक्चरर्ज आदि के रैजिडैक्स के मकान प्रोवाईड करती है और जिनको सरकारी मकान नही मिलते उनको किराया अलग से देती है। क्यो नही सरकार निर्णय करती कि लैक्चरर्ज को पूरी तन्खवाह देने के लिए उन कालेजिज को पूरी ग्रान्ट दे दी जाए ताकि वे आराम से बच्चो को एजुके ान दे सके ? प्राईवेट कालेजिज को चला कर सरकारी खजाने पर कोई वि ोश बोझ नही पडता क्योकि बाकी खर्चा वे चन्दा इकट्ठा करके करते है। इसलिए मै आपके द्धारा सरकार से निवेदन करना चाहता हू कि उन्हे 100 प्रति त ग्राट दी जाए तथा तनख्वाह खजाने से दी जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात और मै सरकार के नोटिस मे लाना चाहता हू। सरकारी कालेजिज मे बहुत से लैक्चरर्ज ऐड हाक बेसिज पर लगे हुए है। कई तो इस साल से ऐड हाक बेसिज पर है चीफ मिनिस्टर साहब मे उन्हे रैगुलर का आ वासन तो दिया था लेकिन बहुत से अभी ऐसे है जो अभी तक रैगुलर नही हुए है। ऐसे लैक्चरर्ज को जल्दी रैगुलर किया जाना चाहिए।

अन्त मे एक बात और कहना चाहता हू कि जिन कालेजिज के नाम जात बिरादरी के नाम पर है जैसे जाट कालेज या वै ा कालेज वे नाम बदले जाने चाहिए । कोठारी कमी ान की रिपोर्ट मे भी इस बात पर जोर दिया है कि कालेजिज के नाम नै ानल लैवल पर होने चाहिए । मुझे उम्मीद है कि सरकार इस और भी ध्यान देगी । इन भाब्दो के साथ डिप्टी स्पीकर साहब मै अपना स्थान लेता हूं और आ ाा करता हूं कि मेरा प्रस्ताव सदन द्वारा पास किया जाएगा ।

स्वामी अग्निवे ा पुडरीः उपाध्यक्ष महोदय, मेरे योग्य साथी श्री राम लाल वधवा जी ने अभी जो प्रस्ताव आपके सामने रखा है, मै उसकी मूल भावना से सहमत हूं लेकिन जो कुछ बाते उन्होने कही है उनसे मेरा कुछ मतभेद भी है। वधवा जी ने अपना प्रस्ताव रखते हुए मांग की कि सरकार प्राईवेट कालेजिज को 100 प्रति त अनुदान भी दे और पढाने वाले अध्यापको को सरकारी खजाने से तन्खवाह भी मिले। ये दोनो बाते परस्पर विरोधी है

अगर सरकार 100 प्रति त अनुदान या जितना यह उचित समझे देदे और अध्यापको की तनख्वाह भी सरकारी खजाने से मिले तब तो उनकी सिक्योरिटी आफ सरकारी कर्मचारियों की तरह बन जाती है और यह भूमिका ने ानेलाइजे ान की है। हमारे दे ा के अन्दर एक रिवाज चल पडा है कि हर चीज का सरकारीकरण कर दिया जाए। नाम तो राश्टीयकरण का होता है लेकिन हो यह सरकारीकरण जाता है। जितना भ्रश्टाचार हुआ करता है किसी प्राईवेट मैनेजमैंट के अन्तर्गत उससे कही ज्यादा भ्रश्टाचार बढ जाता है जब उस सस्थों का सरकारीकरण हो जाता है उसमे इनि ि एटिव नाम की चीज खत्म हो जाती है । हमारे राजनैतिक नेताओ के उपर दबाव पडते है मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मै ि ाक्षा मंत्री होता था, मै इन्कार करता था कि प्राईवेट कालेजिज की मैनेजमैंट को सरकारी हाथो मे नही लेना चाहिए बल्कि जो सस्थाओ ली जा चुकी है वे अपना मैनेजमैंट को सरकारी हाथो मे नही लेना चाहिये बल्कि जो सस्थांए ली जा चुकी है वे यदि अपना मैनेजमैंट वापस लेना चाहे तो हमे वापस दे देना चाहिये। परन्तु मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी की राय दूसरी होती थी ।हमे यहा तो इन्ताजम करना चाहिये कि वहां पढने वाले अध्यापको को समय पर तन्ख्वाह मिले लेकिन उनमे अगर किसी तरह से भी हम हस्तक्षेप करते है तो हम बहुत बडा अन्याय ि ाक्षा प्रणाली के साथ करते है। उपाध्यक्ष महोदय, कालेजिज की अवस्था बहुत बुरी है यह मेरे साथी चौधरी राम लाल जी ने कहा लेकिन विचारणीय बात यह है कि कालेज मे आने वाले विधार्थी प्राइमरी स्कूलो से ही

आते है और प्राईमरी स्कूलो की हालत क्या है ? यूनवर्सिटीज की हालत अगर आप देखे और वहां पढाने वालो की तन्ख्वाह भी अगर आप देखे तो ऐसा लगता है कि इसमे उंचे स्तर की सस्था हमारे दे ा मे कोई और नही है दो दो पीरियड पढाने वालो को दो हजार रूप्ये से भी ज्यादा महीने का वेतन मिले लेकिन प्राईमरी स्कूल की टीचर को, जो आठ आठ घंटे बच्चो को पढाता है, गांव मे रहता है, न तो स्कूल की बिल्डिंग ठीक है, न बच्चो के लिए टाट है , न पीने का पानी है, न कुर्सी है और न ब्लैकबोर्ड है, बहुत कम तनख्वाह दी जाती है। कालेज मे बच्चे वही से आ रहे है वह एक फाउडें ान है जिसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड रही है लेकिन कालेजिज के सुधार के लिए हम नए से नए प्रस्ताव लाते रहते है। मै नही कहता कि कालेज के टीचर्ज को तनख्वाह अच्छी नही मिलनी चाहिए लेकिन हमे देखना चाहिए कि प्राथमिकता किस बात को दी जानी चाहिए। अगर हम फाउडे ांन को ठीक नही करेगे तो ऊपर का गुम्बद ठीक नही रह सकता। आज हम यूनिवर्सिटीज मे अराजकता देख रहे है। उसकी भूमिका क्या है? हमारे नौजवान हता ा ओर निरा ा है उनका भविश्य अधकार मे है । जितनी ऐजुके ान दी जा रही है।उनका सारे का सारा प्रयास यह है कि एक सर्फद कालर तबका बाबू जी बनता जा रहा है यानी क्लर्क बनते जा रहे है क्योकि स्कूलो मे हाथ से किया जाने वाला कोई वि ोश काम नही सिखाया जाता। बच्चो को केवल किताबी कीडे बनाकर रख दिया गया है । उन्हे ही मैरिट पर ऊंचा माना जाता है । देहात के बच्चे जो अपने हाथ से काम

करते है, खेतो मे काम करते है, हथौडे से काम करते है उन्हे मैरिट से बहुत नीचे माना जाता है । इसलिए हमे ि ाक्षा प्रणाली को आमूलचूल बदलना पडेगा । आज यूनिवर्सिटीज को सबसे जयादा सुविधा मिली हुई है, दूसरे नम्बर की सुविधा कालेज वालो को मिली हुई है, उससे कम सविधा हाई स्कूल और मिडल स्कूलो को मिली हुई है लेकिन प्राईमरी स्कूल्ज बिल्कुल निगलैक्टिड है। तो मेरी आपके द्धारा सरकार से गुजारि ा है कि सरकार इस और भी ध्यान दें। उपाध्यक्ष महोदय, भजन लाल जी की एक आदत है जब कभी ये दौर पर जाते है और लोग इन्हे किसी जलसे से मैमोरैन्डस दे देते है तो ये लोगो की हाजरी को देख कर झट से कह देते है कि आपके कालेज को टेक ओवर करता हूं।बाद मे वित मंत्री जी को सोचना पडता है कि कहां से इतना खर्चा पूरा करेगे। सरकारी कर्मचारी यह सोच कर घबराते है कि यह जो आय दिन प्राईवेट सस्थाये टेक ओवर हो रही है, यह ि ाक्षा के लिए कहां तक फायदेमंद होगा। डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात और गोर से देखने की है प्राईवेट कालेजिज के टीचर्ज आप फख से यह दावा करते है कि सरकारी कालेजिज की निस्बत असुरक्षा की हालत मे काम करने क बावजूद उनके रिजल्टस बढिया है । यह एक वास्तविकता है कि प्राईवेट कालेजिज के अन्दर अच्छी पढाई हो रही है, उनके रिजल्टस अच्छे है और बच्चे डिस्पिलिड है जबकि गवर्नमैंट कालेजिज मे ऐसा नही है। तो हमे इस पहलू से भी सोचने की आव यकता है।

डिप्टी स्पीकर साहब, जैसा मैने पहले कहा प्राईमरी स्तर पर ि ाक्षा की पूर्ण उपेक्षा हो रही है।

जनता पार्टी की सरकार ने एक मौलिक परिवर्तन किया था कि अग्रेजी पढाना जरूरी नही है ं। उनकी जगह सो ाल और यूजफूल प्रोडेक्टिव वर्क होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे हाथ से काम करना सीखे। निर्भरता ि ाक्षा की पूरी कसौटी होनी चाहिए । प्राईवेट कालेजों को सौ प्रति ात अनुदान और खजाने से उनके अध्यापकों को तनख्वाह दिए जाने की बात सोचोगे तो हम अपनी ि ाक्षा प्रणाली के साथ न्याय नही करेगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मै हमे ाा से ही पब्लिक स्कूलो का विरोध करता रहा हूं । कमला नेहरू और मोती लाल नेहरू स्कूल सरकार के खर्चे स`चल रहे है वे पब्लिक के लिए सफेद हाथी है। उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरे से सहमत होगे क्योकि आप भी प्रगति ील विचारधारा के है । क्या आप महसूस नही करते कि एक बच्चा पब्लिक स्कूल मे पढता है और दूसरा आम स्कूल मे, तो क्या उसकी विचारधारा मे फर्म नही होगा ? आज कितने ही गरीब लोगो के बच्चे हाली पाली बन कर गावो मे भैंस चरा रहे है। जो बच्चा पब्लिक स्कूल मे पढता है। और कार मे बैठ कर स्कूल जाता है उसके मुकाबले मे जो आम स्कूल मे पढता है उसके विकास मे जमीन आसमान का अन्तर होगा। इसलिए इस अन्तर को मिटाने का हमारा सब से पहला कर्तव्य होना चाहिए।

श्री हीरा नन्द आर्य लोहाः उपाध्यक्ष महोदय, जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक कितने ही कमी ान और कमेटींया ि ाक्षा के सबंध मे बैठी है परन्तु 34 साल के प चात भी ि ाक्षा के क्षेत्र मे कोई वि ोश सुधार नही आया । दिन प्रति दिन ि ाक्षा का ढांचा बिगड़ता जा रहा है। चाहे गवर्नमैंट कालेज है या प्राईवेट कालेज है, सब की एक जैसी हालत है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हरियाणा चौधरी देवी लाल की सरकार थी उस समय कुछ कानून बने थे। एक तो प्राईवेट कालेजो को टेक ओवर करने का और दूसरा उनके अध्यापको को सिक्योरिटी आफ सर्विस का । हमने एक कमेटी बनाई थी, जिसमे प्राईवेट स्कूलो के सबंध मे सिफारि ा की थी कि अगर किसी अध्यापक की सर्विस एक साल की हो गई तो उसके नाम की भी सरकार ग्रान्ट देगी । यह भी सिफारिस की गई थी कि अगर कोई एक साल नौकरी मे रह जाये तो उसका भी खर्चा कवर किया जायेगा लेकिन अभी तक उसका फैसला नही किया गया । स्कूलो के संबध मे 75 प्रति त ग्रान्ट देने का फैसला किया गया था चीफ मिनिस्टर साहब ने इसके बारे मे आ वासन भी दिया था । स्वामी जी ने पब्लिक स्कूल राई का वैलिड प्र न उठाया है आप को यह सुनकर हैरानी होगी कि पब्लिक स्कूल राई औमर कामन स्कूलो मे कितना अन्तर है। गवर्नमैंट स्कूलो मे लगभग 125 रूपये प्रति बच्चे के हिसाब से एक साल मे खर्च होता है और यदि 125 रूपये मे

से अध्यापको की तनख्वाह निकाल दी जाये तो 5 प्रति त से भी कम एक बच्चे पर खर्च होता है दूसरी तरफ पब्लिक स्कूल राई से साढे छः हजार रूपये प्रतिवर्श प्रति बच्चे पर खर्च होते है (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) यह जमीन और पाताल का अन्तर है। आप अन्दाज लगाये कि किस प्रकार से ि ाक्षा का सुधार हो सकता है। जो पब्लिक स्कूल के बच्चे है उनका स्तर ओर अध्यापक का स्तर बराबर हो यह कैसे हो सकता है? मै मानता हूं कि यह आसान बात नही है कि एक दम मे ि ाक्षा प्रणाली मे परिवर्तन कर दिया जाये।

श्री अध्यक्षः बिल तो कालेजिज के बारे मे है और आप स्कूलो के बारे मे बात कर रह है।Arya Sahib, Rai School has got nothing to do with it. This is in regard to proviate college Bill.

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मै तो ि ाक्षा प्रणाली के बारे मे बात कर रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, जब किसी प्राईवेट कालेज की व्यवस्था खराब हो और कोई मैनेजमैंट वालन्टरी इस कालेज को देना चाहे तो सरकार को ले लेना चाहिए। अगर कोई मैनेजमैंट नही देना चाहती तो अधिक से अधिक दो तीन साल के लिए ले ले और जब उसकी व्यवस्था ठीक हो जाये तो उस सस्थां को वापस कर दिया जाये। जहां तक सम्पति का सवाल है, सम्पति लोगों की प्रापर्टी होती है, पब्लिक के फण्डज होते है। अगर किसी कालेज को टेक ओवर करना पडे तो उसको कुछ कम्पनसे ान दे कर किया जा सकता है । उसमे

सकोंच करने की जरूरत नही है । स्पीकर साहब, आप जानते है कि प्राईवेट कालेजों को 35 प्रति त की बजाए 75 प्रति त ग्रान्ट देने का प्रयत्न चौधरी देवी लाल की सरकार ने किया था और अगर सारा खर्चा जोडा जाए तो कुछ मिला कर यह 83 प्रति त बनती है। क्योकि आजकल लोग चन्दा नही देते है इस लिए प्राईवेट कालेजिज की ग्रान्ट बढा दी जाये तो ठीक ही होगा ।

श्री अध्यक्षः आजकल कितनी ग्रान्ट है ?

श्री हीरा नन्द आर्यः आज कल 75 प्रति त ग्रान्ट है लेकिन कुल मिला कर 83 प्रति ात हो जाती है।

Mr. Speaker: That means that the grant has gone up from 45% to 75% when I was education Minister it was only 45%.

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, ऐसे ऐसे प्राईवेट कालेजिज है जो अठारह अठारह महीने तनख्वाह नही देते है।

चौधरी राम लाल वधवाः स्पकीर साहब, हमने 85 प्रति ात ग्रान्ट दी और यदि अब 15 प्रति ात छूट दे दे तो पूरी 100 प्रति ात हो जायेगी ।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, प्राईवेट कालेजिज के बारे मे एक कमेटी बनी थी । आज उस कमेटी की क्या स्थिति है, उसका कुछ पता नही हैं। इस कमेटी के बारे मे मैने चर्चा भी की थी। एक्ट मे अमैडमैंट करके हमने पिछल तीन साल मे

एजूके ान का सुधार करने का प्रयत्न किया था । अगर उन प्रयत्नों मे कोई ढील हो गई तो एजूके ान का सत्याना ा हो जायेगा। स्पीकर साहब, सारे कालेजिज मे और दूसरी सस्थाओ मे एडहाक एम्पलाईज की बडी दुर्द ाा हो रही है। एक तरफ लोगो को हटा रहे है। और दूसरी तरफ नोकरी पर लगा रहे है। एडहाक एम्पलाइज की व्यवस्था सुधारने के लिये कोि ा ा करनी चाहिए । रोहतक यूनिवर्सिटी और हिसार यूनिवर्सिटी मे बर्बर्ता पूर्ण लोगो के साथ अत्याचार किए जा रहे है। वहा पर कालेजिज बन्द पडे है। एक लडका औमप्रका ा नाम का है। पुलिस ने और मैनेजमैंट ने उस लडके की आख, कान, और गुर्दे मे ग्रिसिंग की है। अगर सरकार इस बारे मे इन्साफ देना चाहती है तो जुडि ायल इन्कवायरी करवा ले, सारी बातो का पता लग जायगा जिस तरह डबवाली मे सरकार दोशी पाई गई उसी तरह फरीदाबाद मे भी वही स्थिति हुई । मै दावे के साथ कहता हूं कि रोहतक ओर हिसार मे अत्याचार हुए थे । लडको ने भाान्तिपूर्ण ढंग से जलूस का प्रद ान करना चाहा था। लेकिन विरोध मे पुलिस ने बुरी तरह उन स्टूडैन्टस को पीटा।

परिवरहन मंत्री श्री जगन नाथः क्या वो स्टूडैन्ट वर्क ााप मे नही घुसे थे ?

श्री हीरा नन्द आर्यः वर्क ााप एम्पलाईज ने भी उनके साथ ज्यादती की है। अगर ि ाक्षा मे सुधार करना चाहते है, तो चाहे विधार्थी प्राईवेट कालेज का हो चाहे सरकारी कालेज का हो,

उसके साथ जब तक न्याय नही किया जायेगा तब तक ि ाक्षा मे सुधार नही हो सकता । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मै चाहता हू कि इस बारे मे जुडि ियल इन्कवायरी करवाई जाए ।

बैठक का समय बढाना ।

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, जिस सबजैक्ट पर बहस हो रही है उसका चूकि अभी मिनिस्टर महोदय ने भी जवाब देना है और एक दूसरे मैटर पर भी आधे घंटा की चर्चा होनी है। पहले बढाये हुए समय के अनुसार हाउस 3 बजे तक चलना था । इसलिए अगर हाउस चाहे तो यह समय बढाकर साढे तीन बजे तक कार कर दिया जाए ।

आवाजेः ठीक है, हाउस का समय साढे तीन बजे तक बढा दिया जाये ।

श्री अध्यक्षः हाउस का समय साढे तीन बजे तक बढाया जाता है।

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पुनरारम्भ

मुख्य संसदीय सचिव श्रीमती भाान्ति देवीः अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य श्री राम लाल वधवा के रूल 84 के तहत अपने प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए, अपने सुझाव रखे है । उन्होने कहा कि प्राईवेट कालेजों को अधिक से अधिक सहायता दी जाये

ताकि उनमे ठीक प्रकार से कार्य हो सके। उनके कुछके सुझाव रचनात्मक भी थे। हमारी सरकार ने इस कार्य मे बहुत बडा योगदान किया है। पहले ग्रान्ट केवल 35 प्रति त दी जाती थी । जिस वक्त माननीय अध्यक्ष महोदय एजूके ान मिनिस्टर थे, उस समय यह ग्रान्ट 35 प्रति ात से बढा कर 45 प्रति ात कर दी गई थी । बाद मे हमने इस ग्रान्ट को 45 प्रति ात से बढा कर 75 प्रति ात कर दिया । इनको इस बात के लिये सरकार को बधाई देनी चाहिए। (ाोर) जिस समय आप बोल रहे थे तो हम चुपचाप आपकी बाते सुन रहे थे। अब आप मे भी बात सुनने का संयम ओर सहन ीलता होनी चाहिए। हमने कालेजों की गवर्निग बाडी के अन्दर अध्यापको मे से दो नुमायन्दे लिए है और एक नान टीचिंग स्टाफ से नुमायंदा लिया है यह कोई छोटा निर्णय नही है। स्पीकर साहब, हमारी सरकार ने एक और बहुत बडा काम किया है। जिस की आज तक दुनिया मे कोई मिसाल नही है। हमारी सरकार ने देहाती क्षेत्र मे 12 प्राईवेट कालेज टेक ओवर कर लिए है और 3 कालेजों को और टेक ओवर करने का मामला अभी सरकार के विचारधीन है । इन कालेजो को भी सरकार भीघ्र ही अधिग्रहण कर लेगी । इसके अतिरिक्त मेरे भाई ने कहा कि प्राईवेट कालेजो को जबरन टेक ओवर कर लेना चाहिए। मै अपने माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि जो खुद भी मिनिस्टर रह चुके है, उन्हे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि प्राईवेट कालेज किसी मैनेजिंग बाडी के अधीन होते है। जो लोग चन्दा देते है। ये कालेज उनके अधीन होते है और वही लोग इन सस्थाओं को

चलाते है और बनाते है। इसलिए आप मुझे बताए कि वे पदाधिकारी, जिन के अन्डर ये कालेज चल रहे है जब तक वे नही चाहते तो कैसे सरकार इन को टेक ओवर कर लेगी ? मै कहना चाहती हू कि जब तक कोई सस्था या मैनेजिंग बाडी तैयार नही होगी तो सरकार उन को किस ढगं से टेक ओवर कर सकती है। मेरे भाई वधवा साहब ने प्वायंट रेज किया है कि सरकार को इन कालेजो को सैन्ट परसैन्ट ग्रान्ट देनी चाहिए। आप बताइए कि यदि उन्हे सैंट परसैन्ट ग्रान्ट सरकार दे देती है और फिर भी सारा कार्य प्राईवेट मैनेजमैंट के हाथ मे रहे और यह मनमानी करे तो यह कैसे सम्भव हो सकता है अध्यक्ष महोदय, इस दि ाा मे सरकार अपना कार्य करना अच्छी तरह जानती है इसलिए उन्हे 75 प्रति त ग्रान्ट दे रही है। मै भी इस बात से सहमत हू कि यदि थोडा सा प्रोत्साहन इन सस्थाओं को ओर दे दिया जाये तो वे अच्छा काम कर सकती है लेकिन हमारे पास इतने फंडज नही है। हमारी सरकार यह भी अच्छी तरह से जानती है कि प्राईवेट कालेजों के अन्दर पढाई अच्छी प्रकार से होती है इस मे कोई दो राय नही है। मेरे साथी कह रहे है कि उन्हे ट्रेजरी से तनख्वाह भी दिलवाई जाये और भातप्रति ात ग्रान्ट भी दी जाये। मै अपने भाई को बतलाना चाहती हू कि ये दोनो बाते कैसे संभव हो सकती है? वे एक बात की मांग कर सकते थे कि या तो उन्हे ट्रेजरी से तनख्वाह दी जाये और या भातप्रति ात ग्रान्ट दी जाये। इसलिये ये दोनो बाते साथ साथ संभव नही हो सकती। एक ही काम सरकार कर सकती है । मेरे भाई ने प्राईवेट कालेजो के अन्दर जो

लैकचरर्ज लगे हुए है, उनके बारे मे कहा है कि उन्हे रैगुलर एम्पलाएमेंट दी जाए। यह उनका बडा अच्छा सुझाव है ।

स्पीकर साहब, हमने अपनी सरकार आने के बाद छोटी सी अवधि के दौरान ही अब तक 250 स्कूलो को अपग्रेड कर दिया है। मेरे साथी स्वामी जी पहले भी चितित रहते थे और अब भी है। उनका यह कहना ठीक है कि जब तक किसी मकान की नींव मजबूत नही होगी तब तक उस पर वि ाल इमारत खडी करना बेकार है। स्वामी जी ने बडा अच्छा रचनात्मक सुझाव दिया है कि प्राईमरी ि ाक्षा का स्तर अच्छा हो । स्पीकर साहब, हमने बहुत से स्कूल ओर बनाये है। पिछली सरकार मे यान चौधरी देवीलाल जी की सरकार मे आर्य साहब जब एजुके ान मिनिस्टर थे तो उस वक्त इन्होने स्कूलो को अपग्रेड कर दिया लेकिन आगे कोई कार्यवाही नही की (ाोर)

श्री भले रामः आन ए प्वायट आफ आर्डर सर। अभी बहिन जी ने कहा है कि हमने 250 स्कूलो को अपग्रेड कर दिया है। यह बहुत अच्छी बात है लेकिन मै इनका ध्यान दिलाना चाहता हू कि उन स्कूलो मे बहुत सी जगह पर आज तक हैड मास्टर नही पहुचे ंहै उनको तनख्वाह नही दी गई है।

श्री अध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नही है।(ाोर)

मास्टर ि ाव प्रसादः आन ए पवायंट आफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्षः किस रूल के तहत आप पवायंट आफ आर्डर रेज कर रहे है ? यदि इररेलेवेन्ट प्वायंट रेज होते रहे, तो कैसे काम चलेगा ?

मास्टर ि ाव प्रसादः स्पीकर साहब, बहिन जी स्वंय टीचर्ज रही है। इनक को पता होना चाहिए कि स्कूलो के अन्दर जो टीचर है, उनकी डियूटी मर्दम भ्ाुमारी के लिए लगायी हुई है। जिससे कि बच्चो की पढाई पर बहुत असर पडता है। इसलिए मै चाहता हूं कि उनकी डियूटी न लगाई जाए क्योकि बच्चो के एगजाम बहुत नजदीक आ रहे है। (ाोर)

15.00 बजे।

श्रीमती भ्ाान्ति देवीः सैन्सस का काम तो पढे लिखे व्यक्ति ही कर सकते है, एक दो हफते की सारी बात है सारे अध्यपाको का भी वह दायित्व बनता है। कि वे अपने प्रान्त का यह काम करें। यह काम अध्यापक अच्छी तरह से कर सकते है अध्यापक ही एक ऐसी जमात है जो हर जगह पर काम कर सकते है जंहा पर उनकी जरूरत पडती है, एक आवाज से उस काम को करते है। वे अपने दायित्व को पूरी तरह से निभाते है। जहां तक प्राईमरी स्कूलो की बात है, मै इन्हे यह बताना चाहती हू कि हमने बहुत से स्कूल अपग्रेड किये है। जहां तक उनके लिये बिल्डिंग की बात है, हमारी सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि प्राईमरी स्कूलो की बिल्डिंग है, उनकी मैचिंग ग्रान्ट देकर बनवाया

जाये। हमारी सरकार ने यह तय किया है कि जो गांव जितना पैसा इस काम के लिये इकट्ठा कर लेगा, उतना ही पैसा उसको सरकार देगी। हम इस काम के लिए उन्हे प्रोत्साहित कर रहे है ताकि देहातो मे बच्चो को सिर छुपाने के लिये कमरे और जगह उपलब्ध हो सके। मै यह भी कहना चाहती हूं कि आज के मुख्य मंत्री जी के थोडे से कार्यकाल मे कई प्रगति के कार्य हुए है । ि ाक्षा के लिये स्कूल अपग्रेड किय गये है, कई सरकारी कालेज बना दिय गये है, ठीक समय पर स्कूलो मे अध्यपाको का प्रबन्ध किया गया है और मैचिंग ग्रान्ट देने का फैसला किया गया है यह सारे काम करना कोई छोटी बात नही है इसके लिये मै अपने विभाग के अधिकारियों को भी बधाई देना चाहती हू क्योकि इस सारे काम का श्रेय उनको जाता है । उन्होने रूचि लेकर इस बारे मे कार्यवाही की है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि हम इसी तरह से आगे बढते जायेगे और दिन दुगनी रात चौगुनी हरियाणा की तरक्की कर सकेगे।

आधे घन्टे की चर्चा–

राज्य के खद की मांत्रा प्राप्त होने सबंधी ।

श्री अध्यक्षः अब डाक्टर मंगल सैन और सरदार सुखदेव सिंह स्टार्ड क्वै ाचन नम्बर 1885 के जवाब के अराईड हुए मैटर पर अपनी हाफ एन आवर डिस्क ान भ्ाुरू करेगे?

डा0 मगंल सैनः स्पीकर साहब, मै आपका बडा अभारी हू कि आपने इस पर हाफ एन ओवर डिस्क ान करने के लिये मेरी मो ान स्वीकार की । यह प्र न जो पूछा गया है, यह आनरेबल मैम्बर चौधरी संत कवर जी के नाम के एडमिटिड था, जिसमे उन्होने यह पूछा था कि टोटल कितना क्वाटिट यूरिया तथा डी0ए0पी0 फर्टीलाईजर की सेटंर से हरियाणा को सन् 1979.80 तथा 1980.81 मे अलग अलग से मिली। इस सवाल बी भाग मे उन्होने यह पूछा था कि उन एजेसिंयो के नाम बताये जिनके माध्यम से कन्जयूमर्ज को फर्टीलाइजर वितरित की जाती है। इसके साथ ही उन्होने यह भी पूछा कि किस रेट पर सेंटर से आती है और किस रेट पर बेची जाती है और इसमे कितना कमी ान दिया जाता है। स्पीकर साहब, आपने उस दिन ठीक आबजर्वे ान की थी। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि खाद बेचने का काम हैफेड को और एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरे ान को करना चाहिए । जवाब मे इन्होने यह कहा कि उनको जितना कोटा दिया गया उतना इन्होने लिफट नही किया । मंत्री महोदय ने यह कहा कि यह हमारी मजबूरी थी, कि उन्होने पूरा कोटा नही उठाया इसलिये प्राईवेट पार्टीज को देना पडा जिसके कारण से कुछ भांकाए उत्पत्र हुई । मै आपकी मार्फत सरकार से यह कहना चाहता हू कि यह बात समझ मे नही आई कि जो हैफेड है वह क्यो नही सारा माल उठा सकी जब यह कहा गया कि हरियाणा एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरे ान इतना माल उठाये तो उसमे क्यो नही उठाया, इसमे कुछ भांका उत्पत्र हो रही है। यूरिया और डी0ए0पी0 को बेचने के

लिये इनको मजबूरी मे प्राईवेट एजेन्सियों का सहारा लेना पड़ा है। स्पीकर साहब, हमे पता लगा हे कि उसमे काई भार्ते होती है। एक तो ग्राईडिंग की भार्त होती है कि साहब आपको यह ग्राइडिंग का प्लान्ट लगाना पडेगा। हैफेड वाले और एग्रो वाले इस कारण से संकोच कर रहे है कि कागजो मे हमे दिखाना पडेगा ।प्राईवेट कम्पनियों तो जहां चाहा स्टोर कर लेती है, उन्हे कोई पूछने वाला नही है।

श्रीमती सुशमा स्वराजः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर स्पकीर साहब यह सवाल डाक्टर मंगल सैन और डाक्टर सुखदेव सिंह दोनो की तरफ से हाफ एन आवर डिस्क ान के लिये एडमिट हुआ थां। लेकिन हम यह देख रहे है। कि चौधरी भजन लाल द्धारा डाक्टर सुखदेव सिंह को अपने पास बुला कर कुछ हिदायते दी जा रही है इनके पीछे पार्लियामैट्री अफेयर्ज मिनिस्टर भी बैठे है, वे भी उन्हे हिदायते दे रहे है कि वे सदन मे सच्चाई न खोले (व्यवधान एवम भाोर) Sir, I seek your protection. (Interruptins)

Mr. Speaker. Sushma Ji this is not a point of order. Please sit down.

स्थानीय भाासक मंत्री चौधरी खुर ाीद अहमदः स्पीकर साहब, और भी बाते होती है हजारों प्यार मुहब्बत की बाते होती है जो हम कर सकते है इस बारे मे तो सदन मे हम कोई बात नही कर रहे है। (व्यवधान एवम भाोर)

डा0 मंगल सिंहः सरकार ने यह तय किया था कि हैफेड ओर एग्रो इडस्ट्रीज वाले खाद उठायेगे और वह कन्जयूमर को देगे । इन दोनो इस्टीच्यू ान्ज को बनाने का मुदा यह था कि कजयूमर और सैलर के बीच मे मिडल मैन को एलीमिनेट किया जाये। और कन्जयूमर को सैलर की लूट से बचाया जाये। यह सरकार इतनी नाअहल है इतनी निकम्मी है यह इनती फेल हो गयी है कि इन्होने दोनो हाथ खडे कर दिये है। कि हम यह काम नही कर सकते । इन्होने अपने दोनो हाथ ऊपर उठा दिये है। बेहतर होगा यदि ये गद्दी छोड कर अपने घर चले जाये।

Mr. Speaker. Doctor Sahib, If I am mistaken, HAFED is no Corporaion and not a Government Depatment.

Dr. Mangal Sein: No, Sir it is Government Federation. स्पीकर साहब, वह कोई लाले की दुकान तो नही है कोई प्राईवेट कम्पनी तो नही है। जो सरकार के बस की बात नही है आखिर सरकार उसकी पालिसी कन्ट्रोल करती है। अगर इस आगस्ट हाउस मे हम उस कार्पोरे ान को भी डिस्कस नही कर सकते, उनकी पालिसी को भी डिस्कस नही कर सकते तो हर ओर क्या करेगे ? इन्होने यह कहा कि हमारी मजबूरी है । हमारी भी कि हमे सारी बाते कहनी पड रही है, चाहे वह इनको पसन्द आये न आये क्योकि हकीकत हमें ाा कडवी होती है

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, वैसे तो डाक्टर साहब ने बोलने की बडी रिहर्सल की हुई है । यह जो

बी0जे0पी0सी0 ने प्रस्ताव किया है कि गाधीयान सो ालिजम को मानेगे, यह उस पर चलने लग गये है।

डा मगल सैनः अभी तो आप नये नये यूथ काग्रेस के प्रधान बने है, अभी हमारे से दूरी ही तो अच्छा है। क्यों हमसे कुछ सुनना चाहते है? अभी हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने अम्बाला मे बडी तकलीफ उठा कर कश्ट उठाकर एक प्लान्ट का उद्घाटन किया है। इन्होने यह कहा है कि उससे हमे फर्टीलाईजर मिलेगा। उसके जरिये ये री–प्रोसैस करेगे, लेकिन वह री प्रासैंस नही करते, सारा माल वैसे ही बेच देते है एक मि ारल फर्टीलाईजर्ज एण्ड कैमिक्लज, नाम की सिरसा मे फर्म है । उनका एक आदमी खाद ले जाते हुए डबवाली थाने मे पकडा गया था। उसको पोलिटीकल प्रै ार से छुडावा दिया गया। मै यह नही कहता कि मंत्री महोदय ने प्रै ार डाल कर छुडवाया है लेकिन उनके अलावा भी दूसरे पोलिटीकल प्रै ार हो सकते है अगर इसे गलत साबित कर दे तो हम मान जायेगे कि हमारी जानकारी गलत है। कुछ तो ऐसे लोग है जिनका कन्सर्न राजस्थान मे भी है, पजाब मे भी है और यू0पी0 मे भी है यू0पी0 मे तो वे ब्लैक लिस्ट हो गये लेकिन यहा पर आकर काफी फायदा उठा गये। मै यह चाहूगां कि अगर सरकारी एजेसियां खाद उठा ले तो यह नौबत ही न आये। प्राईवेट पार्टीज को देनी ही ने पडे अबर हैंफेड वाले सारा माल उठा ले। एक बात और जानना चाहता हू कि क्या मंत्री महोदय इस बात को स्पश्ट करेगे कि कमी ान के बारे मे क्या पोजी ान

है ? संत कवर जी इस बारे मे यहा पर कुछ कह रहे थे ं मै कहना चाहता हू कि इसमे कमि ान स्पेसिफाई नही किया गया है जवाब के आखिर मे इन्होने लिखा है–

" No Specific commission is perescribed. Residual saving after meeting incidental/ handling expenses mentioned above, may be considered as commission which is shared mutually by the allottees and dealers depending upon the kind of fertilzer demand and supply position."

स्पीकर साहब, इस सब जेगलरी ने हमे चक्कर मे डाल दिया है। अगर कमि न डिफाइन नही किया है तो बात बडी साफ है कि जो लाखो रूपया लगा रहे है वे कोई सेवा समिति तो है नही। वे कमी ान कमाने के लिए ही पैसा इन्वैस्ट करते है। उन्होने कितना पैसा कमाया यह हमने अखबारो मे पढा था । सरकारी पार्टी की मीटिंग मे किसी विधायक ने करोडो की बात कही है। अगर तारा सिंह जी उस पर कोई रो ानी डाल दे तो अच्छी बात है। पहले तो इन्होने कट्राडिक्ट नही किया है, आज कर दे तो बडी अच्छी बात है ।स्पीकर साहब, मै कहना चाहता हू कि यह मसला अहम है हरियाणा एक कृशि प्रधान प्रदे ा होने के कारण यहां पर बहुत ज्यादा हमारे किसान भाई रहते है यहां पर 75 प्रति ात या 80 प्रति ात किसान रहते है लेकिन इस दलबदलू सरकार ने सता मे आते ही तीस रूपये यूरिया खाद के कट्टे पर बढा दिये।

चौधरी भजन लाल मुख्य मंत्रीः स्पीकर साहब, इनसे पूछा जाए कि ये दल बदल कर कहां गए ?

डा0 मंगल सैनः मै कही नही गया। मै असैम्बली के बीच मे खडा हुआ हू। आप भााति रखे। स्पीकर साहब, मै कहना चाहता हू कि कम्पनीज को रूपया कमवाने के पीछे क्या मं ाा है सदन मे यह बात साफ होनी चाहिए और क्या कारण है कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट जो फर्टिलाइजर देती है उसकी डिस्ट्रीब्यू ान करने के लिए प्राईवेट पार्टीज को दिया जाता है किन मजबूरियो मे दिया जाता है, हैफेड के थरू क्यो नही बाटा जाता है? बस मै इतना ही कहकर समाप्त करता हूं ।

स्वामी अग्निवेशः स्पीकर साहब, मै भी बोलना चाहता हू।

श्री अध्यक्षः इसमे जिन्होने नोटिस दिए है , वे बोल सकते है।

सरदार सुखदेव सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब कल भी और आज सुबह भी मै मत्री जी के डिस्कस कर चुका हू । मेरी तरफ से वही जवाब देगे।

श्रीमती सुशमा स्वराजः मैने तो बात कही थी, वही बात हुई ।

Mr. Speaker: Every member is free to say whatever he likes.

स्वामी अग्निवेशः मै तो थोडा ही समय लूगां ।

श्री अध्यक्षः इस बारे मे रूल बिल्कुल किलयर है अगर मै स्वामी जी को इजाजत दे दू तो फिर दूसरे को इजाजत देनी पडगी और फिर तीसरे को। इस बारे मे रूलिंग बिल्कुल क्लियर है।

कृशि मंत्री सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, इसमे तीन मोटे प्र न है। पहला प्र ान यह है कि कितनी क्वाटिटी सैन्ट्रल और स्टेट गवर्नमैंट एलोकेट करती है। दूसरा प्र ान यह है कि डिस्ट्रीब्यू ान के ऊपर मारजिन कितना है मुनाफा कितना है। तीसरा प्र ान यह है कि प्राईवेट पार्टीज, प्राईवेट डीलर्ज इसमे किस रूप मे आते है।

श्री अध्यक्षः चौथा हे कि हैफेड क्यो नही उठा रहा है ?

सरदारा तारा सिंहः यह तो प्राईवेट पार्टीज के बारे मे जब कहूगा तब आ जाएगा ।

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, हमे आज की कार्यवाही का जो एजेउा मिला है उसमे लिखा है कि खाद की मात्रा के सम्बन्ध मे ताराकिंत प्र न स0 1885 के उतर पर आधे घंटे की चर्चा । इसम कही नही लिखा कि डिस्क ान मे वही बोल सकते है जिन्होने नोटिस दिया है

श्री अध्यक्षः हाफ एन आवर डिस्क ान का आप रूल देख लीजिए । उसमे पता लग जाएगा।

सरदार तारा सिंहः अध्यक्ष महोदय अब मै पहले प्र न पर कुछ कहूगा कि सैन्टर से स्टेट गवर्नमैंट को कितना खाद ऐलोकेट हुआ । इस सम्बन्ध मे एक प्र न आया और जो जवाब दिया गया उसमे छ सात कम्पनियां है । जैसे गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एण्ड कैमीक्लज, चण्डीगढ फर्टिलाइजर एण्ड कैमीक्लज, ट्रावनकोर, मद्रास कैमिकल्ज एण्ड फर्टिलाइजर, मद्रास दिल्ली कलौथ मिल्ज, दिल्ली, इडियन एक्सप्लोसिव लिमिटिड, दिल्ली, भारत ऐलम इडस्टी, जयपूर कैपिटल फर्टिलाइजर कार्पोरे ान, चण्डीगढ ओर हिन्दुस्तान कौपर लिमिटिड, राजस्थान वगैरह का नाम आया। जिसमे थोडा सा भाक पैदा हुआ कि हरियाणा की फर्म्ज को खाद की एजेन्सियों क्यो नही दी गई ।बाहर की फर्म्ज को खाद की एजेन्सियां क्यो दी गई? स्पीकर साहब, असल बात यह है कि इतनी बडी बडी कम्पनियां है जिनकी लागत चार सौ करोड रूपया पाच सौ करोड रूपया और एक हजार करोड़ रूपया तक है और यह कोई मद्रास की है और कोई दिल्ली की हैं। खाद की डिस्ट्रीब्यू ान के बारे मे सैन्ट्रल गवर्नमैंट की पालिसी यह है कि किसी प्रान्त मे अगर कोे खाद की फैक्टरी है तो उसकीत खाद केवल उसी प्रान्त मे न दी जाए। जैसे पानीपत मे एन0एफ0एल0 फैक्टरी चल रही है, ऐसा नही है कि उसकी खाद हरियाणा मे ही सप्लाई होती है बल्कि पानीपत की खाद दूसरे

प्रान्तों मे भी जाती है । नंगल की फैक्टरी की जो खाद है वह मद्रास को भी जाती है भटिडा मे जो फैक्टरी है उसकी खाद फैल हो जाए या कोइ ऐसा कारण हो जाता है कि उत्पादन बन्द हो जाए तो कोई प्रान्त खाद की डिस्ट्रीब्यू ान से न रह जाए। स्पीकर साहब हमारी पानीपत की खद मद्रास मे जाती है, गुजरात मे जाती है। यह बात लगती तो कुछ अजीब सी है कि जो खाद यहा पैदा होती है, वह यही पर खर्च क्यो नही होती लेकिन कन्टरी के इट्रेस्ट मे ऐसा किया जाता है।

स्पीकर साहब, अब मै खाद की डिस्ट्रीब्यू ान के बारे मे कहना चाहता हू दो तरह की खाद होती है । एक इडीजीनस खाद ओर दूसरी पूल यूरिया । साल मे दो जोनल मीर्टिग्ज होती है। एक खरीफ से पहले और दसूरी रबी से पहले। जो जोनल मीटिग्ज होती है उनमे सैन्ट्रल गवर्नमैंट के सैकटरीज होते है। वे देखते है कि इस प्रान्त मे कितनी खाद की जरूरत है और इस प्रान्त ने पिछले साल कितना खाद इस्तेमाल किया है ।इस प्रान्त मे पानी की फैसिलीटीज कितनी है और यह प्रान्त कितना खाद इस्तेमाल कर सकता है। जो चार्ट दिया हुआ है उसमे दिया है कुल कितना यूरिया ऐलोकेट हुआ। इस चार्ट मे दिया है कि 37000 टन यूरिया ऐलोकेट हुआ और उसको मिल गया 74 हजार टन । इस बात मे मेरे साथियों के दिमाग मे थोडा कफफयूजन होगा।स्पीकर साहब, असल बात यह है कि जिस वक्त जोनल मीटिंग मे फैसला होता है तो उस वक्त बता देते है कि हम फला

फैक्टरी से जैसे हरियाणा से गुजरात वालों को इतनी खाद दे देगे लेकिन बाद मे उनको और स्टोक मिल जाता है तो वे वहां से उठा लेते है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐलोकें ान के बाद भी सैन्टल गवर्नमैंट से और से ऐलोके ान हो जाती है इससे वह रिकार्ड और बढ जाता है । इसी तरह से कई दफा जब इडीजिनस खाद हमारी पूरी नही होती तो हम फिर दोबारा और ऐलोके ान के लिए प्रैस करते है। स्पीकर साहब, यह बाता तो हुई डिस्ट्रीब्यू ान के बारे मे। अब मै इसका जवाब दूंगा जो यहां बार बार कहा जा रहा है कि प्राईवेट आदमी को डिस्ट्रीब्यू ान के लिए खाद क्यो दी जाती है डा साहब ने अभी कहा है कि हैफेड के थ्रू या एग्रो के थ्रू डिस्ट्रीब्यू ान क्यो नही की जाती है। स्पीकर साहब, मै बताना चाहता हू कि 1976.1977 मे कोआप्रेटिव सैक्टर मे 576 डीलर बनाए और दूसरे डीलर्ज की सख्या 615 थी । इसी तरह से 1977.78 मे हमने कोआप्रेटिव सैक्टर 600 डीलर्ज बनाये ओर दूसरे 615, 1978–79 मे कोआप्रेटिव सैक्टर 713 और दूसरे 1116 बनाये, 1979–80 मे 946 कोआप्रेटिव सैक्टर मे और 1178 प्राईवेट सैक्टर मे । स्पीकर साहब, ये भाायद कहते है कि हम प्राईवेट वालों को स्पोर्ट करते है। मै आपको बताना चाहता हू कि 1978–79 मे पानीपत की एन0एफ0एल0 चालू हो गयी थी , वहा पर बहुत डीलर्ज का एक नैट बनाया गया। स्पीकर साहब, मैने पहले बताया कि हमारी खाद जो पानीपत मे होती है, वह बाहर गुजरात मद्रास व कोचीन की तरफ जाती है । (व्यवधान एवम भाोर)

डा0 डा. मंगल सैनः सरदार जी, करनाल और सिरसा के बारे मे बात दीजिये।

सरदार तारा सिंहः डाक्टर साहब, आप तसल्ली रखिये। मै आपका बताता हू कि अगर हमारी खाद बाहर जाती है तो बाहर की कई फर्मे ऐसी है जिन्होने कि हमारे हरियाणा मे भी अपने डिलर्ज बना रखे है हम हैफेड और एग्रो वालो को 50 प्रति त खाद देते है और 50 प्रति ात प्राईवेट वालो को देते है ।स्पीकर साहब मै बताना चाहता हू कि किसी वक्त कोई फर्म फेल हो जाती है फर्ज करो हैफेड वाले स्ट्राइक कर देते है तो अगर खाद एक पार्टी के पास ही होगी तो हमारे किसान मारे जायेगे। अगर हमने दूसरे डीलर्ज भी बनाये होगे तेा हम किसानो को उस वक्त मे दूसरी एजेसियों से भी खाद दिलवा सकेगे और किसानों का काम भी चलता रहेगा। नही तो किसानो को ऐसे वक्त मे काफी मुसीबतों का सामना करना पडेगा मई जून के महीनों मे कोआप्रेटिव सैक्टर वाले रिकवरी करने मे लग जाते है। जितने उनके अफसर है जितने मिनी बैन्कस के मैनेजर है वे सभी और दूसरे आरज और डी आरज सभी रिकवरी के काम मे लग जाते है। आम तौर पर यह देखा गया है कि किसानों को जब खाद की जरूरत होती है तो वे लोग दफतरो मे नही मिलते और किसान बेचारे परे ाान होते रहते है सिरसा के बारे मे तो इतना ही कहता हू कि वहा पर खाद पहली बार मिली है । करनाल की बात

डाक्टर साहब कहते है उनको मै बताना चाहता हू ..... (व्यवधान एवम भाोर)

डा. मंगल सैनः .....

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, मै फुल रिसपान्सिबिलिटी से कह रहा हू.....(व्यवधान एवम भाोर)

श्री अध्यक्षः कोई भी प्राईवेट बात रिकार्ड पर नही आनी चाहिये।

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, क्योकि डाक्टर साहब ने मुझे रिकवैस्ट की थी

सरदार सुखदेवः स्पीकर साहब.....

डा0 मंगल सैनः .....

सिचाई तथा बिजल उपमत्री श्री देवेन्द्र भार्माः स्पीकर साहब, मैने रिकवैस्ट की थी कि मेरा मामला प्रिवलिज कमेटी को सौप दिया जाए।

श्री अध्यक्षः इससे उस मामले का क्या सम्बन्ध है ?

श्री देवेन्द्र भार्माः स्पीकर साहब, अब हाउस का समय होने जा रहा है । अगर आपने मेरा मामला प्रिवलिज कमेटी को नही सौपा तो अब सौप दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी ।

श्री अध्यक्षः मै उसे अभी एग्जमिन कर रहा हूं

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, इसके बाद मै डिस्ट्रीब्यू ान मार्जन के बारे मे बताना चाहता हूं हम पर बैग कोआप्रेटिव सैक्टर मे यूरिया पर 5.75 रूपये ओर डी0ए0पी0 पर 7. 00 रूपय देते है 1980–81 मे प्राईवेट सैक्टर मे हमने यूरिया पर 5.25 रूपये और डी0ए0पी0 यूनिया पर 6.25रूपये पर बैग डिस्ट्रीब्यू ान मार्जन दिया है इसके साथ साथ यहा पर यह कहा गया कि मैने अखबारों की खबरो को कट्राडिक्ट नही किया। क्योकि हाफ एन आवर डिस्क ान के लिए अलाउ कर दिया गया था इसलिए मै कट्राडिक्ट नही कर सका। मैने कहा कि मै इस बारे मे हाउस मे ही बताऊगा । मै आपको बताता हू कि हमने 225 लाख टन यूरिया हैफेड वालों को दिय, जिसमे उनको ग्रास आमदनी अढाई करोड रूपये की थी और नैट प्रोफिट 11 लाख रूपया था। यह बैलेन्स भीट अफसरो के पास है चैयरमैन साहब को इस बात का पता है। आप सोचिए कि 42 करोड रूपये की इन्वैस्टमैंट के लिए 11 लाख रूपये का प्रौफिट है हमारा 80 परसैंट वितरण हैफड और एग्रो वालो के पास है और 9 परसैंट प्राईवेट पार्टियों के पास है। आप ही अन्दाजा लगा सकते है कि जिन लोगो ने केवल 15–20 लाख रूपये का खाद बेचा हो, वे एक करोड रूपया सरदार तारा सिह को कैसे लाकर देगे? हैफड वालो को भी अपनी मजबूरी है कि वे इतना माल नही उठा सकते ओर उन्होने यह लिख कर दिया हुआ है कि 9 रूपये बैग के मार्जन के

बिना मुनाफा नही हो सकता । स्पकीर साहब, मै इससे आगे यह बताना चाहता हूं कि जून मे खाद की कीमत बढ गई ।अगर इन्वैस्टमैंट और ज्यादा होगी तो मुनाफा भी कम होगा और फिर ये जो कोआप्रेटिव सैक्टर है ये खाद नही उठा सकेगे। इधर हमारी यह डिफीक्लटीज है कि अगर हम निर्धारित कोटे के मुताबिक खाद नही उठाते तो अगले साल हमे पूरा कोटा नही मिलता । हमारा कोटा काट देगे। इसलिये हर हालात मे हमे अपना पूरा कोटा वहा से उठाना पडता है। अगर पैसा बचत हो तो हैफेड और एग्रो वाले खाद को उठा ले, पर नही उठाते स्पीकर साहब, इसके साथ साथ यंहा पर पजाब की बात भी कही गयी। पजाब की और हमारी पोजी ान अलग अलग है । पजांब मे 90 परसैट से ऊपर पानी है पर हमारे यहां पर 52 परसैंट है इसलिए उनकी खाद की लागत हमारे से ज्यादा है। इसलिये हम उनके साथ कंपीट नही कर सकते। बस मै इतना ही कहता हुआ आपका धन्यवाद करता हूं ।

15.30 बजे

Mr. Speaker: The House stands adjourned sine-die

(The Sabha then adjourned sine die)